चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 19 अप्रैल–25 अप्रैल 2010

देश की आधी मुठभेड़ फ़र्ज़ी हैं

पेज 3

पर्यावरण सुरक्षा और भारत

पेज 5

मनरेगा, जो मन में आए करो!

पेज 7

प्रेम-मैत्री, अहिंसा और भाईचारे का संदेश देता है इस्लाम

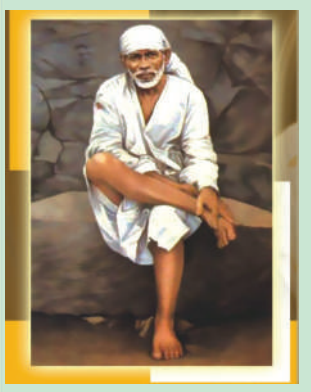

पेज 12

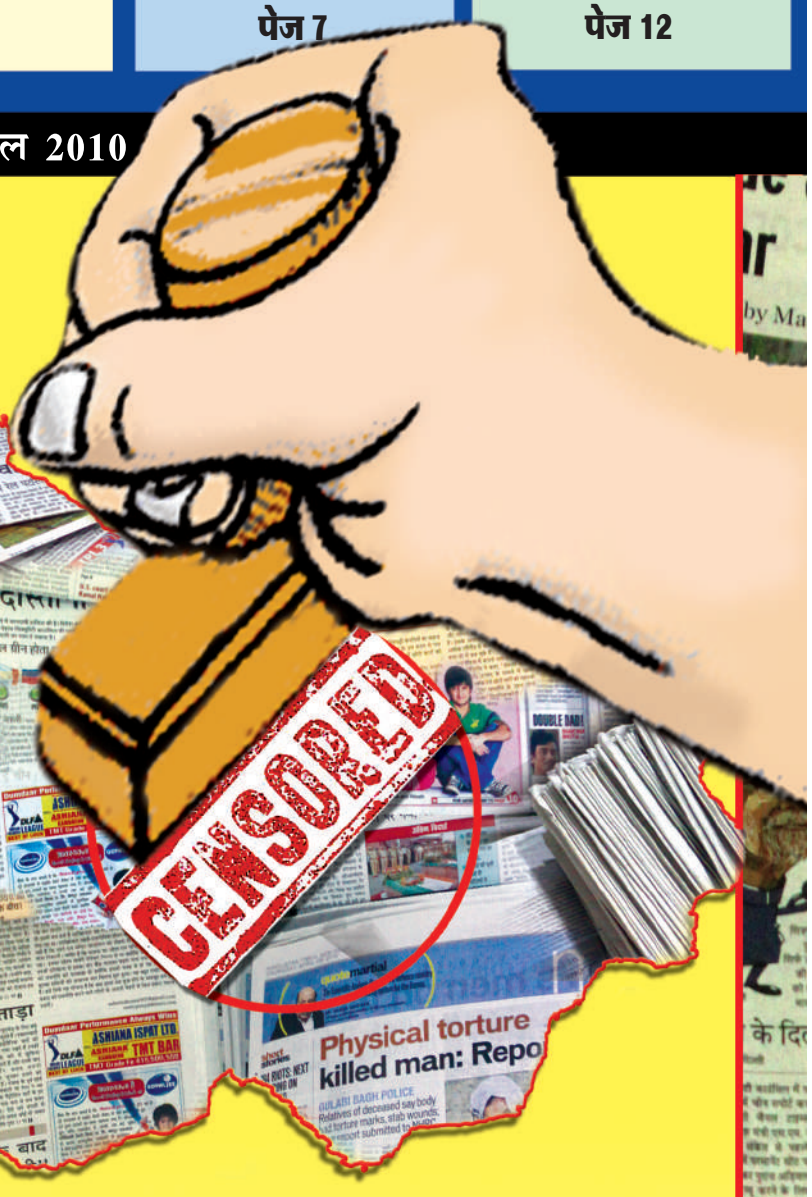

मेरे ख़िलाफ़ लिखना मना है

मनीष कुमार

सरकार की योजनाओं और कामों को प्रचारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग होता है. हर सरकार यही चाहती है कि उसके अच्छे कामों का प्रचार हो और सरकार की कमज़ोरियां बाहर न आएं. सरकार की विफलताओं और कमज़ोरियों को जनता के सामने लाना मीडिया का काम है. लेकिन बिहार में स्थिति अलग है. बिहार में अघोषित सेंसरशिप लागू है. पटना के अख़बारों ने नीतीश सरकार की ग़लतियों और बुराइयों को छापना बंद कर दिया है. सरकार के ख़िलाफ़ ख़बर छापने पर अख़बार मालिकों को माफी मांगनी पड़ती है और ख़बर लिखने वाले पत्रकार को सजा मिलती है. बिहार के मीडिया ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं और वह जनसंपर्क विभाग की तरह काम कर रहा है.

पटना के एक शख्स को जनता की समस्याओं को लेकर बटाईदारी क़ानून के बारे में एक ख़बर छपवानी थी. यह ख़बर नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ थी. वह शख्स पटना के सारे अख़बारों के दफ़्तरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर अख़बार ने इस ख़बर को छापने से मना कर दिया. इस शख्स को अख़बार के दफ़्तरों में बताया गया कि जो ख़बर आप छपवाना चाहते हैं, वह नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम नहीं छाप सकते. उस शख्स ने अपनी ख़बर एक इश्तेहार के रूप में छपवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी अख़बार ने उस ख़बर को छापने की हिम्मत नहीं की. बिहार के अख़बारों पर नज़र डालें तो एक अजीबोग़रीब पैटर्न दिखता है. पहले पेज पर सरकार के अच्छे कामों का बढ़ा–चढ़ा ब्यौरा मिलता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अच्छी तस्वीर होती है और बाक़ी जगह पर हत्या, बलात्कार और लूट की ख़बरें होती हैं. जितना विकास हुआ नहीं, अख़बार उससे कहीं ज़्यादा ढोल पीटते हैं. नीतीश कुमार के विरोधियों, दूसरे नेताओं और उनके विचारों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है. बिहार के कुछ पत्रकारों से बात करने पर पता चला कि वे राज्य की समस्याओं के बारे में लिखना चाहते हैं, लेकिन उनकी कलम को रोक दिया जाता है. जिस अख़बार में नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ ख़बर छप जाती है, उस अख़बार को सरकारी विज्ञापन मिलना बंद हो जाता है. यह तब तक बंद रहता है, जब तक अख़बार के मालिक बिहार सरकार के मुखिया के पास जाकर गिड़गिड़ाते नहीं हैं. बिहार के पत्रकारों ने बताया कि कुछ दिन पहले हिंदी के एक बड़े अख़बार ने बिहार सरकार के ख़िलाफ़ एक ख़बर छापी. ख़बर की हेडिंग थी– मुख्यमंत्री जी, शराब बड़ी जालिम होती है. इस स्टोरी में एक्साइज डिपार्टमेंट के एक घोटाले की कहानी थी. यह ख़बर छपते ही इस अख़बार को मिलने वाले सारे सरकारी विज्ञापन बंद हो गए. मालिकों ने घुटने टेक दिए. संपादक–मालिकों को माफी मांगनी पड़ी और रिपोर्टर को पटना से ट्रांसफर करके झारखंड के जंगलों में नक्सलियों की ख़बर लेने भेज दिया गया. फ़िलहाल इस बीच मालिकों में से एक ने नीतीश कुमार के विरोधियों से हाथ मिला लिया. उन्होंने नीतीश के विरोधियों को बताया कि सरकार ज़्यादती कर रही है. बिहार में सरकार के ख़िलाफ़ और विपक्ष की ख़बरों को प्रमुखता देने का अंजाम क्या होता है, आदि बातें आम हैं.

यही वजह है, बिहार के अख़बारों और समाचार चैनलों की रिपोर्टों से बस यही लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है. ज़्यादातर अख़बार और न्यूज़ चैनल चारणों की तरह नीतीश सरकार की शान में क़सीदे ऐसे पढ़ते और लिखते हैं कि जैसे आप बिहार सरकार का चैनल देख रहे हों या फिर बिहार सरकार के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का कोई पर्चा पढ़ रहे हों.

इस साल चुनाव होने वाले हैं. नीतीश सरकार अपने पांच साल पूरे करने वाली है, लेकिन इस कार्यकाल के दौरान क्या–क्या कमियां रहीं, यह छापने या दिखाने की हिम्मत कोई भी अख़बार या न्यूज़ चैनल नहीं कर सका. कुछ लोग यह कह सकते हैं कि बिहार सरकार मीडिया को मैनेज कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि मीडिया ख़ुद बिकने के लिए बाज़ार में खड़ा है. सरकार को उसे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह ख़ुद मैनेज होने के लिए तैयार बैठा है. अब जब मीडिया ही सरकार के पब्लिक रिलेशन का काम करने लग जाए तो ऐसे में अख़बारों और न्यूज़ चैनलों से क्या उम्मीद की जाए.

नीतीश कुमार की सरकार पहले से बेहतर तरीक़े से बिहार में काम कर रही है. इसमें कोई शक़ नहीं है कि विकास के काम हो रहे हैं. यह भी सच है कि इस साल होने वाले चुनाव की नज़र से देखा जाए तो फ़िलहाल नीतीश बढ़त की स्थिति में हैं. वह अपने विरोधियों से आगे चल रहे हैं, लेकिन यह वॉक ओवर वाला मामला नहीं है. थोड़ी सी स्थिति बदलने से नीतीश कुमार के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है. हैरानी की बात यह है कि बिहार के अख़बार जिस तरह से राजनीतिक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि मीडिया नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही विजयी बनाने में लगी है. ऐसा लगता है कि बिहार के अख़बार नीतीश सरकार के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में तब्दील हो चुके हैं.

बिहार में क्या ज़मीन के बंटवारे की स्थिति सुधर गई है, क्या हर शहर और ग्रामीण इलाक़ों में पीने का साफ पानी मिलने लगा है, क्या बिहार में बेरोज़गारी पर जीत हासिल कर ली गई है, क्या बिहार की स्वास्थ्य–चिकित्सा व्यवस्था ठीक हो गई है, क्या महादलितों की समस्याओं का हल हो चुका है, क्या बाढ़ग्रस्त इलाक़ों में राहत का काम सही तरीक़े से हो चुका है, क्या बिहार में नरेगा जैसी योजनाओं में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्या बिहार में सरकारी दफ़्तरों में घूसखोरी ख़त्म हो गई है, क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है और क्या बिहार में क़ानून व्यवस्था की हालत अच्छी हो गई है? किसी पत्रकार ने यह हिम्मत नहीं जुटाई कि कोसी के सच को सामने लाया जाए. बिहार के कई पत्रकार कहते हैं कि सरकार के ख़िलाफ़ ख़बर लिखने का मतलब नौकरी से हाथ धोना है. लेकिन, विज्ञापन का लड्डू दिखाकर बिहार सरकार जो खेल कर रही है, वह नया नहीं है. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2004 के चुनावों में एनडीए की सरकार ने भी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बिहार के अख़बारों पर नज़र डालें तो एक अजीबोग़रीब पैटर्न दिखता है. पहले पेज पर सरकार के अच्छे कामों का बढ़ा-चढ़ा ब्यौरा मिलता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अच्छी तस्वीर होती है और बाक़ी जगह पर हत्या, बलात्कार और लूट की ख़बरें होती हैं. जितना विकास हुआ नहीं, अख़बार उससे कहीं ज़्यादा ढोल पीटते हैं.

भारत का राजनैतिक इतिहास

मनमोहन सिंह से चंद्रशेखर आहत थे

दिग्विजय सिंह

मनमोहन सिंह से चंद्रशेखर बहुत आहत थे. इसका एक बड़ा कारण यह था, क्योंकि चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में मनमोहन सिंह उनके वित्त सलाहकार थे. पिछले 40 वर्षों में मनमोहन सिंह का भारतीय अर्थनीति के बारे में एक जैसा विचार था. संभवत: यही देखकर चंद्रशेखर जी ने उन्हें अपने वित्तीय सलाहकार के रूप में चुना होगा. वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे. लेकिन जैसे ही सरकार बदली और नरसिंहराव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया, उन्होंने पूरी पलटी मार दी. चंद्रशेखर जी भी चकित थे कि जिसने अपने जीवन के साठ साल एक तरह से जिया हो, एक ख़ास सिद्धांत को लेकर चलता रहा हो, वह अचानक कैसे बदल गया?

एक वाकया याद आया. उस दिन लोकसभा में बजट पर भाषण हो रहा था और चंद्रशेखर जी सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना कर रहे थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने खड़े होकर कहा, चंद्रशेखर जी, हमने तो आपके ही आदमी को वित्त मंत्री बनाया, यह सोचकर कि वह आपके इकोनॉमिक एडवाइज़र थे. वह वही कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे. इस पर चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया, भाई मनमोहन सिंह मेरे आर्थिक सलाहकार थे, वित्त मंत्री नहीं थे. जिस चाकू से बैगन काटा जाता हो, उससे आप दिल की सर्जरी करने लगें तो इसमें चाकू का दोष थोड़े ही है. मैं तो इनसे सलाह ले रहा था, फ़ैसला करने का काम वित्त मंत्री का होता है. आपने तो पूरी नीति ही उलट कर रख दी. यह बात कई बार वह व्यथित होकर कहते थे. कभीकभार मनमोहन सिंह भी उनके प्रहार से बौखला जाते थे.

दिग्विजय सिंह

चंद्रशेखर जी को कई बार ऐसा लगता था कि मनमोहन सिंह ने अपने सिद्धांत से डिसऑनेस्टी की है. देश से डिसऑनेस्टी की बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मनमोहन सिंह राष्ट्रभक्त आदमी हैं. पर साठ वर्षों तक उन्होंने जिस इकोनॉमिक पॉलिसी को माना, उसे एकदम से रिवर्स गियर में ले आया गया. यह कोई छोटी बात नहीं थी. इससे देश को कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुक़सान, यह बहस का मुद्दा हो सकता है. कुछ लोग कहेंगे कि देश का जो कुछ भी नफ़ा-नुक़सान हो रहा है, उसके पीछे उन्हीं के एक आर्थिक सलाहकार, जो योजना आयोग के सदस्य भी थे, के कहने या राय देने पर हुआ है. पर हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि उसी सरकार ने जो अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनाई थी, उसने सरकारी नीति की बखिया उधेड़ कर रख दी. कमेटी ने कहा कि देश के 74 करोड़ लोग केवल 20 रुपये में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं. इसके उलट देश में दौलत की चकाचौंध भी है, जो सिमट कर केवल 20 फ़ीसदी लोगों के हाथ में रह गई है. 80 फ़ीसदी लोगों तक यह दौलत नहीं पहुंचती.

दिल्ली शहर में तो चकाचौंध है, कॉमनवेल्थ ने दिल्ली बदल दी है, पर हमें यह समझना चाहिए कि भारत के अंदर कई भारत बनते जा रहे हैं. अगर यह पॉलिसी इतनी सफल होती तो नरेगा और बीपीएल की सूची नहीं बनानी पड़ती. अब बिहार को ही लें. वहां डेढ़ करोड़ लोग ग़रीबी रेखा से नीचे हैं. औसतन एक परिवार में पांच लोग होते हैं. इसका मतलब है कि अकेले बिहार में 7.5 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. चंद्रशेखर जी इससे बहुत चिंतित रहते थे.

दिग्विजय सिंह चंद्रशेखर जी के सबसे करीबी लोगों में रहे हैं. यह पूरा इंटरव्यू आप www.chauthiduniya.tv पर देख सकते हैं. इतिहास की ऐसी ही कई घटनाओं का पहली बार ख़ुलासा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा.

संपादक

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार जल्द ही मितव्ययिता से जुड़े कुछ सरकारी फरमानों को वापस ले लेगी.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

फ़िज़ूलख़र्ची को ग्रीन सिग्नल

केंद्र सरकार के बदले रवैये से लगता है कि सरकारी बाबुओं और सुविधाभोगी मंत्रियों के दिन अब फिर से बहुरने वाले हैं. मितव्ययिता के भूत ने मंत्रियों और सरकारी बाबुओं को आरामतलबी से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया था. फाइव स्टार होटलों और एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मंदी से उबरने के बाद अर्थव्यवस्था में जान लौटी तो केंद्र अब इन पाबंदियों को हटाने पर विचार कर रहा है. कहा तो यह भी जा रहा है कि इन बदलावों को लेकर कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर ने मंत्रियों को पहले ही अनौपचारिक रूप से सूचित कर दिया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार जल्द ही मितव्ययिता से जुड़े कुछ सरकारी फरमानों को वापस ले लेगी. इससे मंत्रियों और सरकारी बाबुओं को अब इकोनॉमी क्लास (जिसे ट्विटर में कैटल क्लास कहा गया था) में यात्रा नहीं करनी पड़ेगी. हालांकि बिजनेस क्लास में यात्रा पर लगी पाबंदी का ज़्यादा असर पहले भी नहीं था, क्योंकि मंत्रियों द्वारा महंगे एयरलाइनों में सवारी का दौर बदस्तूर जारी था. हां, इससे नौकरशाहों को ज़रूर ख़ुशी होगी.

हालांकि संभावना यह है कि कुछ पाबंदियां अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेंगी. सूत्रों का कहना है कि बार–बार विदेश भ्रमण और फाइव स्टार सुविधाओं को भोगने की आज़ादी के लिए मंत्रियों और सरकारी बाबुओं को अभी और इंतज़ार करना होगा. वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान में मितव्ययिता से जुड़ा जो संशोधन किया जाने वाला है, वह आरामतलब और हाई प्रोफाइल मंत्रियों के कुनबे के दबाव का ही नतीजा है. ऐसे में सरकारी बाबुओं को भी ये उम्मीद जागी है कि थोड़े इंतज़ार से उन्हें फिर से पहले वाली सुविधाओं के उपभोग की आज़ादी मिल जाएगी.

सीबीआई आंकड़े में पीछे

भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों पर आरोप सिद्ध कराने के मामले में सीबीआई इस साल पीछे रह गई है. इस साल सीबीआई भ्रष्टाचार के 64 फ़ीसदी मामलों में ही आरोपों को प्रामाणित करने में कामयाब हो पाई है. हालांकि, सीबीआई की सफलता की यह दर पिछले कुछ साल से यूं ही घटती जा रही है. 2006 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के 73 फ़ीसदी मामलों में सफलता प्राप्त की थी, जो 2009 में घटकर 58 फ़ीसदी रह गई. इस दौरान निदेशकों के आने–जाने का दौर जारी है, लेकिन इस शीर्ष संस्था के कामकाज में कोई ख़ास अंतर नज़र नहीं आ रहा है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब यह चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार के ज़्यादा से ज़्यादा मामले पकड़ कर ही देश में विकास की गति को तेज़ किया जा सकता है, तो सीबीआई ने अब अपने लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित कर लिया है. संस्था ने इस साल 2010 में भ्रष्टाचार के 70 प्रतिशत मामलों में आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप सिद्ध करने के लिए कमर कस ली है. हालांकि, केवल लक्ष्य निर्धारित कर लेने भर से कितना फ़ायदा होगा, यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि सूत्रों का यह भी कहना है कि सीबीआई योग्य अधिकारियों की कमी की समस्या से जूझ रही है. फ़िलहाल विभाग में 762 पद खाली हैं जबकि भ्रष्टाचार के 988 मामले लंबित हैं. इनमें से 438 ऐसे मामले हैं जिनमें पिछले दस सालों में चार्जशीट भी दायर नहीं की गई है क्योंकि ऐसा करने के लिए विभाग के पास अधिकारियों की भारी कमी है.

इन आकड़ों से सकते में आई सरकार ने अब जाकर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे विशेषज्ञ वकीलों को अनुबंधित करने का फ़ैसला किया है. सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में एक समिति ऐसे विशेषज्ञ वकीलों की पहचान कर रही है जो भ्रष्टाचार के मामलों में तीन से लेकर सात साल तक का अनुभव रखते हों. इन वकीलों को चालीस से साठ हज़ार तक वेतन दिया जाएगा और वे भ्रष्टाचार के मामलों को सुलझाने में तीन साल तक सीबीआई की मदद करेंगे. क्या इसे सीबीआई के अति उत्साह का प्रतीक माना जाए? चाहे जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीबीआई की समस्याएं इतनी आसानी से ख़त्म होती नहीं दिखाई देतीं.

मेरे ख़िलाफ़ लिखना मना है

पृष्ठ एक का शेष

शाइनिंग इंडिया के विज्ञापन के नाम पर मीडिया को करोड़ों रुपये दिए थे. उस वक़्त भी अख़बारों और टीवी चैनलों ने चुनाव से पहले एनडीए की सरकार को विजयी घोषित कर दिया था. उस चुनाव का परिणाम क्या निकला, यह भी हम लोगों के सामने है.

सरकार के जनसंपर्क विभाग की तरह काम करना बिहार में पत्रकारिता का नया चेहरा है. क्या कारण है कि हड़ताल से बिहार में पूरा तंत्र चरमरा जाता है और अख़बारों में इस ख़बर को अंदर के पन्नों में छोटी सी जगह मिल पाती है. क्यों सरकार के विरोधियों को विलेन के रूप में पेश किया जाता है. नीतीश सरकार ने सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल कर अख़बार मालिकों को लालच दिया और अख़बारों को पालतू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बिहार के कुछ वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि अख़बारों को भेजे गए विपक्षी दलों के बयान छपने से पहले मुख्यमंत्री की टेबल पर पहुंच जाते हैं. यहां तक कि दिल्ली से चलाई गई ख़बरों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश आते हैं कि सरकार की नकारात्मक छवि वाली ख़बरें न छापी जाएं. बिहार में यह अघोषित सेंसरशिप बहुत ही सुनियोजित ढंग से लागू की गई है और अख़बारों को अपने हित में इस्तेमाल कर उन्हें राज्य सरकार का एजेंट बना डाला गया है. मंदी के दौर में नीतीश सरकार ने मीडिया की कमज़ोरी को भलीभांति समझा और सरकारी विज्ञापन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया. ऐसे–ऐसे हथकंडे अपनाए गए, जिन्हें हम तानाशाही से जोड़ कर देख सकते हैं. लालू–राबड़ी की सरकार के दौरान बिहार में जंगलराज पर हमेशा कुछ न कुछ ख़बरें छपा करती थीं, लेकिन वर्तमान दौर में ख़बर छापने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सरकार के मुखिया का राजनीतिक क़द कम न हो जाए.

दरअसल, नीतीश सरकार ने मीडिया की कमज़ोरी को पहचान लिया है. और, यह कमज़ोरी है विज्ञापन की. नीतीश सरकार ने विज्ञापनों के सहारे मीडिया को नियंत्रित रखने का काम बखूबी किया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से साल 2005 से 2010 के बीच (नीतीश कुमार के कार्यकाल के चार सालों में) लगभग 64.48 करोड़ रुपये ख़र्च कर दिए गए. जबकि लालू–राबड़ी सरकार के कार्यकाल के अंतिम 6 सालों में महज़ 23.90 करोड़ रुपये ही ख़र्च हुए थे. मिली सूचना के मुताबिक़, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने साल 2009–10 में (28 फरवरी 2010 तक) 19,66,11,694 (लगभग 20 करोड़) रुपये के विज्ञापन जारी किए हैं, जिनमें से 18,28,22,183 (लगभग 18 करोड़ से ज्यादा) रुपये के विज्ञापन प्रिंट मीडिया और 1,37,89,511 (लगभग डेढ़ करोड़) रुपये के विज्ञापन इलेक्ट्रानिक मीडिया को दिए गए. इतना ही नहीं, नीतीश सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर एक ही दिन में 1,15,44,045 (लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा) रुपये का विज्ञापन एक साथ 24 समाचारपत्रों को जारी किया गया. इसमें भी सबसे ज़्यादा विज्ञापन एक ख़ास समूह के अख़बार को दिया गया. कुछ ख़ास अख़बारों को तो अकेले 50 लाख रुपये से ज़्यादा का विज्ञापन दिया गया है.

कुछ दिन पहले पटना में बिहार में पत्रकारिता विषय पर एक सेमिनार हुआ. इस सेमिनार का आयोजन हाल में ही लांच हुए बिहार के टीवी चैनल मौर्य टीवी ने किया था. इसमें बिहार के सारे बड़े संपादक, ब्यूरो चीफ और संवाददाता मौजूद थे. इस सेमिनार में कुछ नेता भी थे. सेमिनार में अजीबोग़रीब नज़ारा देखने को मिला. नेता पत्रकारों को खरी–खोटी सुना रहे थे और पत्रकार चुपचाप सुन रहे थे. सेमिनार से जो बात सामने आई, वह यह है कि बिहार का मीडिया सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान हो चुका है. सरकार जिस ख़बर को दबाना चाहती है, वह दब जाती है और जिसे लोगों तक पहुंचाना चाहती है, उसे बिना किसी विश्लेषण या टिप्पणी के छाप दिया जाता है. नीतीश कुमार अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं. वह तो यही चाहेंगे कि वह जो काम करते हैं, उसे अख़बार में हज़ार गुना ज़्यादा दिखाया जाए. वह तो यही चाहेंगे कि उनके हर काम का प्रचार हो और जो बुरा है, उसे जनता की नज़रों से बचाया जाए. प्रजातंत्र में पत्रकारों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन पर यह दायित्व है कि वे सरकार के सभी क्रियाकलापों पर नज़र रखें और उसमें जो ग़लत है, उसे जनता के सामने लाएं. पत्रकारों का यह काम है कि किसी डॉक्टर की तरह शरीर की सुंदरता के अंदर से बीमारी को निकाल बाहर करना. अगर अख़बार चारण का काम करने लगेंगे तो जनता के सवालों को सरकार तक कौन पहुंचाएगा. अगर बिहार के पत्रकार यह कहें कि उनके हाथ बंधे हैं, अगर सरकार के ख़िलाफ़ ख़बर लिखने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? क्या यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि बिहार में अघोषित सेंसरशिप है.

manish@chauthiduniya.com

इसलिए हम चुप रहते हैं...

नीतीश सरकार ने चार साल पूरा होने के अवसर पर एक ही दिन में इन अख़बारों को 1 करोड़ 15 लाख 44 हज़ार रुपये के विज्ञापन दिए

अख़बार	भुगतान की गई राशि (रुपये में)
हिंदुस्तान	37,09,162
दैनिक जागरण	27,89,835
आज	3,66,546
प्रभात खबर	3,89,622
राष्ट्रीय सहारा	1,52,132
टाइम्स ऑफ इंडिया	1,80,850
हिंदुस्तान टाइम्स	15,80,640
इंडियन एक्सप्रेस	1,15,784
दैनिक भास्कर	1,30,486
सन्मार्ग	63,916
इकोनॉमिक टाइम्स	2,17,845
पंजाब केसरी	1,91,543
बिजनेस स्टैंडर्ड (दिल्ली)	50,643
बिजनेस स्टैंडर्ड (मुंबई)	25,321
प्रात: कमल (मुजफ्फरपुर)	28,595
कौमी तंजीम	2,70,162
फारुकी तंजीम (पटना)	2,70,162
पिंदार (पटना)	2,51,580
संगम (पटना)	2,70,162
इंकलाब–ए–जदीद (पटना)	38,595
प्यारी उर्दू (पटना)	71,880
राजस्थान पत्रिका (जयपुर)	1,86,642
अमर उजाला (दिल्ली)	88,829
राष्ट्रीय सहारा रोजनामा (पटना)	93,117

पांच साल-करोड़ों का विज्ञापन

	प्रिंट मीडिया	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
2005–06	4,49,99,894=00	शून्य
2006–07	5,40,01,195=00	शून्य
2007–08	9,65,85,105=00	शून्य
2008–09	24,99,92,986=00	25,30,326=00
2009–10	18,28,22,183=00	1,37,89,511=00

(कुल 66 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा)

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार
वर्ष 2 अंक 6
दिल्ली, 19 अप्रैल–25 अप्रैल 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी एनकाउंटर को ही अगर देखें तो शुरुआत से ही इस मामले से जुड़े जांच अधिकारियों पर आरोपी पुलिस वालों को बचाने का आरोप लगता रहा है.

देश की आधी मुठभेड़ फ़र्ज़ी हैं

■ बाटला हाउस एनकाउंटर भी फ़र्ज़ी है ■ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ी मुठभेड़

■ सोलह साल में 2560 मुठभेड़, इसमें से 1224 फ़र्ज़ी मुठभेड़

मरने वाला अकेला नहीं मरता. उसके साथ मरती है कई और ज़िंदगियां. ताउम्र, तिल-तिल कर. और अगर वह मौत असमय हो तो तक़लीफ़ और बढ़ जाती है. फ़र्ज़ी मुठभेड़ का मामला भी कुछ ऐसा ही है. हर-एक मुठभेड़ के बाद पुलिस जोर-शोर से इसे सही साबित करने की कोशिश करती है तो कुछेक मानवाधिकार संगठन मुठभेड़ की सत्यता की जांच को लेकर हंगामा मचाते हैं. लेकिन फिर से पुलिस ऐसी ही कोई कहानी दोहरा देती है. आख़िर क्या है फ़र्ज़ी मुठभेड़ का सच?

शशि शेखर

सोलह साल में 2560 पुलिस और कथित अपराधी मुठभेड़. और इनमें से 1224 फ़र्ज़ी. यानी, भारत की हरेक दूसरी मुठभेड़ फ़र्ज़ी है. इतना ही नहीं, इस 1224 फर्जी मुठभेड़ की लिस्ट में बाटला हाउस मुठभेड़ का नाम भी शामिल हो गया है. हालांकि इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली पुलिस को पहले क्लीन चिट दे दी थी. लेकिन सूचना क़ानून के तहत आयोग ने जो लिस्ट उपलब्ध कराई है उसमें बाटला हाउस भी फ़र्ज़ी मुठभेड़ की लिस्ट में शामिल है. आख़िर, इस विरोधाभास की वजह क्या है. कहते हैं, मरने वाला अकेला नहीं मरता. उसके साथ मरती है कई और ज़िंदगियां. ताउम्र, तिल-तिल कर. और अगर वो मौत असमय हो तो तक़लीफ़ और बढ़ जाती है. फ़र्ज़ी मुठभेड़ का मामला भी कुछ ऐसा ही है. हर-एक मुठभेड़ के बाद पुलिस जोर-शोर से इसे सही साबित करने की कोशिश करती है तो कुछेक मानवाधिकार संगठन मुठभेड़ की सत्यता की जांच को लेकर हंगामा मचाते हैं. लेकिन, क़ानून को सबूत चाहिए. जांच रिपोर्ट चाहिए, जिसके आधार पर फ़ैसले लिए जाते हैं. लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे जिसे बनाने वाला पहले तो क्लिन चिट देता है और बाद में उसी घटना को फ़र्ज़ी बताता है. आयोग के जवाब से न सिर्फ़ बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगा है, बल्कि सारे 1224 फ़र्ज़ी मुठभेड़ों के बारे में चिंता हो गई है.

इसके अलावा, एनएचआरसी ने जो सूचना उपलब्ध कराई है उसके मुताबिक़ पिछले 16 साल में सांप्रदायिक हिंसा या जातीय हिंसा की 432 शिक़ायतें आयोग में पहुंची है. हिरासत में पुलिसिया जुल्म की फ़ेहरिस्त भी कोई कम नहीं है. पुलिस हिरासत में मारे जाने के 2320 मामले आयोग तक पहुंचे. पुलिस हिरासत में होने वाली मौत के मामले में महाराष्ट्र नंबर वन पर है. और इसके बाद नंबर आता है गुजरात का जहां साल 2002 के बाद पुलिस हिरासत में मौत की घटनाओं में वृद्धि दर्ज़ की गई है. इसके अलावा, आयोग ने यह भी बताया है कि पिछले सोलह सालों में जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं उनमें से महज़ 16 मामलों में ही पीड़ितों को मुआवज़ा मिला है. ज़ाहिर है, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन मामलों को आयोग ने फ़र्ज़ी करार दिया है

उसके लिए दोषी पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई? असल में पुलिस वालों का मनोबल इसी लिए बढ़ा रहता है, क्योंकि फ़र्ज़ी मुठभेड़ में शामिल किसी पुलिस वाले को कठोर सजा नहीं मिलती. दरअसल, किसी दोषी पुलिस अधिकारी की जांच भी तो कोई दूसरा पुलिस वाला ही करता है. ऐसे में अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को बचाने की भरसक कोशिश करता है.

सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी एनकाउंटर को ही अगर देखें तो शुरुआत से ही इस मामले से जुड़े जांच अधिकारियों पर आरोपी पुलिस वालों को बचाने का आरोप लगता रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात सरकार ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गीता जौहरी को चुना. लेकिन गीता जौहरी के ख़िलाफ़ भी आरोपी पुलिसवालों को बचाने के आरोप लगे. सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन को इस जांच पर भरोसा ही नहीं रहा. बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में चल रहे इस मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी और पूरा रिकार्ड सील करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को अपनी मदद के लिए एमेकस क्यूरी नियुक्त किया. एमेकस क्यूरी ने कई ऐसी लापरवाहियां गिनाईं जिससे गीता जौहरी ख़ुद संदेह के घेरे में आ गईं. उनके मुताबिक़ इस एनकाउंटर में राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी और सरकारी तंत्र भी शामिल था, लेकिन गीता जौहरी ने जांच के दायरे में उन्हें नहीं लिया. हालांकि, पिछले कुछ समय में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें अदालत ने फ़र्ज़ी मुठभेड़ के आरोपी पुलिसवालों को सजा सुनाई है. उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ज़िले में वर्ष 2003 में एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ हुई थी. सितंबर 2003 में सोनभद्र में बीएससी के छात्र प्रभात कुमार और उसके दोस्त रमाशंकर साहू को शातिर बदमाश बताकर पुलिस ने फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार डाला था. 6 साल की लंबी सुनवाई के बाद ज़िला फास्ट ट्रैक अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को उम्रक़ैद की सजा सुनाई. साथ ही इन पर 50 हज़ार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना भी ठोंका. फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मारे गए दोनों युवक झारखंड के गढ़वा ज़िले के निवासी थे. इसी तरह, देहरादून में गाज़ियाबाद के रहने वाले रणवीर सिंह की हत्या भी फ़र्ज़ी मुठभेड़ में कर दी गई थी. बाद में काफी हो-हल्ला होने पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई. सीबीआई और एसआईटी दोनों ने अपनी पड़ताल के बाद इसे फ़र्ज़ी मुठभेड़ कहा. सीबीआई-एसआईटी टीम ने जब मुठभेड़ स्थल का दौरा किया तो वहां ज़मीन के अंदर दबा कर रखे गए 10 कारतूस भी बरामद किए गए. सीबीआई ने अपनी जांच में 18 पुलिसवालों को फ़र्ज़ी मुठभेड़ के लिए दोषी माना. कुछ के ख़िलाफ़ केस भी दर्ज़ हुए हैं. लेकिन अभी भी यह देखना बाक़ी है कि इन दोषी पुलिसवालों को सजा मिलती भी है कि नहीं. पूर्वोत्तर भारत की हालत तो और भी ख़राब है जहां आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जैसा क़ानून लगा कर सुरक्षा बलों को निरंकुश ताक़त दे दी गई है. मणिपुर में तो सरे बाज़ार लोगों को गोली मार दी जाती है और बाद में कहा जाता है कि ये आतंकवादी थे. मणिपुर में फ़र्ज़ी मुठभेड़ और मानवाधिकार उल्लंघन तो आम बात है. साल 2008 में मणिपुर कमांडो पर उत्पीड़न और हत्या के 27 मामलों के आरोप लग चुके हैं. साल 2004 में इंफाल में महिलाओं द्वारा निर्वस्त्र प्रदर्शन पुलिस बल के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ ही था. निश्चित तौर पर वह प्रदर्शन अभी भी लोगों ने भुलाया नहीं होगा. यह प्रदर्शन असम राइफल्स के जवानों द्वारा एक मणिपुरी महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के विरोध में किया गया था. साल 2000 में असम राइफल्स के जवानों ने दस नागरिकों के साथ एक ऐसे युवक को मार गिराया था जिसे 1988 में राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इस हत्याकांड के विरोध में 28 वर्षीया इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल आज भी चल रही है.

मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वह यह कि क्या सरकार इसपर कोई कार्रवाई करेगी? आयोग की रिपोर्टों को कूड़ेदान में डालने की सरकारी तंत्र की पुरानी आदत है. आयोग को वैसे भी कोई क़ानूनी अधिकार है नहीं. पर पुलिस विभाग में काम करने वाले तमाम लोगों पर लगाम लगाने की जरुरत है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

राज्यवार फ़र्ज़ी मुठभेड़ों की संख्या

आंध्र प्रदेश	73
असम	11
बिहार	79
गुजरात	20
हरियाणा	18
जम्मू और काश्मीर	18
कर्नाटक	10
मध्य प्रदेश	36
महाराष्ट्र	61
मणिपुर	18
उड़ीसा	3
पंजाब	31
राजस्थान	11
तमिलनाडु	24
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	716
प. बंगाल	8
अंडमान और निकोबार	1
दिल्ली	22
छत्तीसगढ़	6
झारखंड	21
उत्तराखंड	29

फ़र्ज़ी है बाटला हाउस मुठभेड़!

जिस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस को क्लिन चिट दे दी थी उसी आयोग ने अब यह मान लिया है कि बाटला हाउस का एनकाउंटर फ़र्ज़ी था. यह खुलासा ख़ुद आयोग के उस लिस्ट से हुआ है जिसमें पिछले सोलह साल के दौरान हुए फ़र्ज़ी मुठभेड़ों की चर्चा है. सूचना क़ानून के तहत मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के अफ़रोज आलम को 50 पन्नों की जो लिस्ट उपलब्ध कराई है उसमें 1224 फ़र्ज़ी मुठभेड़ के विवरण शामिल हैं. फ़र्ज़ी मुठभेड़ों की इसी सूची में एल-18 पर बाटला हाउस एनकाउंटर भी शामिल है. बाटला हाउस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा की मृत्यु हुई थी. इसमें दो संदिग्ध आतंकवादी के मारे जाने की बात पुलिस कहती रही है. इनकी पहचान आतिफ़ अमीन और मोहम्मद साजिद के रूप में हुई थी और यह बताया गया था कि इनका संबंध इंडियन मुजाहिदीन से है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जब आजमगढ़ में ये कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर फ़र्ज़ी था तो राजनीतिक हलकों में तूफ़ान मच गया. बाद में उन्हें अपने बयान से पलटना पड़ा.

उत्तर प्रदेश, यानी फ़र्ज़ी मुठभेड़ का प्रदेश

विकास के किसी भी पैमाने पर उत्तर प्रदेश कहीं नहीं ठहरता. लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें इसने बाक़ी सभी राज्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया है. वह क्षेत्र है फ़र्ज़ी मुठभेड का. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक़ पिछले 16 साल में पूरे देश में जितने फ़र्ज़ी एनकाउंटर हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए. इस दौरान यहां पर 716 फ़र्ज़ी पुलिस मुठभेड़ हुए. ग़ौरतलब है कि इतने ही समय में पूरे देश में कुल 1224 फ़र्ज़ी एनकाउंटर हुए. कुल फ़र्ज़ी मुठभेड़ की आधी से भी अधिक संख्या सिर्फ़ उत्तर प्रदेश से है. इसके बाद नंबर आता है बिहार का. बिहार में 79 फ़र्ज़ी मुठभेड़ हुए. आंध्र प्रदेश, जहां 73 लोगों की जानें फ़र्ज़ी मुठभेड़ के नाम पर चली गई. महाराष्ट्र भी फ़र्ज़ी एनकाउंटर के मामले में ज़्यादा पीछे नहीं है. इस राज्य में 61 फ़र्ज़ी एनकाउंटर की घटनाएं हुई. फिर भी, उत्तर प्रदेश का आकड़ा दिल दहलाने वाला है. हरेक साल लगभग 50 की औसत से होने वाले फर्जी एनकाउंटर की घटना तो आम आदमी के दिल में भी असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए काफी है.

भारत सरकार के इस फ़ैसले का पूरे देश में पर्यावरणविदों गंगा प्रेमियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है.

मनमोहन ने बंद कराई गंगा परियोजना

संतों के सामने कांग्रेस भाजपा से ज़्यादा नतमस्तक

राजकुमार शर्मा

गंगा की अविरल जल धारा को बनाए रखने के मामले में संतों के कहने पर कांग्रेस की यूपीए सरकार भाजपा से भी आगे निकल गई है. अब वह मानने लगी है कि अगर गंगा की धारा से ज़्यादा छेड़छाड़ की गई तो उत्तराखंड का विकास हो कि न हो, पर्यावरण पर इसका सीधा असर पड़ेगा. साधु संत और कुछ सामाजिक संगठन भी ऐसा ही कह रहे हैं. ऐसे में देश के साधु-संतों के साथ खड़ी यूपीए सरकार के फ़ैसले से नाराज़ सूबे की निशंक सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रही है. भाजपा सरकार का आरोप है कि राज्य के विकास को नज़रअंदाज़ करके यूपीए सरकार ने संतों के सामने घुटने टेक दिए हैं. मनमोहन सरकार चाहती है कि गंगा की अविरल धारा के साथ कम से कम छेड़ छाड़ की जाए. गोमुख से उत्तरकाशी तक गंगा को सुरंगों से कम से कम गुज़ारा जाए जिससे गंगा जल की गुणवत्ता बनी रहे. इसी बात को ध्यान में रख कर संत समाज की मांग को मानते हुए केंद्र सरकार ने गंगा पर बन रही दो बड़ी परियोजनाओं, भैरवघाटी व पाला मनेरी को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फ़ैसला किया है. इसके कारण सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया लगता है. उल्लेखनीय है कि यह फ़ैसला भारत सरकार ने प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया है. तीसरी परियोजना लोहारी नागपाला के बारे में भी निर्णय डेढ़ माह बाद ले लिया जाएगा. लेकिन निशंक सरकार अब भी चाहती है कि गंगा से जुड़ी उसकी अनेकों छोटी छोटी परियोजनाएं चलती रहें ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार का रास्ता बनता रहे और राज्य का विकास भी जारी रहे. पर केंद्र सरकार का रुख़ इन छोटी परियोजनाओं को लेकर भी नकारात्मक है. संभवत: आपको ध्यान हो, पूरे देश में गंगा को बचाने की एक मुहिम पर्यावरण प्रेमियों द्वारा लंबे अरसे से चलाई जा रही है. मजबूरी में राज्य सरकार ने भी पिछले साल से ही इन परियोजनाओं पर काम रोक रखा है.

लोहारी नागपाला में अब तक तीस प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, इसलिए इस कार्य के तकनीकी पहलुओं के प्रभावों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बैठा दी गई है जिसमें पर्यावरण, बिजली विभाग और आईआईटी के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. यह समिति हर स्तर से इसके नफ़े नुक़सान का आकलन कर डेढ़ माह बाद अपनी रिपोर्ट देगी. पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना को भी बढ़ने की उम्मीद नहीं है. सरकार के इस फ़ैसले से सूबे को 933 मेगावाट मिलने वाली बिजली की परियोजनाओं पर पानी फिरता नज़र आ रहा है. इन परियोजनाओं पर अब तक चार सौ करोड़ रुपये ख़र्च हो चुके हैं. डेढ़ हज़ार करोड़ की लागत से बनने वाली इन परियोजओं से सूबे को सीधे 933 मेगावाट बिजली मिलती. उत्तरकाशी से गंगोत्री के मध्य लगभग 600 करोड़ रुपये के बजट वाली पाला मनेरी पर भी सरकार के 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा ख़र्च हो चुके हैं, जिसमें 480 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभावित था, इतनी ही लागत से तैयार होने वाली भैरोंघाटी जल विद्युत परियोजना पर काम अभी शुरू नहीं हुआ था.

ये दोनों परियोजनाएं राज्य सरकार की उपक्रम हैं. राज्य में बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए इन परियोजनाओं पर सरकार को खासा लाभ मिलने की उम्मीद थी जिस पर पानी फिरने से पूरी सरकार में खलबली मच गई है. यद्यपि इन परियोजनाओं को रोकने एवं पर्यावरण को बचाने के लिए अब तक चले आंदोलनों का इतिहास भी लंबा है. 13 जून को प्रो.जीडी अग्रवाल ने जो अनशन शुरू किया था वह 30 जून तक चला था. इस आंदोलन को देखते हुए राज्य की सरकार ने ही पालामनेरी व भैरों घाटी प्रोजेक्ट को 18 जून को रोकने की घोषणा की थी. इस प्रकरण में 30 जून 2008 में ही केंद्र सरकार ने परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की थी. इस कमेटी को 90 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी किंतु दिसंबर तक यह रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकी. इस मामले को गरमाने के उद्देश्य से प्रो.अग्रवाल पुन: 14 जनवरी को एक माह तक आमरण अनशन पर बैठे, केंद्र सरकार ने उसे गंभीरता से लेते हुए गंगानदी विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री बने और निर्णय आने तक परियोजना का काम बंद रखने की बात तय की गई. 27 फरवरी 2009 को अवधेश कौशल जी की एक याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने परियोजना के पक्ष में स्थगन आदेश दे दिया. 18 मई 2009 को माननीय उच्च न्यायालय ने इन परियोजनाओं पर निर्णय का अधिकार गंगा विकास प्राधिकरण को सौंप दिया. 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री ने प्राधिकरण की पहली बैठक स्वंय ली. इस बैठक में भाग ले रहे सभी ग़ैर सरकारी सदस्यों ने इन तीन परियोजनाओं को ख़ारिज करने के लिए अपनी सिफ़ारिश की. इस बैठक के रुख़ को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा एंव पर्यावरण मंत्रालय को नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश भी जारी किया. 30 नवंबर 09 को दोनों विभागों के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए ग़ैर सरकारी सदस्यों की एक बैठक ली. इन मंत्रियों के साथ दोनों मंत्रालयों के सचिवों ने स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंपी. इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं को स्थगित करने का फ़ैसला लिया. अब इस फ़ैसले के आते ही अपनी दूसरी असफलताओं से तंग सूबे के मुख्यमंत्री को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है. इस प्रकरण पर सूबे के मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों की भावनाओं को भुनाने के लिए केंद्र सरकार से दो हाथ करते दिखना चाहते हैं. पिछले संसदीय चुनाव में सूबे की पांचों सीटों पर अपना परचम लहरा चुकी कांग्रेस एवं उसके स्थानीय नेता इस गंगा की अविरल धारा में डूबते उतराते दिख रहे हैं. उन्हें लगता है कि उनकी अगली राजनीति का आधार यही बन सकता है. टिहरी से सांसद विजय बहुगुणा ने तो प्रधानमंत्री जी से मिल कर इन परियोजनाओं को स्थानीय उनके मतदाताओं की भावनाओं को देखते हुए परियोजनाओं को निरस्त करने जैसे फ़ैसले न करने की वकालत भी कर डाली थी. सूबे के प्रतिपक्ष के नेता हरक सिंह रावत भी पूरी तरह से विजय बहुगुणा की हां में हां मिलाते दिखे. किंतु प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के संतों और पर्यावरण विदों की भावनाओं का आदर करते हुए इन परियोजनाओं को ख़ारिज करना ही मुनासिब समझा है.

भारत सरकार के इस फ़ैसले का पूरे देश में पर्यावरणविदों गंगा प्रेमियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्व विद्यालय के प्रथम कुलपति जैराम संस्थाओं के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने इस फ़ैसले का तहे दिल से स्वागत करते हुए कहा कि यह फ़ैसला भारतीय संस्कृति की प्रतीक गंगा को बचाने का एक भागीरथ प्रयास सिद्ध होगा. इसी कड़ी में अटल सरकार में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे परमार्थ आश्रम हरिद्वार के परमाध्यक्ष स्वामी चिन्मयानंद ने मुख्यमंत्री की ख़बर लेते हुए कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री को अपने किए गए वायदे के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए. उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री गंगा की अविरल धारा के साथ राजनीति करने की भूल न करें. गोरखपुर गोरखनाथ पीठ के पीठाध्यक्ष एवं सांसद महंत योगी आदित्य नाथ ने मनमोहन सरकार के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने संतों की पवित्र भावना का आदर किया है, उन्होंने निशंक से संस्कार विरोधी आचरण न करने की बात कही है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास ने केंद्र सरकार के फ़ैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार ने गंगा को बचाने के लिए सार्थक क़दम उठाया है, हिमालय के प्रख्यात पर्यावरण विद सुंदर लाल बहुगुणा ने कहा कि पर्यावरण के हित में केंद्र का ये पश्चाताप स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि गंगा असंख्य वर्षों तक बहती रहे इसके लिए उसे बांधना छोड़ दे. यहां तक कि सूबे के बसपा के विधायक शहजाद ने भी केंद्र सरकार के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार संतों का सम्मान करती है.

मुख्यमंत्री निशंक का सरकार के फ़ैसले पर बिफरना संत समाज को बिल्कुल नहीं भा रहा है. इसके बावजूद निशंक सूबे की जनता के हित की दुहाई देकर केंद्र सरकार से दो हाथ करने के मूड में दिख रहे है. इस फ़ैसले के बाद निशंक केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री डा.जय राम रमेश से खासे नाराज़ दिख रहे हैं. अब तक गंगा संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति की वकालत कर राष्ट्र में अपनी वजूद बनाने वाली भाजपा के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का गंगा की अविरल धारा पर राजनीति की पैतरे बाजी से अनेक भाजपाई भी हैरत में हैं जिसे देखकर यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भाजपा में भी दो गुट बन चुके हैं . गंगा के सवाल पर जगतगुरू स्वरूपानंद सरस्वती जी का मानना है कि मानव जीवन के लिए गंगा का बचना ज़रूरी है. उन्होंने सरकार की बिजली परियोजनाओं के ख़ारिज करने के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जीवन दायिनी मोक्ष दायिनी गंगा के सवाल पर निशंक को राजनीति नहीं करनी चाहिए.

कैग ने गंगा बचाने की पहल की

सरकारी संस्था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कैग) ने हाल ही में उत्तराखण्ड की जल विद्युत परियोजनाओं के परफार्मेंस के संदर्भ में जो रिर्पोट सरकार को सौंपी है उससे लगता है कि कैग पर्यावरण बचाने के लिए किसी से भी टकराव लेस करता है. उसकी रिपोर्ट में यह बताने के लिए पर्याप्त आधार दिए गए है कि राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं के चलते गंगा लगभग ख़त्म हो जाएगी. रिपोर्ट में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि इसका ख़ासा असर उत्तरप्रदेश एवं बिहार की खेती पर भी पड़ेगा जिसके चलते इन दोनों राज्यों में भी गंगा पर आधारित खेती करने वाले 40 प्रतिशत किसानों के प्रभावित होने की आशंका है. इस रिपोर्ट को वैसे तो 1993 से 2006 के मध्य की जल विद्युत परियोजनाओं को फोकस करके तैयार किया गया है, लेकिन इसमें यह साफ कहा गया है कि यदि समय रहते इन परियोजनाओं पर लगाम न लगाई गई तो गंगा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा. यह तर्क दिया गया है कि अलकनंदा से देवप्रयाग के मध्य पड़ने वाले 160 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ने वाले 53 परियोजनाओं के लिए टनल और बांध बनाने होंगे, एक बांध की दूरी लगभग साढ़े तीन किमी आंकी गई हैं. इसमें यह भी खुलासा किया गया है कि इन बांधों के निर्माण के बाद पहाड़ का उपाजाऊ सिल्ट वही जम जाएगा और दूसरी तरफ़ टनल और टरबाइन के ल्यूब्रीकेंट भी गंगा जल में मिलकर उसकी शुद्धता को ख़त्म कर देंगे. विश्वस्तरीय मानकों के अनुसार किसी भी नदी का अधिकतम 75 प्रतिशत पानी डायवर्ट करके ही पर्यावरण और जलीय जीवों को बचाया जा सकता हैं. हिमालयी क्षेत्र का पूरा इलाक़ा पहले से ही भूकंप के लिहाज़ से अति संवेदनशील है और यह पूरा क्षेत्र जोन -5 में शामिल है.

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन लाख से ज़्यादा दर्शक

- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- दुनिया की बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री
- हैरतअंगेज़ वीडियो
- हर रोज़ मिलिए चौथी दुनिया के लेखकों से
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

कोपेनहेगन समझौते में भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका और ब्राजील शामिल हैं. हालांकि समझौते के प्रावधान समझौते में शरीक राष्ट्रों के लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं.

पर्यावरण सुरक्षा और भारत

क्योटो प्रोटोकॉल के प्रति भारत का दृष्टिकोण

जस्टिस पी. सथाशिवम

भारत ने अगस्त, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया. इस प्रोटोकॉल की कई शर्तों से भारत को छूट हासिल है और तकनीकी हस्तांतरण एवं विदेशी निवेश के क्षेत्र में फ़ायदा हो सकता है. जून, 2005 को जी-8 के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि विकासशील देशों के मुक़ाबले विकसित देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की दर कहीं ज़्यादा है. भारत हालांकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में अपनी ज़िम्मेदारियों से भलीभांति वाक़िफ़ है, फिर भी उसका मानना है कि विकसित देशों को इस दिशा में ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है. दूसरी ओर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का तर्क है कि आने वाले कुछ दशकों में भारत और चीन जैसे राष्ट्रों में औद्योगीकरण और तीव्र आर्थिक विकास के चलते उत्सर्जन की दर में तेज़ी आ सकती है.

कोपेनहेगन समझौता

कोपेनहेगन समझौते में भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका और ब्राजील शामिल हैं. हालांकि समझौते के प्रावधान समझौते में शरीक राष्ट्रों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन यह क्योटो प्रोटोकॉल को बनाए रखने की अनुशंसा करता है. इसमें यह माना गया है कि जलवायु परिवर्तन मौजूदा दौर की गंभीरतम समस्याओं में से एक है और इससे तत्काल निपटने के लिए सम्मिलित ज़िम्मेदारी एवं योग्यता के सिद्धांत के अनुरूप मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है. पर्यावरण तंत्र के साथ मानवीय छेड़छाड़ की गंभीरता को रेखांकित करते हुए समझौते में इस वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार किया गया है कि दीर्घकालीन विकास और जलवायु परिवर्तन के नज़रिए से वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि दो डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए. इस ख़तरे से निपटने के लिए उठाए गए क़दमों का पीड़ित राष्ट्रों पर पड़ने वाले असर, ख़ासतौर से ऐसे राष्ट्र जो इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, को रेखांकित करते हुए समझौते में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ विस्तृत कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर बल दिया गया है. इसमें यह भी माना गया है कि वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाए जाने की तत्काल ज़रूरत है (आईपीसीसी एआर 4). इतना ही नहीं, समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कम उत्सर्जन पर आधारित विकास की रणनीति बनाई जानी चाहिए.

इसमें कहा गया है कि उत्सर्जन के ख़िलाफ़ विकासशील राष्ट्रों में प्रतिरोधी क्षमता के विकास और उन पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सामंजस्य से तत्काल क़दम उठाए जाने चाहिए. ऐसे देशों में मुख्य रूप से अल्प विकसित राष्ट्र, छोटे द्वीपीय राष्ट्र और अफ़्रीकी महादेश के राष्ट्र शामिल हैं. समझौते में विकसित राष्ट्रों से यह अपील की गई है कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर ख़तरे से निपटने के लिए वे विकासशील राष्ट्रों को पर्याप्त और दीर्घकालीन आर्थिक एवं तकनीकी संसाधन मुहैया कराएं. उत्सर्जन को कम करने की दिशा में इसमें कहा गया है कि विकसित राष्ट्र 31 जनवरी, 2010 से पहले साल 2020 तक उत्सर्जन के स्तर में कमी से संबंधित अपने लक्ष्य की घोषणा करेंगे और क्योटो प्रोटोकॉल के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के मद्देनज़र इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे. विकसित राष्ट्रों की इन कोशिशों का सीओपी के दिशानिर्देशों के तहत आकलन और पुनरीक्षण किया जाएगा. विकासशील देशों को भी उत्सर्जन के अपने लक्ष्यों को 31 जनवरी, 2010 से पहले घोषित करना होगा. अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के लिए इसमें कहा गया है कि वे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के आधार पर इस दिशा में स्वत: ही कदम उठाएंगे.

समझौते में बताया गया है कि विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय के माध्यम से हर दो साल पर अपने प्रयासों का लेखाजोखा प्रस्तुत करेंगे. समझौते में जंगलों की कटाई से होने वाले उत्सर्जन की भूमिका पर भी जोर दिया गया है और इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि को कम करने की ज़रूरत को रेखांकित किया गया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों से आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए एक सुनियोजित तंत्र विकसित करने की ज़रूरत पर भी बल दिया गया है और ऐसे मौक़ों की तलाश करने की बात की गई है, जिससे उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के इन प्रयासों को बाज़ार के मुताबिक़ कम ख़र्चीला बनाया जा सके.

ऐसे विकासशील देश जहां पहले से ही उत्सर्जन का स्तर कम है, उन्हें विकास के इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है. समझौते में कहा गया है कि इन देशों में कम उत्सर्जन सुनिश्चित करने वाली विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तमाम आर्थिक और तकनीकी सहूलियतें मुहैया कराई जाएंगी. समझौते में यह सहमति भी बनी कि विकसित राष्ट्र साल 2010-2012 के बीच 30 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त कोष पैदा करेंगे. इतना ही नहीं, साल 2020 के आते-आते विभिन्न स्रोतों से हर साल 100 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त कोष जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसका इस्तेमाल विकासशील देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों के हित में किया जाएगा. इन प्रयासों के लिए भविष्य में भी आर्थिक सहायता सरकारी तंत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी.

समझौते के तहत एक कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का प्रावधान है, जो उत्सर्जन में कमी लाने के विकासशील देशों के प्रयासों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के काम में उपयोगी होगी. इस दिशा में एक उच्चस्तरीय निकाय के गठन का भी प्रावधान है, जो हर देश की ज़रूरत के हिसाब से तकनीकों के हस्तांतरण पर नज़र रखेगा और इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित भी करेगा.

अंत में इसमें यह भी कहा गया है कि समझौते के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा 2015 तक पूरी कर ली जाएगी. यह समीक्षा समझौते के दीर्घकालीन लक्ष्यों, जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि की दर को 1.5 डिग्री तक नियंत्रित करना, के संदर्भ में की जाएगी. समझौते में शामिल सभी देश, जिनमें भारत भी शामिल है, का स्पष्ट मानना है कि हालांकि वे इन सभी प्रावधानों को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन ये प्रावधान क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं.

पर्यावरण से संबंधित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सभी बैंकों से यह अपील की है कि वे परियोजनाओं के लिए लोन आवंटन की प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन का ध्यान रखें. आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक़, बैंक के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर को भी अपनी व्यवसायिक रणनीति में कार्बन उत्सर्जन की समस्या को जगह देनी होगी. इस परिप्रेक्ष्य में निम्न पांच प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखना मददगार हो सकता है:

निरंतरता : व्यवसायिक मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए ऐसी नीति अपनाई जाए, जो सामाजिक और पर्यावरणीय ज़रूरतों से मेल खाती हो.

कोई नुकसान नहीं : अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को इस तरह नियंत्रित करना कि पर्यावरण और समाज को कोई नुक़सान न पहुंचे.

उत्तरदायित्व : अपनी व्यवसायिक गतिविधियों का पर्यावरण एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की पूरी ज़िम्मेदारी लेना.

जवाबदेही : व्यवसायिक गतिविधियों से प्रभावित होने वाले सभी पक्षों के प्रति जवाबदेही.

पारदर्शिता : सभी संबद्ध पक्षों के साथ पारदर्शिता बनाए रखना. यहां पारदर्शिता से तात्पर्य केवल नियमित अंतराल पर प्रसारित-प्रकाशित की जाने वाली उद्घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि पूछे जाने पर बैंक की नीतियों, प्रक्रियाओं और लेनदेनों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने से है.

अन्य प्रतिबद्धताएं

2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन की शुरुआत में भारत के पर्यावरण मंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए हर प्रयास के प्रति भारत के सहयोग और समर्थन की घोषणा की. उन्होंने इस संदर्भ में छह ऐसे क़दमों का ख़ासतौर पर ज़िक्र किया, जिन्हें देश के क़ानून में जगह देने की पहल शुरू हो चुकी है, जैसे- साल 2011 तक ईंधन के साधनों में सभी आवश्यक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना. 2012 तक निर्माण कार्यों में सभी आवश्यक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना. वनीकरण में वृद्धि, ताकि देश के कुल कार्बन उत्सर्जन का कम से कम 10 प्रतिशत उसके जंगलों में ही खप जाए. 2020 तक ईंधन के मानकों में 10 प्रतिशत और वृद्धि. साल 2020 तक देश के कुल बिजली उत्पादन में वायु, सौर एवं हाइड्रो स्रोतों की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी (फ़िलहाल यह केवल 8 प्रतिशत है) संभव हो सके और सभी नई कोयला परियोजनाओं में 50 प्रतिशत को कोयला मुक्त बनाना.

धनी राष्ट्र केवल उपदेश देते हैं, प्रयास नहीं करते

विश्व के धनी देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में कोई कमी नहीं आई है. यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) द्वारा जारी किए ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है. यूएनएफसीसी के इन आंकड़ों में क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार 1990 को आधार वर्ष (बेस इयर) माना गया है. इसके मुताबिक़, साल 2007 में धनी राष्ट्रों में उत्सर्जन के स्तर में 1990 के मुक़ाबले 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उक्त सभी राष्ट्र क्योटो प्रोटोकॉल को मानने के लिए अपनी हामी भर चुके हैं. इन 17 सालों में अकेले अमेरिका में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 17 प्रतिशत इज़ाफ़ा हुआ है. इसके बावजूद भारत धनी देशों के निशाने पर है, जबकि उत्सर्जन के मामले में भारत का रिकॉर्ड अमीर देशों के मुक़ाबले कहीं अच्छा है. फिर भी तीव्र आर्थिक विकास के नाम पर धनी राष्ट्र भारत को ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार बताते हैं. जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय बातचीत के इस निराशाजनक माहौल को देखते हुए भारत और चीन ने अपने स्तर पर इस दिशा में कुछ क़दम उठाने की पहल की है. ग्लोबल वार्मिंग और इससे संबंधित अन्य पर्यावरणीय मामलों में बेहतर सहयोग और जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों ने एक सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए अलग-अलग स्तरों, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय, पर पहल करना वक़्त की ज़रूरत है. संयुक्त राष्ट्र समर्थित 192 देशों के बीच बहुपक्षीय बातचीत का अपना अलग महत्व है. इसने विभिन्न देशों के बीच विचार-विमर्श के अलावा नागरिक संस्थाओं एवं मीडिया में इसे गर्मागर्म बहस का मुद्दा बना दिया है. वास्तविकता यह है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता भले बढ़ी हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका कोई ख़ास परिणाम नहीं निकल पाया है. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के ताज़ा आंकड़ों को देखें तो यही लगता है कि अभी तक इसके परिणाम अपेक्षाओं के विपरीत ही रहे हैं.

प्रभावोत्पादकता के नज़रिए से द्विपक्षीय बातचीत और समझौते ज़्यादा सफल हो सकते हैं, क्योंकि इनमें लक्ष्यों की स्पष्ट व्याख्या होती है और उन पर नज़र रखने के लिए समुचित निगरानी तंत्र का गठन भी आसान है. देश में कोयला परियोजनाओं और गाड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते चीन वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है. इससे निपटने के लिए चीन ने स्वच्छ तकनीकों के इस्तेमाल की योजना बनाई है और इस मुद्दे पर भारत-चीन के बीच सहयोग काफी संभावनाएं पैदा कर सकता है. दोनों देश यानी भारत और चीन तकनीकी रूप से सक्षम हैं और यदि वे उत्सर्जन के अलावा प्रदूषण के अन्य कारकों पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे तो यह उनके नागरिकों के लिए काफी अच्छा होगा. तकनीक, सूचनाओं एवं एक-दूसरे के अनुभवों के आदान-प्रदान से भी काफी कुछ हासिल किया जा सकता है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं)
feedback@chauthiduniya.com

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का देश के मुसलमानों ने पूरे उत्साह से स्वागत किया था. इस तथ्य को हमारे इतिहासविदों ने कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया.

स्वाधीनता संग्राम और मुसलमान

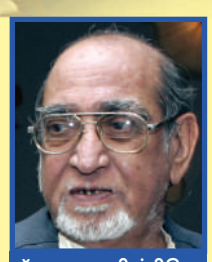

डॉ. असगर अली इंजीनियर

इस साल कांग्रेस अपना 125वां स्थापना दिवस मना रही है. भारत के सभी धर्मों के नागरिकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज़रिए स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, परंतु हमारे नेताओं की बहुसंख्यकवादी मानसिकता और स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने वालों के संकीर्ण दृष्टिकोण के चलते भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अल्पसंख्यकों की भूमिका को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया है. भारत कभी उस अर्थ में राष्ट्र नहीं रहा, जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पश्चिम में किया जाता है. पश्चिमी राष्ट्रों का आधार है एक भाषा और एक संस्कृति. इसके विपरीत भारत कभी एक भाषा, धर्म या संस्कृति वाला देश नहीं रहा. धार्मिक, भाषाई, नस्लीय और सांस्कृतिक विविधताएं हमेशा से भारत की विशेषता रही हैं. जब हमने ब्रिटिश राज की अपरिमित शक्ति को चुनौती देने का निर्णय किया, तभी हमारे नेताओं को यह अहसास हो गया था कि देश के लोगों–विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों में एकता कितनी महत्वपूर्ण है. स्वाधीनता संग्राम का एक नारा था, *दीन–धरम हमारा मज़हब, ये ईसाई (अर्थात अंग्रेज) कहां से आए.*

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का देश के मुसलमानों ने पूरे उत्साह से स्वागत किया था. इस तथ्य को हमारे इतिहासविदों ने कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया. हमारे इतिहासविद् हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सर सैय्यद ने मुसलमानों को यह सलाह दी थी कि वे कांग्रेस की सदस्यता न लें. तथ्य यह है कि यह मुस्लिम श्रेष्ठी वर्ग के एक छोटे से हिस्से की राय थी. यह वह तबका था, जिसने 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों के हाथों बहुत अत्याचार सहे थे और जो अंग्रेजों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था. हिंदुओं में भी ऐसे तत्व थे, विशेषकर जमींदारों, राजाओं एवं महाराजाओं में. इसके अलावा सर सैय्यद का कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण शत्रुता का नहीं था. वह तो केवल यह चाहते थे कि मुसलमान आधुनिक शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर ज़्यादा ध्यान दें. सर सैय्यद की भूमिका के बारे में बहुसंख्यक सांप्रदायिक तत्वों ने कई तरह के भ्रम फैलाए हैं. इस सिलसिले में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि सर सैय्यद ने हिंदू–मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रयास किए. उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को भारत रूपी दुल्हन की दो आंखें निरूपित किया था. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर सैय्यद आम जनता के नेता नहीं थे. वह तो केवल उत्तर भारत के मुस्लिम श्रेष्ठी वर्ग को सामाजिक एवं शैक्षिक सुधारों के लिए प्रेरित करना चाहते थे. पूरा मुस्लिम श्रेष्ठी वर्ग भी सर सैय्यद के साथ नहीं था. इस वर्ग के एक सदस्य एवं बंबई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बदरुद्दीन तैय्यबजी ने बंबई अधिवेशन के दौरान अपने 300 साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली थी. वह बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए.

आम मुसलमानों ने कांग्रेस की स्थापना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और कांग्रेस के सभी आंदोलनों को अपना समर्थन दिया. कांग्रेस के निर्माण से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक मुसलमान कांग्रेस के साथ बने रहे. इस लेख में हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे. सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि किसी समुदाय के कुछ सदस्यों के कामों या गतिविधियों से पूरे समुदाय के संबंध में कोई राय नहीं क़ायम करनी चाहिए. हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं और अपना एजेंडा होता है. कई लोगों को यह जानकर हैरत होगी कि मुसलमानों में कांग्रेस के सबसे उत्साही समर्थक हैं देवबंद के पुरातनपंथी उलेमा. यहां यह जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि उलेमाओं ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिया था और उसमें अपनी पूरी ताक़त झोंक दी थी. इन उलेमाओं ने 1857 की क्रांति में बड़ी–बड़ी कुर्बानियां दीं और उनमें से सैकड़ों को कालापानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया. कई को इटली के दक्षिण में स्थित माल्टा नामक द्वीप में निर्वासित कर दिया गया. मैंने माल्टा के कब्रिस्तान में सैकड़ों उलेमाओं की कब्रें देखी हैं. उन्हें अपने महबूब वतन की मिट्टी में दफन होना भी नसीब नहीं हुआ. जिन उलेमाओं को निर्वासित किया गया था, उनमें से कई तो बहुत जाने–माने थे. ऐसे ही एक उलेमा थे मौलाना फज़ल काहिराबादी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद दारूल उलूम देवबंद के संस्थापक मौलाना कासिम अहमद नानोटवी, जो स्वयं एक जाने–माने आलिम थे, ने एक फतवा जारी कर मुसलमानों को कांग्रेस की सदस्यता लेने और अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर करने के लिए कहा. न केवल यह, उन्होंने इस तरह के एक सौ फतवों को इकट्ठा कर उनका संकलन प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था नुसरत अल–अहरार (स्वतंत्रता सेनानियों की मदद के लिए). उक्त उलेमा आम मुसलमानों के नेता थे और देश से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध थे. एक अन्य जाने–माने आलिम मौलाना महमूद उल हसन ने हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का संदेश पूरे देश में फैलाने की एक योजना, जिसे रेशमी रूमाल षड्यंत्र कहा जाता है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. मौलाना महमूद उल हसन के अलावा अन्य कई उलेमाओं और आम मुसलमानों ने इस षड्यंत्र में भाग लिया था. मौलाना हसरत मोहानी एक प्रतिष्ठित उर्दू कवि एवं बुद्धिजीवी थे. इसके साथ–साथ वह एक महान क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में हिस्सा लिया और बहुत कष्ट भोगे. वह बाल गंगाधर तिलक और उनके प्रसिद्ध नारे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के घोर प्रशंसक थे. वह तिलक को तिलक महाराज के नाम से पुकारते थे. एक मौलाना होते हुए भी वह 1925 में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. मौलाना कई बार जेल गए और उन्हें कड़ी सजाएं दी गईं. इनमें शामिल थी रोज 40 किलो अनाज पीसने की सजा, परंतु मौलाना ने कभी हार नहीं मानीं. गांधी जी तक देश के दूरगामी हितों की ख़ातिर कुछ समय के लिए होमरूल के लिए राजी हो गए थे, परंतु मौलाना इस मामले में किसी प्रकार के समझौते के पक्षधर नहीं थे. जब कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में होमरुल प्रस्ताव पेश किया गया, उस समय मौलाना को एक मुशायरे की तैयारी के बहाने अधिवेशन स्थल से दूर रखा गया, क्योंकि यह तय था कि वह प्रस्ताव का कड़ा विरोध करेंगे. यह थी मौलाना की भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता.

ख़िलाफ़त आंदोलन के संबंध में भी अनेक भ्रांतियां हैं. ख़िलाफ़त आंदोलन, महात्मा गांधी की अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति का हिस्सा था. इसके ज़रिए गांधी जी ने सफलतापूर्वक लाखों आम मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा. दुर्भाग्यवश, हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस आंदोलन को सही दृष्टिकोण से नहीं देखता, परंतु इस तथ्य को कोई नहीं नकार सकता कि इस आंदोलन के कारण ही बड़ी संख्या में मुसलमान स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा बने. यह अलग बात है कि कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में हुई क्रांति के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया. अली बंधु–मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली इसी आंदोलन की उपज थे. अली बंधुओं ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. उनकी मां भी स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति उतनी ही प्रतिबद्ध थीं. जब उनकी मां को इस अफ़वाह की जानकारी मिली कि अली बंधु माफी मांग कर जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं (यह कोरी अफ़वाह ही थी) तो एक पर्दानशीन महिला होने के बावजूद उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से घोषणा की कि अगर मेरे पुत्रों ने ऐसा कुछ किया तो मैं उनका दूध माफ नहीं करूंगी. जीवन के अंतिम समय में मौलाना मोहम्मद अली के गांधी जी से गंभीर मतभेद हो गए थे, परंतु अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि उन्हें येरूशेलम में दफनाया जाए, क्योंकि वह गुलाम भारत में नहीं दफन होना चाहते. ख़िलाफ़त आंदोलन के दौरान कुछ मुसलमानों ने ब्रिटिश भारत को दारूल हर्ब (युद्ध का घर) घोषित करके अफ़ग़ानिस्तान पलायन करना शुरू कर दिया, ताकि वहां निर्वासित सरकार स्थापित कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का संचालन किया जा सके. इस पलायन के मुख्य प्रेरणास्रोत थे मौलाना उबेदुल्ला सिंधी. उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान में स्वतंत्र भारत की अंतरिम निर्वासित सरकार बनाई. राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार के राष्ट्रपति थे और मौलाना उबेदुल्ला प्रधानमंत्री. दुर्भाग्यवश अफगानिस्तान के बादशाह ने ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर वहां पहुंचे मुसलमानों को अपने देश से निकाल दिया. इस कार्यवाही में हज़ारों मुसलमान मारे गए. ऐसी थी आज़ादी के प्रति मुसलमानों की दीवानगी.

स्वाधीनता आंदोलन के एक अन्य चमकीले सितारे थे मौलाना हुसैन अहमद मदानी. उन्होंने देश के विभाजन का जमकर विरोध किया. वह महान कवि एवं चिंतक इक़बाल से तक भिड़ गए और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर इक़बाल के विचारों को चुनौती दी. उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिसका शीर्षक था मुत्तहिदा कौमीयत और इस्लाम (सांझा राष्ट्रवाद और इस्लाम). उन्होंने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को भी चुनौती दी और कुरान और हदीथ से लिए गए उदाहरणों से यह साबित किया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को इस्लाम की मंजूरी नहीं है. उनकी इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है. यह अनुवाद जमीयते उलेमा ए हिंद ने कराया है और अब इस पुस्तक का लाभ उर्दू न जानने वाले भी उठा सकते हैं. मौलाना हुसैन अहमद को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जूतों की मालाएं पहनाईं. स्वतंत्रता आंदोलन में मौलाना आज़ाद और सरहदी गांधी ख़ान अब्दुल गफ्फार खान के स्वर्णिम योगदान को कौन भुला सकता है. दोनों अपनी अंतिम सांस तक भारत की आज़ादी के दीवाने बने रहे. खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र ऐसे नेता थे, जिन्होंने देश के विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठकों में विभाजन का तब भी विरोध किया, जब नेहरू और सरदार पटेल तक ने इसे अपरिहार्य मानकर स्वीकार कर लिया था. मौलाना आज़ाद ने विभाजन का विरोध करते हुए जो लेख लिखा था, इस विषय पर उससे बेहतर शायद ही कुछ लिखा गया होगा. इन मुस्लिम नेताओं को स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में वह स्थान नहीं मिला, जिसके वे लायक़ थे. हमारे कई शिक्षाविदों, इतिहासकारों, पाठ्यपुस्तक लेखकों और सबसे बढ़कर राजनीतिज्ञों की सांप्रदायिक सोच के कारण इन मुस्लिम नेताओं की स्वाधीनता आंदोलन में महती भूमिका को भुला दिया गया या फिर उसे बहुत ही कम स्थान दिया गया. जब मैं मदुरई के गांधी संग्रहालय में गया, जो देश के सर्वश्रेष्ठ गांधी संग्रहालयों में से एक माना जाता है, तो मुझे यह देखकर बहुत दु:ख हुआ कि वहां सरहदी गांधी की स्वाधीनता संग्राम में भूमिका के नाम पर उनकी केवल एक तस्वीर थी. मैंने संग्रहालय के संचालक का ध्यान इस गंभीर कमी की ओर आकर्षित किया. उन्होंने वायदा किया कि वह इस कमी को दूर करेंगे.

आज एक आम हिंदू सोचता है कि मुसलमानों ने इस देश के दो टुकड़े करवाए और वह उन्हें संदेह की दृष्टि से देखता है. कांग्रेस ने इस भ्रांति को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया. मैं कांग्रेस के नेतृत्व से अनुरोध करता हूं कि वह कांग्रेस की स्थापना के इस 125वें वर्ष में तो कम से कम स्वाधीनता संग्राम में मुसलमानों की भागीदारी को जनता के सामने लाए. इससे देश की एकता मज़बूत होगी.

(लेखक मुंबई स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म के संयोजक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... चिदंबरम और नक्सली! ...धीर

लोक निर्माण विभाग को मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष में 806 करोड़ रुपये के काम करने थे लेकिन लोक निर्माण विभाग ने मात्र 56 करोड़ रुपये के ही काम कराए हैं.

मनरेगा, जो मन में आए करो!

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार योजना (मनरेगा) ग़रीबों के लिए केंद्र सरकार की खास योजना है. लेकिन अधिकारियों ने इसे अपनी तरह से चलाने की मनमानी शुरू कर दी है. इस समय प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में जो आ रहा है वही, इस योजना के लिए भेजे गए फंड के साथ किया जा रहा है. हालांकि राहुल गांधी द्वारा इसमें हो रही लूट की ओर इशारा करने के बाद मायावती ने कुछ अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है. इससे कांग्रेस के आरोपों की सच्चाई अपने आप प्रमाणित हो जाती है. मनरेगा से जुड़े कुछ उदाहरण देखिए.

उन्नाव में मनरेगा के पैसे से 972 डिजिटल कैमरे ख़रीद लिए गए हैं. चित्रकूट, जो ग्रामीण विकास मंत्री दद्दू प्रसाद का ज़िला है, में भी 700 कैमरों की ख़रीदारी दिखाई गई है. महोबा में 247 आलमारी, बांदा में दो करोड़ रुपए की मेज–कुर्सी, सिद्धार्थनगर में 1,210 शिक़ायत पेटिकाओं की ख़रीददारी भी मनरेगा के पैसे से की गई है.

कानपुर देहात में तो कमाल ही हो गया जहां दलितों में वितरित करने के लिए ढाई करोड़ रुपये का सब्जी का हाईब्रिड बीज ख़रीद डाला गया. महाराजगंज में एक एनजीओ को 50 लाख रुपये प्रचार–प्रसार के लिए दे दिए गए. औरेया में 55 लाख के ट्री–गार्ड ख़रीदे गए, पर मौक़े पर एक भी नहीं मिला. गोंडा में मनरेगा गाइड लाइन के विपरीत तीन साल में 17 करोड़ रुपये की ख़रीदारी की गई. एक करोड़ का तो सिर्फ़ खिलौना ख़रीदा गया. 50 लाख के बाल्टी–मग, 75 लाख की बांस बल्ली जैसी चीजों की ख़रीद के बावजूद कोई बड़ा अधिकारी इस बर्बादी की ओर गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है. कांग्रेस मनरेगा सेल के संयोजक संजय दीक्षित व प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी ने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनरेगा में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजने की जो बात कह रही हैं वह सिर्फ़ दिखावा है. अगर उनमें ज़रा भी नैतिकता हो तो इन प्रकरणों में कार्रवाई करें. वह केवल बातें करती रहती हैं. बाराबंकी में इंदिरा नहर पर मनरेगा के तहत हो रहे काम को इस समय भी देखा जा सकता है जहां नहर की पटरी की मरम्मत के नाम करोड़ों के वारे– न्यारे हुए हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह की मांग हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की सेवाएं समाप्त होनी चाहिए और उनके द्वारा किए गए घपलों की वसूली उनके वेतन से होनी चाहिए. भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को आमतौर पर निलंबित भर किया जाता है और कुछ दिन बाद उसकी तैनाती अन्यत्र कर दी जाती है किंतु निलंबन कोई दंड नहीं है. लोक निर्माण विभाग को मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष में 806 करोड़ रुपये के काम करने थे लेकिन लोक निर्माण विभाग ने मात्र 56 करोड़ रुपये के ही काम कराए हैं. वर्ष 2009–10 में लोक निर्माण विभाग को डा. अंबेडकर ग्राम विकास योजना, तटबंध, पटरी, पुलिया आदि के कार्य मनरेगा से कराने के लिए 800 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था. विभिन्न कार्यों के लिए विभाग के 20 खंडों के मनरेगा से जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है उसमें से भी 10 फ़ीसदी से ज़्यादा नहीं ख़र्च की गई है. इनमें निर्माण खंड बिजनौर व गौतमबुद्धनगर में तो बिल्कुल काम नहीं हुए. काम में इस तरह की लापरवाही पर विभागीय अभियंताओं के अपने तर्क हैं. वे कहते हैं कि उच्च स्तर से लक्ष्य चाहे जो तय कर दिया जाए, सच्चाई यह है कि विभाग से कोई कार्य कराना ही नहीं चाहता है.

काग़ज़ों की बाज़ीगरी में उत्तर प्रदेश का प्रशासन सुर्ख़ियों में रहा है. अपनी तिकड़म से इसने काग़ज़ों में एक साल में 51 हज़ार शिक्षित बेरोज़गार घटाएं हैं.

राजधानी लखनऊ तथा मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपदों में मनरेगा के अंतर्गत लघुसिंचाई, वन, उद्यान, लोक निर्माण, कृषि, रेशम, मत्स्य, पंचायती राज तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में फरवरी ख़र्च के आंकड़े भी सरकार की कलई खोल देते हैं.

मनरेगा में रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति से चिंतित मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि मनरेगा में जो रिश्वत ले और योजना का पैसा ख़ुद खाए ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए लेकिन अभी मनरेगा में घोटाला करने वाला एक भी अधिकारी/कर्मचारी जेल नहीं भेजा गया है. स्वागतयोग्य एक काम यह ज़रूर हुआ है कि न्यायपालिका ने स्वयं सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पण की पहल करके बुंदेलखण्ड के बांदा जनपद में ज़िला जज सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ग्राम्य पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जागरूकता का ज़िम्मा लिया है. इतना ही नहीं गांवों में ही लोक अदालत लगाकर इससे संबंधित समस्याएं भी निस्तारित की जा रही हैं.

राहुल के निशाने पर मनरेगा की कार्यप्रणाली

मनरेगा के तहत सुलतानपुर जनपद में काम करने वाला स्वयं सेवी संगठन 88 लाख रुपये लेकर ग़ायब है. एक लाख 23 हज़ार जॉब कार्ड में केवल 11495 मज़दूर परिवारों को सौ दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया जा सका है. इन तथ्यों के सामने आते ही स्थानीय सांसद तथा कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ज़िलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता करते हुऐ बिफर पड़े. राहुल गांधी ने मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गहरी नाराज़गी व्यक्त की. मनरेगा योजना से जुड़े धन आवंटन में अनियमितता के एक मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की एक कमेटी से जांच कराने का निर्णय सुनाया तो ज़िला अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति में बतौर सदस्य उपस्थित बसपा प्रतिनिधियों ने विरोध जताया. मनरेगा और ग़रीबों को आवास के मसले पर भी कांग्रेस और बसपा सदस्यों के बीच विवाद हुआ. मनरेगा योजना को लेकर राहुल गांधी की नाराज़गी की वजह केवल दस फ़ीसदी लोगों को रोज़गार मिलना है. जब राहुल गांधी ने मनरेगा पर कड़ा रुख़ अपनाया तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने भी मनरेगा के क्रियान्वयन में अनियमितता की शिक़ायतों पर कार्रवाई का साहस दिखाया. उन्होंने चित्रकूट और सुल्तानपुर जनपदों के तत्कालीन ज़िलाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा जनपद महोबा एवं चित्रकूट के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने जनपद सुल्तानपुर के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी को आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही करने तथा जनपद गोण्डा, बलरामपुर, महोबा, सुल्तानपुर तथा चित्रकूट के अन्य दोषी अधिकारियों को निलंबित करते हुए जांच के निर्देश जारी किए हैं. मायावती ने कहा है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि मनरेगा के तहत अवस्थापना एवं विकास कार्यों को पूरी ईमानदारी से अंजाम दें. उन्होंने कहा कि ग़रीबों के रोज़गार से जुड़ी इस योजना में प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेगी.

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रत्येक तहसील स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के अनुश्रवण के लिए निगरानी समिति गठित की गई थी. इसके अलावा समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा भी स्थलीय भ्रमण करके मनरेगा के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों के निरीक्षण की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री ने मनरेगा एवं अन्य विकास कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन के भी आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिक़ायतों की जांच कराई गई. जांच के फलस्वरूप जनपद गोण्डा के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्री राज बहादुर को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त परियोजना निदेशक श्री जी.पी0.गौतम, नाज़िर/सहायक लेखाकार श्री सुधीर कुमार सिंह, लेखाकार श्री अवधेश कुमार सिंह तथा संख्या सहायक श्री दुर्गेश मिश्रा को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

The Ormita Commerce Network has entered the Indian marketplace

Ormita provides a mechanism for business owners to turn their excess capacity into needed goods and services. It supplements existing cash income and provides a way to offset costs against new sales. If your business is not at 100% capacity all of the time then you have an opportunity to increase your revenue and reduce your current cash costs.

How It Works

Ormita acts as a clearinghouse for the trade of excess capacities, goods and services - much like an alternative commodity exchange.

Participants buy and sell their excess capacity and/or stock in return for already budgeted expenses, new investments, cash-flow enhancing products, professional services and donations.

Rather than promoting direct trade between participants the Company brokers transact through its centralized marketplace.

1. Transactions are detailed in a centralized "ledger" which records the value of the items purchased (debit) and sold (credit) - much like a clearinghouse does for stocks, or a commercial bank does for cheques.
2. This ledger system utilises a "credit" as a method of accounting with 1 Ormita Credit = 1 Cash Rupee.
3. Just like any brokerage firm, Ormita receives a cash commission on each transaction.
4. Buyers pay no transaction fees to Ormita but they may pay a small percentage of the entire purchase price in cash to the seller. This cash covers the sellers' fees, sales tax and their additional costs to create this new sale.

A Unique Offering

- 24 hour, 7 day a week live brokerage services.
- Buy, sell and transfer funds online.
- No monthly fees and no annual fees.
- Lowest overall price in the industry.
- No cash outlay until we have met both your buying and selling needs.

[1] Subject to customer meeting minimum trading volumes per month.

For more information about Ormita and franchises.

Website:
www.ormita.co.in
Offices:
(011) 433 55 555
Email:
info@ormita.co.in
Blog:
blog.ormita.co.in
Facebook:
www.facebook.com/pages/Ormita-India/370208677506
Twitter:
twitter.com/ormitaindia

Ormita®
Commerce Network

मुस्लिमों के कल्याण के लिए सरकार के किसी भी क़दम के विरोध में पहला तर्क यही दिया जाता है कि हमारा संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण की इजाज़त नहीं देता.

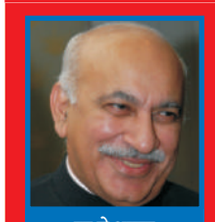

एम जे अकबर

यूपीए युवावस्था के मुहासों से परेशान है

साल 2010 अभी अपने युवावस्था में ही है. केंद्र सरकार के चेहरे पर अचानक नज़र आने लगे मुहासों की वजह भी कहीं यही तो नहीं है? यह न तो लाइलाज है और न ही ज़्यादा गंभीर. बस एक छोटी सी चाहत कि इस खुजलाहट और धब्बे वाले चेहरे के बिना ज़िंदगी शायद ज़्यादा आसान और हसीन होती. जनवरी तक सरकार बिल्कुल सेहतमंद और चाक-चौबंद नज़र आ रही थी, लेकिन मार्च आते-आते उसके क़दम लड़खड़ाने लगे और कम से कम एक वाकया ऐसा भी हुआ, जब लगा कि उसके पैर केले के छिलके पर फिसल गए हैं. अप्रैल में सरकार ने सावधानी भरा रुख़ अपनाया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अनिवार्य शिक्षा की ख़ूबियों को बताने के लिए देशवासियों से रूबरू हुए. हालांकि अनिवार्य शिक्षा के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता छह दशक पहले ही ज़ाहिर कर चुके थे और इसे बहुत पहले ही कार्यरूप में परिणित हो जाना चाहिए था. हमें फिर भी प्रधानमंत्री की सराहना करनी चाहिए. आख़िर वह मूलत: एक शिक्षक हैं और उनकी गंभीरता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमें आश्चर्य उनका भाषण तैयार करने वाले लोगों पर होता है. वही पुराने, घिसे-पिटे मुहावरों के अलावा क्या वे नए विचारों, नई संभावनाओं और बदलाव की दिशा में नहीं सोच सकते? ज़रा सोचिए, मौजूदा माहौल में शिक्षा के प्रसार में मोबाइल फोन एक क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है. एक तो ज़रूरत और दूसरा इसका क्रेज मोबाइल फोन को दूरदराज के ग्रामीण इलाक़ों तक पहुंचा रहा है. मोबाइल फोन में उपलब्ध सुविधाओं में एसएमएस का अहम स्थान है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए साक्षर होना ज़रूरी है. यदि आधुनिक तकनीक को बाज़ार की ज़रूरत के अनुरूप ढाला जा सके तो विकास का नया मॉडल तैयार हो सकता है.

देश के नाम इस संबोधन से कहीं सोनिया गांधी का कोई रिश्ता तो नहीं है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के रास्ते अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में उनके प्रवेश की मंशा का असर कहीं मनमोहन सिंह के भाषण में नज़र तो नहीं आता. श्रीमती गांधी पिछले दो आम चुनावों में कांग्रेस की जीत की नायिका रही हैं, पार्टी अध्यक्ष और संसद में एक सामान्य सदस्य की तरह बैठने वाली सोनिया की वास्तविक हैसियत इससे कहीं ज़्यादा है. यूपीए के पहले शासनकाल में उन्होंने एनएसी को सामाजिक क्षेत्र के लिए नीति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया. एनएसी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही नीतियों को सरकारी स्तर पर आगे बढ़ाया जाता था. इसके पीछे छुपी मंशा यह थी कि मनमोहन सिंह एक अराजनीतिक प्रधानमंत्री हैं और उन्हें राजनीतिक धरातल पर सहयोग की ज़रूरत है. एनएसी के माध्यम से सोनिया अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री को वही सहयोग उपलब्ध कराती थीं. हालांकि ऐसी व्यवस्था में अक्सर संबद्ध पक्षों का स्वाभिमान आड़े आ जाता है, लेकिन मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्हें देखकर व्यक्तिगत अहम या स्वाभिमान का एहसास भी नहीं होता.

मनमोहन का स्वाभिमान अभी भी कहीं नज़र नहीं आता. अब यह बात और है कि यूपीए की पहली पारी में उनके भाग्य से छींका भले टूटा हो, लेकिन गठबंधन के दूसरे शासनकाल में उनकी हैसियत के बारे में कोई शक नहीं रह गया है. समस्या सिर्फ़ यह है कि उनकी सरकार अक्सर बेवजह उपजी समस्याओं में फंस जाती है. स्वभाव से सौम्य मनमोहन अब नौकरशाहों के साथ तो कड़ाई से पेश आने लगे हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों के साथ पेश आने में वह पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं. एनएसी की दूसरी पारी से सोनिया की राजनीतिक हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी हैसियत को तो किसी ने चुनौती दी ही नहीं थी. लेकिन एनएसी का दोबारा गठन प्रधानमंत्री के कमज़ोर होने का एहसास ज़रूर दिलाता है. इसकी वजह यह है कि छह साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्हें ऐसी मदद की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी. राजनीति में वास्तविकताएं कभीकभार ही सामने आती हैं. ऐसे में जो सामने दिखता है, लोग उसी को सच्चाई मान लेते हैं. दिल्ली के राजनीतिक हलकों में शारीरिक भाषा को पढ़ने में लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता. कैबिनेट की बैठकों में मंत्रियों की ग़ैर मौजूदगी की शिक़ायत प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं. ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण बैठकों से नदारद रहने वाले मंत्रीगण कहीं और देशसेवा में लगे हैं. उन्हें तो अपनी ज़िम्मेदारियों की कोई फ़िक्र ही नहीं है. लेकिन क्या वे सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठकों से नदारद रहने की हिमाकत कर सकते हैं?

प्रधानमंत्री इससे ख़फ़ा हैं कि भारत-अमेरिका संबंध, पाकिस्तान के साथ शांति और आर्थिक सुधार के जिन तीन मुद्दों पर उन्होंने मज़बूती से क़दम आगे बढ़ाए, उनकी गति अचानक रुक गई है. आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत को अंगूठा दिखा दिया और अमेरिका एवं चीन उसकी मदद के लिए आगे आ गए. बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह के लिए शाही डिनर का आयोजन किया, लेकिन रणनीतिक बातचीत पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कयानी के साथ की. चीन ने भारत को सलाहें तो ख़ूब दीं, लेकिन और कुछ नहीं. जबकि पाकिस्तान को 82 प्रतिशत लोन सुविधा के साथ दो परमाणु प्लांटों का तोहफ़ा दिया. अब वह 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर ईरान गैस पाइप लाइन को पाकिस्तान होते हुए आगे बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहा है. मनमोहन सिंह ने वाशिंगटन को ख़ुश करने के लिए ईरान-पाक-भारत गैस पाइप लाइन परियोजना से अपने हाथ खींच लिए, लेकिन इस्लामाबाद ऐसे किसी ख़ौफ़ से दूर है.

आर्थिक सुधारों की राह में अड़ंगा लगाने के लिए प्रधानमंत्री पांच साल तक वामदलों को जिम्मेदार बताते रहे. वामदल आज भले ही हाशिए पर हैं, लेकिन आर्थिक सुधार कहां हैं? एक राजनीतिक दल की हैसियत से जनभावनाओं को समझते हुए कांग्रेस ने सरकार के परमाणु उत्तरदायित्व विधेयक के ख़िलाफ़ छुपा अभियान चला दिया है. यह विधेयक पहले ही भारतीय संसद और अमेरिकी परमाणु उद्योग के दो पाटों के बीच पिस रहा है. एनएसी का दोबारा गठन संगठन और सरकार के बीच की दूरी की ओर इशारा करता है. संगठन का सारा उद्देश्य जहां अगले चुनावों में जीत हासिल करना है, वहीं सरकार का सारा ध्यान शासन चलाने पर है. ख़ुद सोनिया गांधी द्वारा चुने गए एनएसी के सदस्य एक पोलित ब्यूरो की तरह काम करेंगे. वे लोकलुभावन नीतियों की रूपरेखा तैयार करेंगे और फिर उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे.

2014 के आम चुनावों के लिए अभी से चिंता करना कहीं सोनिया की जल्दबाज़ी तो नहीं है? वह दरअसल आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की खाई को पाटना चाहती हैं. महिला आरक्षण विधेयक पर मचे हल्ला-हंगामे से पार्टी तो मज़बूत हुई, लेकिन सरकार कमज़ोर हो गई. कहावतें बोलने में उस्ताद लालू यादव ने कह दिया कि लाश को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए चार लोग ही काफी होते हैं और उनके पास चार सांसद हैं. सरकार को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन एक अनिश्चितता का माहौल तो बन ही गया है, जिसे विपक्षी दल सदन की अगली बैठकों में भुनाने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी कमज़ोरी को पहचान कर उसके लिए तैयारी करने में जल्दबाजी जैसी कोई बात नहीं होती.

अमिताभ बच्चन वाले मामले में भी कांग्रेस केले के छिलके पर फिसल गई. लोग हंसते रहे और पार्टी बयान पर बयान देती रही. जब चेहरे पर मुहासों की टीस कहीं अंदर महसूस हो रही हो तो अक्सर छोटी बातें भी बुरी लग जाती हैं, जबकि एक छोटी सी मुस्कान किस्से को वहीं ख़त्म कर सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

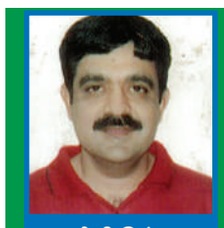

योगी सिकंद

कोटा नहीं तो कैसे उठेंगे पिछड़े मुसलमान?

जैसा कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई अनेक कमेटियां, जिनमें सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग सबसे प्रमुख हैं, पहले ही बता चुकी हैं कि देश की मुस्लिम जनसंख्या विकास के अधिकांश सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर सबसे निचले पायदान पर खड़ी है. मुस्लिम समुदाय के अंदर पिछड़ी जातियां, जो कुल जनसंख्या की क़रीब 80 प्रतिशत हैं, की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है. लगातार अवहेलना और सरकारी भेदभाव ने देश की इतनी बड़ी आबादी को इस हाल में जीने पर विवश कर दिया है. ऐसी हालत में दलित और अन्य पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों के हित में सरकार द्वारा सद्भावनापूर्ण पक्षपात की नीति की ज़रूरत को कम करके नहीं आंका जा सकता. लेकिन कितनी निराशा की बात है कि आज जब इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है तो चारों ओर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं.

आज अमेरिका हम भारतीयों के लिए रोल मॉडल बन चुका है. हर अमेरिकन चीज की नकल करने में हमारा शासक वर्ग भी गर्व का अनुभव करता है. लेकिन कितनी ताज्जुब की बात है कि वही शासक वर्ग अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के हित में उठाए जा रहे ऐसे क़दमों से आंखें मूंद लेता है. और इतना ही नहीं, समाज के पिछड़े लोगों के हित में उठाए जाने वाले हर क़दम, चाहे वह कितने भी छोटे क्यों न हों, के विरोध में उठ खड़ा होता है.

मुस्लिमों के कल्याण के लिए सरकार के किसी भी क़दम के विरोध में पहला तर्क यही दिया जाता है कि हमारा संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण की इजाज़त नहीं देता. यदि ऐसा है तो फिर हाल के दिनों तक देश में पिछड़ी जातियों को मिले आरक्षण का लाभ केवल हिंदू दलित ही क्यों उठा रहे थे?

इस परिप्रेक्ष्य में ऊंची जातियों के कुछ मुस्लिम राजनीतिज्ञों और इस्लामिक संस्थाओं द्वारा पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करना भी हैरान करने वाला है. मुसलमानों की पिछड़ी जातियों से संबंध रखने वाले कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह मांग मान भी ली गई तो उन्हें इसका फ़ायदा नहीं होगा. सारा फ़ायदा केवल ऊंची जातियों के मुसलमानों को होगा, जो शैक्षणिक और राजनीतिक धरातल पर दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं. वे इस बात को मानने से भी इंकार करते हैं कि कमज़ोर मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था से मुसलमान समुदाय बंट जाएगा. उनका कहना है कि आरक्षण विरोधियों का यह तर्क तब पूरी तरह जायज़ है कि किसी भी तरह का आरक्षण समाज को बांटने का काम करता है और इसलिए राष्ट्रीय हित के ख़िलाफ़ है. अन्य पिछड़ी जातियों के मुसलमानों के लिए आरक्षण के विरोध में अक्सर यह सुनने में आता है कि पहले से मौजूद ओबीसी कोटे का फ़ायदा वे उठा सकते हैं और उनके लिए अलग से आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन सच्चाई यह है कि विकास की दौड़ में ओबीसी हिंदुओं के मुक़ाबले ओबीसी मुसलमान ज़्यादा पिछड़े हैं. सरकारी स्तर पर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ भेदभाव के चलते वे मौजूदा ओबीसी कोटे का फ़ायदा नहीं उठा पाते. पिछड़ी जातियों के मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए आज समय की ज़रूरत बन गई है. लेकिन समस्या यह है कि देश का शासक वर्ग समाज के कमज़ोर तबकों के हित में उठाए जाने वाले किसी भी क़दम के विरोध में एक साथ उठ खड़ा होता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था के निजीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में कई ऐसे परंपरागत उद्योग-धंधे और व्यवसाय पूरी तरह पृष्ठभूमि में चले गए हैं, जो दलित और ओबीसी मुस्लिम समुदाय के जीवन का आधार थे. इन उद्योग-धंधों के चौपट होने का नतीजा यह रहा कि कई परिवार आज भुखमरी की हालत में जीने पर विवश हैं. इसे देखते हुए समाज के इस वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था करना और भी आवश्यक हो गया है. लेकिन यह व्यवस्था यदि केवल सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों तक ही सीमित हो तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि सरकारी नौकरियां पहले ही लगातार कम होती जा रही हैं. समाज से दूर अपराधियों की तरह हिंसा के बीच जीवन बिताने को मजबूर यह समुदाय अंदर से आहत है और ख़फ़ा भी. इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि इसे समाज से दोबारा जोड़ने और सशक्तिकरण के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाएं. दलित और ओबीसी मुस्लिम की हालत में सुधार पूरे मुस्लिम समाज के कल्याण से जुड़ा अहम मुद्दा है. और, केवल बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आज ज़रूरत है कि सरकार खुले तौर पर दलित और ओबीसी मुसलमानों के कल्याण के लिए आगे आए और उनकी समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करे.

(लेखक नेशनल लॉ स्कूल बंगलुरू से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

औरत सब कुछ कर सकती है

29 मार्च-04 अप्रैल अंक में प्रकाशित आवरण कथा-लीडर भी बनेंगी और लीडर पैदा भी करेंगी के अंतर्गत महिला लेखकों-विचारकों ने काफी सधी भाषा में एक गंभीर मुद्दे पर उचित राय वयक्त की है. मुस्लिम महिलाओं की दशा-दिशा पर एक साथ इतने आलेख प्रकाशित कर चौथी दुनिया ने विषय के हर कोण को सामने लाने का प्रयास किया है. सच भी है कि आदमी को जन्म औरत ही देती है, मां के रूप में वह उसकी पहली पाठशाला भी होती है. जब वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, खिलाड़ी, राजनेता, समाजसेवी, सैनिक और लेखक पैदा कर सकती है तो खुद क्यों नहीं बन सकती? समाज को अपना दकियानूसी रवैया त्याग कर समय की चाल को समझना चाहिए.

-मोहम्मद आदिल, *बरेली, उत्तर प्रदेश*

गंभीर विषयों की चर्चा होनी चाहिए

यह देखकर अच्छा लगता है कि आप हर अंक में एक खास विषय पर चर्चा आरंभ कराते हैं. इस समय जब दूसरी तमाम पत्रिकाएं समाज की रंगीनियों को छापने में होड़ करते हैं तो चौथी दुनिया समाज और आम आदमी से जुड़े किसी गंभीर विषय पर पहल करता है और पाठकों के बीच अनेक सवाल छोड़ देता है. इस बार आपने मुस्लिम समाज के सबसे ज्यादा सताई जाने वाली महिलाओं के बारे में लिखकर चर्चा चलाई है. हम चाहते हैं अगर साहस हो तो कि इस समाज के मौलानाओं को महिलाओं के राजनीति में आने और नहीं आने को लेकर खुली और तर्कपूर्ण चर्चा करें.

-मो. तस्लीम, *दरभंगा, बिहार*

ज़िम्मेदार कौन?

डॉ. मंज़ूर आलम का आलेख-औरतों को मुक़ाम समाजी और सियासी दोनों है (29 मार्च-04 अप्रैल) पढ़ने का मौका मिला. लेखक ने बहुत बेबाकी से समाज में औरत की हालत बयान की. सच भी है, जो औरत हमें जन्म देती है और जीवनसाथी के रूप में मरते दम तक साथ देती है, वह कितना बदहाल जीवन जीती है. उसे बराबरी का दर्जा देने में हमारे कदम इतना हिचकते क्यों हैं? इस दुनिया में सभी को सम्मान से जिंदगी बिताने का हक है, लेकिन औरतें इस अधिकार से वंचित हैं. आखिर क्यों? हमें यह कहने में हिचक क्यों हो रही है कि इसके लिए मुस्लिम समाज के कठमुल्ले धार्मिक नेता जिम्मेवार हैं.

-मनोज कुमार सिंह, *मोतिहारी, बिहार*

परमाणु दायित्व विधेयक

29 मार्च-04 अप्रैल के अंक में तोप मुकाबिल के तहत आपने न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल के संदर्भ में जो सवाल उठाए हैं, वे जनहित से जुड़े हैं. सरकार न जाने किस राह चल पर रही है? उसे देश-जनता की कोई परवाह भी है, ऐसा कहीं से नहीं लगता. देश के अंदर-बाहर बस समझौते ही समझौते. उद्देश्य का कहीं कोई पता नहीं. परिणाम की किसी को कोई चिंता नहीं. ऐसा आखिर कब तक चलेगा?

-राजीव खंडेलवाल, *ई-मेल से*

नेपाल और कोइराला

कोइराला के बाद नेपाली कांग्रेस का भविष्य (05-11 अप्रैल) आलेख पढ़ा. लेखक अच्युत वागले ने बड़ी बारीकी से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के व्यक्तित्व और भारत एवं अन्य देशों के साथ उनकी परस्पर मैत्री पर प्रकाश डाला. जीपी कोइराला एक अच्छे राजनेता थे. नेपाल को अस्थिरता से मुक्ति दिलाने और वहां अमन-चैन कायम करने की दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयास जगजाहिर हैं.

-राजबहादुर, *डाबड़ी मोड़, नई दिल्ली*

ममता बनर्जी की राजनीति

05-11 अप्रैल के अंक में बिमल राय का आलेख-मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी दूर है, रेलमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाओं का सटीक विश्लेषण है. पश्चिम बंगाल के लिए दिल खोल कर दिखाई गई उदारता इसी बात का प्रमाण है कि ममता को मुख्यमंत्री पद पर विराजने की कितनी हड़बड़ी है. उनकी अधिकतर परियोजनाएं राज्य विशेष को समर्पित हैं. जबकि सच तो यह है कि वह देश की रेलमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की नहीं. किसी भी केंद्रीय मंत्री को देश के सभी राज्यों के प्रति समान रवैया रहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य तो यही है कि ऐसा होता नहीं है. इसके लिए केवल ममता बनर्जी को ही दोष क्यों दें? दूसरों ने भी यही किया है. लेकिन मुख्यमंत्री बनने की चाहत में ममता बनर्जी ज्यादा जल्दी में लगती है.

-दुर्गाशंकर तिवारी, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश*

आरुषि हत्याकांड: फाइल बंद

चौथी दुनिया में प्रकाशित आरुषि वाला आलेख पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे देश में गणतंत्र नहीं है, बल्कि राजतंत्र, धनतंत्र, पुलिस और गुंडातंत्र है. पुलिस और सीबीआई अगर कुछ करने लायक है ही नहीं, तो उन पर करोड़ों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है? एक बात और भी साफ है कि देश में प्रशासन की हर क्षेत्र में विफलता और नाकामयाबी का असली कारण भ्रष्ट व्यवस्था है. जब तक यह स्थिति नहीं बदलती, तब तक अपराध बढ़ते रहेंगे और घोटाले होते रहेंगे. आम आदमी ऐसे ही परेशान होता रहेगा. आखिर जनता कब तक लाचार होकर चुपचाप देखती रहेगी?

-सीताराम शर्मा, *भूमिबाड़ा, सीकर, राजस्थान.*

अखबार जरा हटके है

बहुत दिनों से इच्छा थी कि हिंदी में कोई ऐसा अखबार निकले, जो औरों से ज़रा हटके हो. इस अखबार की साजसज्जा और छपाई देखकर मन ख़ुश हो गया. इसकी क़ीमत भी वाजिब है. पर अख़बार अनेक जगहों पर उपलब्ध नहीं है. इसका एक अंक मैं गुड़गांव गया था तो वहीं से खरीदा. इसमें आम जनता की समस्याओं पर भी कालम छपने चाहिए.

-नवीन कुमार शर्मा, *हिंदमोटर, हुगली.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें . संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11 नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कांग्रेस जुआ न खेले तो अच्छा

कांग्रेस को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. बजट सत्र के इस द्वितीय चरण में उसके सामने ख़तरा पैदा हो सकता है. महिला आरक्षण बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा में पास होना है. श्रीमती सोनिया गांधी का स्पष्ट निर्देश है कि इसे हर हालत में पास कराना है. उन्हें वृंदा करात, सुषमा स्वराज जैसी शुभचिंतकों ने समझा दिया है कि वह इतिहास में अमर हो जाएंगी. अगर यह बिल उन्होंने पास करा दिया तो उनका नाम लेनिन और माओ की तरह याद किया जाएगा. लेकिन यही महिला नेत्रियां महिलाओं को पुरुषों के बराबर रोज़गार के अवसर मिलें और उन्हें आर्थिक आज़ादी मिले, इस बारे में कोई क़दम नहीं उठाना चाहतीं. क्यों नहीं कांग्रेस भाजपा और सीपीएम के साथ मिलकर देश की सभी, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट, नौकरियों में महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण का क़ानून बनाती?

दरअसल दोनों महिलाओं ने कांग्रेस को अपने जाल में उलझा लिया है. महिला आरक्षण बिल जब पास होगा, तब पास होगा, पर उससे पहले कांग्रेस ने अपने कुछ साथियों को ख़ुद से दूर कर दिया है. मुलायम सिंह, लालू यादव और मायावती इस बिल पर कांग्रेस के साथ नहीं हैं. भाजपा चाहती है कि यह दूरी इतनी बढ़ जाए तथा मनमुटाव इतना हो जाए कि ये फाइनेंस बिल पर कटौती प्रस्ताव लाएं और उस समय भाजपा तथा सीपीएम इनके साथ मिलकर वोट कर दें. उस स्थिति में सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव होंगे.

मध्यावधि चुनाव की बात केवल अटकलबाज़ी नहीं है. इस ख़तरे को कांग्रेस में सबसे ज़्यादा अगर कोई समझता है तो वह हैं मनमोहन सिंह, जो चाहते हैं कि सरकार चले. वह शायद इस पक्ष में भी हैं कि अगर टालना हो तो टाल दिया जाए. जब लोग तैयार हो जाएं या कोई सहमत हल निकल आए, तभी इसे चर्चा के लिए रखा जाए और वोटिंग हो. लेकिन क्या करेंगे उन रिपोर्टों का, जो कांग्रेस अध्यक्ष के पास भेजी जा रही हैं. एक रिपोर्ट कहती है कि देश की सारी महिलाएं कांग्रेस को वोट करेंगी और पार्टी चार सौ से ज़्यादा सीटें जीतेगी. दूसरी रिपोर्ट कहती है कि देश का सारा युवा वर्ग राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को वोट देगा तथा जो भी कसर होगी, उसे नौजवान पूरा करेगा.

हो सकता है, ये रिपोर्ट सही हों. लेकिन ऐसी रिपोर्ट पर जब चुनाव हुए, तब नतीजा बहुत अच्छा नहीं निकला. राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की सरकार गिराकर इस आशा में चुनाव कराया था कि उन्हें बहुमत मिलेगा, पर दुर्भाग्यवश वह उनके जीवन का अंतिम चुनाव साबित हुआ. उनके निधन के कारण दो चरणों में चुनाव हुए. जब नतीजे आए तो पता चला कि उनके निधन से पहले के मतदान में उनकी पार्टी बुरी तरह हारी थी, लेकिन निधन के बाद वाले मतदान क्षेत्रों में वह बड़ी संख्या में जीते. इसका मतलब कि अगर उनका निधन नहीं हुआ होता तो कांग्रेस वह चुनाव हार जाती. इसके बाद भी नरसिंहाराव को पूर्ण बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री पद का सुख नहीं मिला, उन्हें अल्पमत की सरकार ही चलानी पड़ी.

अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शाइनिंग इंडिया के मोह में पहले चुनाव कराया और भाजपा बुरी तरह चुनाव हार गई. भावी प्रधानमंत्री आडवाणी के नाम पर भी भाजपा हारी. और, अब यह जुआ कांग्रेस खेलना चाहती है. न खेले तो अच्छा.

कांग्रेस के पास कुछ ऐसी ख़ामियां हैं, जिन्हें वह दूर करना ही नहीं चाहती. बिहार और उत्तर प्रदेश इसके उदाहरण हैं. बिहार में कांग्रेस को वोट मिल सकते हैं, वहां की दलीय स्थिति में लोग दिग्भ्रमित हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है. जब अध्यक्ष पद के लिए कोई चेहरा नहीं है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर वहां अंधेरा ही अंधेरा है. चौथे नंबर पर आने वाली पार्टी इस तरह लड़ रही है, मानों उसे ही विधानसभा चुनाव में कमान संभालनी है.

उत्तर प्रदेश में केवल दो नाम नज़र आते हैं संजय सिंह और राजबब्बर. संजय सिंह को दस जनपथ यह ज़िम्मेदारी देना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व न बना लें. दूसरी ओर राजबब्बर यह ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते. राजबब्बर की फिरोज़ाबाद सीट से जीत के बाद उनका कद उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है. वह डरते हैं कि यदि उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली तो सब उनके सिर आ जाएगा.

उत्तर प्रदेश की भी यही कहानी है. मौजूदा अध्यक्ष सब कर रही हैं, जी–जान लगा रही हैं, लेकिन असर नहीं छोड़ पा रही हैं. अब राहुल गांधी की रथ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है. न पार्टी में नेता हैं और न रणनीति बनाने वाले. इस रथ यात्रा के बाद पैदा हुई पूंजी को सहेजेगा कौन?

उत्तर प्रदेश में केवल दो नाम नज़र आते हैं संजय सिंह और राज बब्बर. संजय सिंह को दस जनपथ यह ज़िम्मेदारी देना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व न बना लें. दूसरी ओर राजबब्बर यह ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते. राजबब्बर की फिरोज़ाबाद सीट से जीत के बाद उनका कद उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है. वह डरते हैं कि यदि उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली तो सब उनके सिर आ जाएगा.

जो भी इन प्रदेशों में कांग्रेस के पुर्नजागरण के बारे सोचता हो, उसे गंभीरता से सोचना चाहिए. लेकिन शायद जबसे राहुल गांधी ने कमान संभाली है, तबसे कोई सोचने के ख़तरे में पड़ना ही नहीं चाहता. जो राहुल गांधी करें, करें. इसका मतलब इन प्रदेशों में एक दल के नाते सारी पहल अब राहुल गांधी के हाथ में है.

कुछ महीने हुए, झारखंड के चुनाव हुए. इन्हीं कारणों से कांग्रेस अंदाज़ा लगा रही थी कि उसकी सरकार बनेगी, पर नहीं बन पाई. अब बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस से पिछड़े दूर हैं, कांग्रेस से दलित दूर हैं और कांग्रेस के पास मुसलमान वापस आने से हिचक रहे हैं. इन वर्गों से संवाद करने वाला कांग्रेस में कोई है ही नहीं. शायद राहुल गांधी इस तरीक़े को ही ग़लत मानते हैं. वह समझते हैं कि युवा एक वर्ग के नाते संगठित होकर उन्हें समर्थन देगा. हो सकता है, यह सही हो, पर अभी तो इस सोच में ज़्यादा दम नहीं दिखाई देता. राहुल गांधी से आशा करनी चाहिए कि वह समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं की गहराई को, उसके सही स्वरूप में समझेंगे. इसके बाद ही विभिन्न वर्गों का कांग्रेस से संवाद प्रारंभ हो पाएगा.

कांग्रेस बने या बिगड़े, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस देश में सरकार का नेतृत्व कर रही है और उसके साथ कई पुराने मूल्य जुड़े हैं, जिनमें देश के बहुत से लोगों को विश्वास है. देश में लोकतंत्र क़ायम रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सत्ता का हिस्सा बने दल लोगों की समस्याओं को उनके समाज के आधार पर समझें. अगर ऐसा नहीं होता तो दंतेवाड़ा में नक्सली हमला बार–बार दोहराया जाता रहेगा. हथियारों से युद्ध में दुश्मन को मारा जाता है, अपने ही देश में रहने वालों के साथ चल रहे संघर्ष को अगर हम युद्ध कहने लगें तो हम एक ओर लोकतंत्र के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और दूसरी ओर देश को बांटने में योगदान कर रहे हैं.

कांग्रेस को अपने संपूर्ण नज़रिए पर सोचना चाहिए और देश में रहने वालों को न केवल राजनैतिक, बल्कि सामाजिक समाधान देने में अपनी ताक़त लगानी चाहिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

पुण्यतिथि पर विशेष

ऐसे थे इक़बाल

जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग मेरी कविताएं पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और फिर कहेंगे, ख़ुद को पहचान कर उसने दुनिया को बदल दिया. यह कहना था मोहम्मद इक़बाल का. 9 दिसंबर, 1877 को अविभाजित भारत में सियालकोट के एक कश्मीरी परिवार में पैदा हुए इक़बाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा जैसे कालजयी गीतों के रचयिता इकबाल दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ और इस्लाम के बड़े विद्वान थे. 21 अप्रैल को उनकी 71वीं पुण्यतिथि है तो इस महान व्यक्तित्व के जीवन से जुड़े पहलुओं को याद करने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है.

मोहम्मद इक़बाल को मुख्य रूप से मिर्जा ग़ालिब की तरह एक संपूर्ण शायर एवं गीतकार के तौर पर याद किया जाता है. ग़ालिब की तरह ही उनकी कविताओं में भौतिक और प्राकृतिक तत्वों का ऐसा ख़ूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है कि कई लोग तो यह मानते हैं कि ग़ालिब की आत्मा इक़बाल की लेखनी में समाई हुई है. उर्दू आलोचक सैयद अब्दुल कादिर के मुताबिक, इक़बाल की पहली कविता साल 1901 में हिमालय शीर्षक से प्रकाशित हुई थी, जिसे काफ़ी शोहरत मिली. इसके बाद वह सूफ़ी शायर जलालुद्दीन रूमी के प्रभाव में आ गए और उनकी बाद की रचनाओं में रूमी का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है. लेकिन शायरी तो इक़बाल के व्यक्तित्व का एक पहलू भर है. सच तो यह है कि उनका व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसकी आभा और तेज के आगे, आने वाली कई पीढ़ियां अपना सिर झुकाने को मजबूर होंगी.

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह इक़बाल ही थे, जिन्होंने पाकिस्तान के गठन के लिए नैतिक और आध्यात्मिक जमीन तैयार की. 1930 में इलाहाबाद में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उन्होंने ही सबसे पहले ज़ोर देकर यह कहा था कि पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और बलूचिस्तान को मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण संभव है. हालांकि 1940 में लाहौर प्रस्ताव (जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है) के पास होने से दो साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह इक़बाल के प्रयासों का ही नतीजा था कि क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में देश के मुसलमानों में पाकिस्तान के गठन का जोश पैदा हुआ और तमाम त्यागों एवं बलिदानों के बाद इकबाल के सपनों का पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया.

मोहम्मद इक़बाल को मुख्य रूप से मिर्जा ग़ालिब की तरह एक संपूर्ण शायर एवं गीतकार के तौर पर याद किया जाता है. ग़ालिब की तरह ही उनकी कविताओं में भौतिक और प्राकृतिक तत्वों का ऐसा ख़ूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है कि कई लोग तो यह मानते हैं कि ग़ालिब की आत्मा इक़बाल की लेखनी में समाई हुई है.

हालांकि इक़बाल का दार्शनिक विचार पश्चिमी देशों और आधुनिक विज्ञान पर आधारित था, लेकिन वह पश्चिमी देशों में प्रचलित भौतिकवादिता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. उन्होंने कुरआन का गहराई से अध्ययन किया था और इस्लामिक संस्कृति में उनकी गहरी आस्था थी. पैगंबर मोहम्मद के प्रति उनके प्यार और विश्वास का ऐसा स्तर था कि उन्हें आशिके रसूल की उपाधि से नवाजा गया. उनकी शिक्षाओं और संदेशों में भी इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिलती है. मिस्र के मशहूर पत्रकार एवं लेखक मोहम्मद हुसैन का मानना है कि इक़बाल के संदेश केवल उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमान उनसे शिक्षा हासिल कर सकते हैं.

अल्लाह के प्रति अपनी आस्था जताते हुए इक़बाल ने कहा था कि कोई भी ऐसा इंसान जो खुदा को मानता है और उसकी नेमतों को क़बूल करता है, कभी भी निराश नहीं हो सकता. उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद अल्लाह उसकी रक्षा करने के लिए तैयार होता है. दरअसल, इक़बाल मुस्लिम समुदाय में नई जागृति, नया जोश पैदा करना चाहते थे. उन्हें नींद से जगाकर दुनियादारी की हक़ीक़तों से रूबरू कराना चाहते थे. अपने गीतों और शेरों में उन्होंने बार–बार यह कहा है कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है. यदि हमने थककर आगे बढ़ना छोड़ दिया तो हमारा अस्तित्व वहीं ख़त्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता अख्तियार करने की सलाह नहीं दी. उनका मकसद तो बस एक था–प्यार. सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ में उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के नजदीक पहुंचने का एकमात्र वाजिब तरीक़ा प्यार है. प्यार ही जीवन का आधार है और उद्देश्य भी. जावैदनामा में उन्होंने नई पीढ़ी के लिए कई व्यवहारिक सलाहें दी हैं. इक़बाल का कहना है कि आज के युवा पश्चिमी देशों के अंधानुकरण में ऐसे उलझ गए हैं कि उनकी अपनी पहचान ही खोती जा रही है. उनका मानना था कि पश्चिमी सभ्यता की नक़ल करने के बजाय हमें अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम दुनिया के लिए कुछ भलाई का काम कर सकें.

हालांकि इक़बाल की मौत हुए सात दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं. इस्लामी परंपराओं पर आधारित इत्तेहाद की उनकी अवधारणा में मौजूदा दौर की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान भी तलाशा जा सकता है. लेकिन हैरत की बात है कि आज जब इस्लाम ख़तरे में है, का नारा चारों ओर बुलंद किया जा रहा है, इक़बाल के संदेशों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शोध के मुताबिक़ , 25 प्रतिशत लड़के और 30 प्रतिशत लड़कियां दिन में तीन घंटे से ज़्यादा टीवी या कंप्यूटर पर वक़्त बिताते हैं.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सरकारी स्कूल

इमारतें जर्जर हालत में हैं, क्यों?

एक अप्रैल (मूर्ख दिवस) का दिन गंभीर नहीं माना जाता. इसी दिन केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार नाम से एक नया क़ानून लोगों को तोहफ़े में दिया है. क़ानून के मुताबिक़, छह साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा उनका मौलिक अधिकार होगा. इस क़ानून से क़रीब एक करोड़ ऐसे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. लेकिन, सवाल यह है कि इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या हमारे देश में स्कूलों की मौजूदा संख्या पर्याप्त है? हालत तो यह है कि अधिकांश प्राथमिक स्कूलों के पास अपनी इमारत तक नहीं है. बच्चे खुले मैदान या झोपड़ी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं. जहां इमारत है भी, वह साल-दो साल के भीतर ढहने लगती है. आख़िर इसकी वजह क्या है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आमतौर पर ऐसी शिक़ायतें आती हैं कि स्कूल बनाने के लिए जितना पैसा आता है, उसमें से आधा भी इस मद में ख़र्च नहीं किया जाता. प्रधानाध्यापक और ठेकेदार की मिलीभगत से कमज़ोर इमारत बनाकर बाक़ी पैसा हजम कर लिया जाता है. ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बाक़ी का पैसा सचमुच कहां चला जाता है, क्योंकि यह पैसा आपका है, जो टैक्स के रूप में आप सरकार को देते हैं और जिससे आपके बच्चों के लिए स्कूल की इमारत बन सकती है. इसलिए आप इसकी एक-एक पाई का हिसाब अधिकारियों से मांग सकते हैं. इस अंक में हम इसी से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप स्कूल इमारत बनने के लिए आए पैसों का हिसाब-किताब मांग सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान या सुझाव देने के लिए आपके साथ है. आप हमसे संपर्क कर सकते हैं.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेल:rti@chauthiduniya.com

सरकारी स्कूल की इमारत से संबंधित आवेदन

दिनांक :

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम...
पता...

विषय: सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

कृपया स्कूल (स्कूल का नाम और पता)..... से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं:

1. साल.....से साल.....के बीच उक्त स्कूल को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई? यह सूचना निम्न विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
   (क) राशि आवंटन का वर्ष.
   (ख) कितनी राशि आवंटित हुई.
   (ग) किस उद्देश्य/कार्य के लिए राशि आवंटित की गई.
   (घ) वास्तविक राशि, जो उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए खर्च की गई.
   (च) किस उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए उक्त राशि खर्च की गई.
2. पिछले दो सालों में उक्त स्कूल पर खर्च की गई रकम का ब्यौरा निम्न विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
   (क) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए राशि खर्च की गई.
   (ख) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य का पूर्ण विवरण.
   (ग) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत राशि.
   (घ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को करने की स्वीकृत देने की तिथि.
   (च) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य की वर्तमान स्थिति, कार्य पूरा हो गया या अधूरा है या अभी चल रहा है.
   (छ) उस एजेंसी का नाम, जो इन प्रत्येक उद्देश्यों/कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है.
   (ज) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य के शुरू होने की तारीख.
   (झ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य के पूरा होने की तारीख.
   (ट) एजेंसी को किस दर पर प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया.
   (ठ) एजेंसी को कितनी राशि दी जा चुकी है.
   (ड) कार्य के स्केच की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं.
   (ढ) कब और किस आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कार्य पूर्ण हो चुका है. उस निर्णय की एक कॉपी उपलब्ध कराएं.
   (त) उस सहायक अभियंता और अधीक्षण अभियंता का नाम बताएं, जिसने कार्य का निरीक्षण किया और एजेंसी को भुगतान करने के लिए अपनी सहमति दी. कार्य के कौन से हिस्से का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया.
3. पिछले एक साल में उक्त स्कूल पर खर्च की गई रकम का ब्यौरा निम्न विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
   (क) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए कितनी राशि खर्च की गई.
   (ख) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य का पूर्ण विवरण.
   (ग) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत राशि.
   (घ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को करने की स्वीकृत देने की तिथि.
   (च) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य की वर्तमान स्थिति, कार्य पूरा हो गया या अधूरा है या अभी चल रहा है.
   (छ) उस एजेंसी का नाम, जो इन प्रत्येक उद्देश्यों/कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है.
   (ज) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य के शुरू होने की तारीख.
   (झ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य के पूरा होने की तारीख.
   (ट) एजेंसी को किस दर पर प्रत्येक कार्य पूरा करने के लिए दिया गया.
   (ठ) एजेंसी को कितनी राशि दी जा चुकी है.
   (ड) कार्य के स्केच की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं.
   (ढ) कब और किस आधार पर यह निर्णय लिया गया. कि प्रत्येक कार्य पूर्ण हो चुका है, उस निर्णय की एक कॉपी उपलब्ध कराएं.
   (त) उस सहायक अभियंता और अधीक्षण अभियंता का नाम बताएं, जिसने कार्य का निरीक्षण किया और एजेंसी को भुगतान करने के लिए अपनी सहमति दी. कार्य के कौन से हिस्से का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया.

मैं दस रुपये का आवेदन शुल्क जमा कर रहा हूं.

भवदीय

हस्ताक्षर:
नाम:
पता:

ज़रा हट के

चुस्ती में भारतीय बालाएं नंबर वन

ख़ुद को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए लोग न जाने क्या-क्या नहीं करते. कोई जिम में घंटों पसीना बहाता है तो कोई दौड़ता है. कोई खेलकर तंदुरुस्त रहता है तो कोई बागवानी करके. इस काम में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं, बल्कि तंदुरुस्ती के मामले में वे दुनिया में सबसे आगे हैं. और, भारतीय बालाओं का इस मामले में कोई सानी नहीं है. यह कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का. उसके मुताबिक़, भारत की लड़कियां दुनिया भर में सबसे चुस्त हैं.

संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के लिए 13 से लेकर 15 साल तक की उम्र के 70,000 बच्चों की आदतों को देखा और उनका विश्लेषण किया गया. शोध से पता चला कि ज़्यादातर बच्चे व्यायाम नहीं करते या बहुत कम चलते-फिरते हैं. डब्ल्यूएचओ की रेजीना गूटहोल्ड का कहना है कि व्यायाम के सिलसिले में अमीर और ग़रीब देशों के बीच ख़ास फ़र्क़ नहीं है. ग़रीब देशों में पैदा होने का मतलब यह कतई नहीं है कि बच्चे ज़्यादा चलते-फिरते नहीं हैं. शोधकर्ताओं के मुताबिक़, बच्चों के लिए हफ्ते में एक घंटा व्यायाम करना ज़रूरी है. इस लिहाज़ से अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया और मध्य-पूर्व में केवल 25 प्रतिशत लड़के और 15 प्रतिशत लड़कियों द्वारा ही पर्याप्त व्यायाम किया जाता है.

शोध के मुताबिक़, 25 प्रतिशत लड़के और 30 प्रतिशत लड़कियां दिन में तीन घंटे से ज़्यादा टीवी या कंप्यूटर पर वक़्त बिताते हैं. दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे में 42 प्रतिशत लड़के चुस्त हैं, जबकि जांबिया में केवल 8 प्रतिशत लड़के चुस्त पाए गए. भारत में 37 प्रतिशत लड़कियां पर्याप्त व्यायाम करती हैं, जो शोध में शामिल देशों में सबसे ज़्यादा है. हालांकि इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन गूटहोल्ड का कहना है कि टीवी और कारों की संख्या बढ़ने की वजह से बच्चे अब कम चुस्त रह गए हैं.

श्मशान घाट पर पिकनिक

श्मशान घाट का नाम सुनते ही हो सकता है कि आप डर जाते हों. अगर आपको वहां अकेले जाने के लिए कहा जाए तो शायद आप नहीं जाएंगे, लेकिन एक श्मशान घाट ऐसा है, जो पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है. यह गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के बड़हलगंज इलाक़े में सरयू नदी के तट पर स्थित है. नाम है मुक्तिपथ श्मशान घाट. यहां लोग पिकनिक मनाने आते हैं. इसकी सुंदरता के बारे में सुनकर लोग ख़ुद को रोक नहीं पाते और यहां चले आते हैं कुछ पल सुकून से बिताने.

यहां वह सब कुछ है, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएं. हरी-भरी घास, फूलों के बगीचे, पानी के फव्वारे, ख़ूबसूरत पौधे, कृत्रिम गुफाएं और भगवान शिव की भव्य एवं विशालकाय मूर्ति. मुक्तिपथ के सचिव एवं पेशे से व्यवसायी लक्ष्मी नारायण गुप्ता कहते हैं कि 3.5 एकड़ क्षेत्र में फैला यह श्मशान घाट अपने सौंदर्य के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और पिकनिक मनाने वालों के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है. उनके अनुसार, यहां रोजाना क़रीब 600 से 900 लोग आते हैं. अगर शवों का अंतिम संस्कार करने वालों को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या एक हज़ार से ज़्यादा हो जाती है.

क़रीब नौ साल पहले बदलाव की शुरुआत हुई. स्थानीय लोगों ने इसका कायाकल्प करने की सोची. मुक्तिपथ के कोषाध्यक्ष मुकेश उमर के मुताबिक़, वर्ष 2001 में पहली बार श्मशान घाट के कायाकल्प के लिए तक़रीबन आठ लाख रुपये इकट्ठा हुए. उस धन से शवों को जलाने के लिए नदी के किनारे प्लेटफॉर्म बनाकर उनके ऊपर टिन की चादर लगाई गई. इसके अलावा शोक संतप्त लोगों के बैठने के लिए एक कक्ष का निर्माण किया गया.

2001 में शुरू हुआ धन इकट्ठा करने का सिलसिला आज भी जारी है, जिससे इस श्मशान घाट की तस्वीर बदल गई है. इसके निर्माण के लिए हर क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया. आज मुक्तिपथ सोसाइटी में क़रीब 60 से ज़्यादा सदस्य हैं, जो इसके लिए कार्ययोजना बनाने के साथ-साथ इसके रखरखाव का काम भी देखते हैं. सदस्यों में ज़्यादातर स्थानीय व्यवसायी, दुकानदार, चिकित्सक, शिक्षक एवं अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में हम इस श्मशान घाट के रखरखाव पर एक लाख रुपये मासिक ख़र्च करते हैं. सोसाइटी के सदस्यों के मुताबिक़, जल्द ही यहां पर एक ध्यान कक्ष, एक अतिथिगृह और एक अत्याधुनिक रेस्तरां खोला जाएगा, जिससे और ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे. इसके आलावा सोसाइटी उन लोगों से भी कोई शुल्क नहीं लेती, जो यहां सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं.

राशिफल

19 अप्रैल–25 अप्रैल 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, लेकिन आर्थिक तनाव बढ़ेगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. छात्रों को अपने मूल काम यानी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी. निजी संबंधों में निकटता आएगी. यात्रा-देशाटन का लाभ मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग बनाए रखने के लिए उसके कार्यों में मदद करें. उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है. भौतिक दिशा में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी. आपसी संबंधों में निकटता आएगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. रचनात्मक दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सड़कों पर जोखिम न लें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
सामाजिक कार्यों में व्यस्तता से मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखें. व्यर्थ की परेशानी बढ़ेगी.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी. वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. भौतिक दिशा में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे. जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल होंगे. पिता या संबंधित अधिकारी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. संबंधों में निकटता आएगी. भागदौड़ की स्थिति रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी अपेक्षित है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
कोई अधूरा पड़ा हुआ कार्य पूरा होगा. किसी के विवाद में न उलझें, नहीं तो हानि हो सकती है. दांपत्य जीवन सुखमय होगा. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
रुका हुआ कार्य संपन्न होगा. किसी तरह के विवाद का निपटारा इसी सप्ताह हो सकता है. दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी. निजी संबंधों में निकटता आएगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
व्यवसायिक योजना में प्रयास करने से सफलता मिल सकती है. यात्रा की संभावना बन रही है. संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. आय के नए रास्ते बनेंगे. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. संबंधों में निकटता आएगी. व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी. स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें. कहीं दूर की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रतियोगिता का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं. भागदौड़ रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. घर के मुखिया या पिता से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

पर्यावरण को बचाने के मुद्दे पर आम सहमति बनी तो बांग्लादेश ने जंगलों, पौधों एवं जानवरों की अनेक प्रजातियों की रक्षा के लिए भी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में क़दम आगे किए हैं.

पाकिस्तान अपना नज़रिया बदले

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सड़कों के किनारे नज़र आते पोस्टर्स और टेलीविज़न चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे विज्ञापनों में पिछले दो साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है. सरकार द्वारा प्रायोजित इन विज्ञापनों में इसकी तथाकथित कामयाबियों को ख़ूब बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. वैसे तो पूरे विश्व में सरकारें अपने मुंह मिया मिट्ठू बनने को आतुर रहती हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन कामयाबियों के प्रचार में वह झूठ दिखने लगता है कि अच्छा शासन उपलब्ध कराने में सरकार विफल है और यह भी कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में पाक सरकार की कोई ख़ास रुचि नहीं है.

पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा ही सर्वोपरि रहा है और अफ़ग़ानिस्तान में जिहाद और वार अगेंस्ट टेरर की शुरुआत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने बाक़ी समस्याओं को एक बार फिर पृष्ठभूमि में कर देने का रास्ता आसान कर दिया है. इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सेना आतंकवादियों से लड़ रही है और इसके लिए इसे अमेरिकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि हमारी विदेश नीति अभी भी उसी पुरानी लीक पर चल रही है, जिसका एकमात्र मक़सद भारत विरोध रहा है. 1948 से ही चली आ रही इस नीति में अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद की अहम भूमिका रही है, क्योंकि हमारे नीति निर्माता जानते हैं कि सैन्य मज़बूती के लिए आर्थिक विकास पहली शर्त है. शायद यही वजह है कि हाल के दिनों में अमेरिका के साथ हुई रणनीतिक बातचीत में इसी नज़रिए को आगे बढ़ाया गया है.

लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता से आम आदमी को अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. बातचीत के ताज़ा दौर को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों के एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है. सरकार से लेकर मीडिया तक इसे एक नई शुरुआत बताने पर तुले हैं, पर वास्तविकता यह है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की प्रकृति तब तब नहीं बदलेगी जब तक कि पाकिस्तान का नेतृत्व अपना नज़रिया नहीं बदलता और देश की आम जनता की तरक़्क़ी वाली नीतियों को केंद्र में जगह नहीं मिलती.

पाकिस्तान की त्रासदी रही है कि दशकों से शासन के नाम पर हमें जो देखने को मिला है, वह है शासन का सामंती चरित्र. चाहे कोई भी सत्ता में रहे, उसकी एकमात्र कोशिश राजनीतिक जोड़तोड़ के सहारे इसी सामंती चरित्र को बनाए रखने की रही है. जब भी कोई लोकतांत्रिक सरकार अस्तित्व में आती है तो सत्ता का दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ जाता है क्योंकि सैन्य बलों को संतुष्ट रखने के लिए सत्ता पर क़ाबिज़ सियासी ताक़तें उनके साथ गठजोड़ कर लेती हैं. यह दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा होता है. इससे एक ओर तो सेना को परदे के पीछे रहकर महत्वपूर्ण नीतियों को प्रभावित करने का मौक़ा मिल जाता है, तो दूसरी ओर सियासी दलों को अपने राजनीतिक एजेंडा को लागू करने का मौक़ा. हमारे राजनीतिक नेताओं में इतना साहस नहीं कि वह राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए कोई पहल करें.

आज पाकिस्तान वार अगेंस्ट टेरर के केंद्र में है लेकिन देश के अंदर आम लोगों के लिए आंतकवाद से मुक़ाबले के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है. अपने पैरों पर सीधे खड़े न होने वाली सत्ता से आप ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते लेकिन हैरत की बात तो यह है कि आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित कोई भी विधेयक आज तक हमारी संसद में पेश नहीं किया गया है जबकि आतंकवाद आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ा है. स्वात और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में आतंकी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई जारी है, लेकिन इसकी मदद के लिए किसी सरकारी नीति या इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं कोई वजूद नज़र नहीं आता. इससे न केवल हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमज़ोरी झलकती है, बल्कि देश में लंबे समय तक वजूद में रहे सैन्य शासन की कमियां भी सतह पर आ जाती हैं.

होना तो यह चाहिए था कि सरकार और सेना के बीच का यह गठजोड़ देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए ज़मीन तैयार करता. फिर यह भी सच है कि लोकतंत्र को फलने-फूलने का मौक़ा देना अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्ट हो चुके नेताओं और नौकरशाहों को बार-बार मौक़े दिए जाने से राजनीतिज्ञ का लबादा ओढ़े सैन्य अधिकारियों को अपनी हांकने का मौक़ा मिल जाता है. जब तक ज़मीनी स्तर से नेतृत्व को पैदा होने का

मौक़ा नहीं मिलता और इसे आम लोगों के सहयोग के सहारे राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक विकल्प के रूप में पहचान नहीं मिलती, तब तक आम पाकिस्तानी जनता अधिकारविहीन होकर जीने के लिए अभिशप्त है. इसीलिए हमारा मानना है कि अब समय आ चुका है कि आम लोगों के हितों को राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में सबसे ऊपर जगह दी जाए.

देश में आतंकवाद के ख़िलाफ़ चल रही लड़ाई का तात्कालिक मक़सद भले ही सुरक्षा का माहौल तैयार करना है, लेकिन यह आतंकी मानसिकता के प्रसार को रोकने में कामयाब नहीं हो सकता. आप विदेशी मुल्कों के साथ चाहे जितनी बातचीत कर लें, रणनीतिक गठजोड़ कर लें, लेकिन इससे आतंकवाद को पराजित नहीं किया जा सकता. इसके लिए ज़रूरी है कि देश की सुरक्षा को देशवासियों की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जाए. पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वह विदेशी मुल्कों से पहले अपनी जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करे, उनकी भावनाओं को समझे और नीति-निर्माण में उनकी ज़रूरतों को जगह दे.

तलत फारुख

(लेखक पाकिस्तान के राजनीतिक हालात के जानकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

बांग्लादेश ग्लोबल वार्मिंग से निबटने की तैयारी

बांग्लादेशी समाज का तक़रीबन हर तबका सरकारी तंत्र, नागरिक संस्थाएं और देश के प्रमुख विश्वविद्यालय, पर्यावरण पर मची हलचल को लेकर कौतूहल में हैं. सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि अब आगे क्या होने वाला है. इस साल की शुरुआत से ही देश भर में इस विषय पर सभा-सेमिनारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हाल ही में गठित क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट फंड से जुड़े नियम-क़ानूनों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है जिससे इस मोर्चे पर बांग्लादेश सरकार की गंभीरता का पता चलता है.

बांग्लादेश में अचानक बढ़ी इस जिज्ञासा और चिंता के पीछे दरअसल यह छुपा अहसास भी है कि आने वाले दिनों में पर्यावरण की रक्षा देश के भविष्य और विकास के लिए सबसे गंभीर चुनौती हो सकती है. अच्छी बात यह है कि राजनीतिक धरातल पर भिन्नताओं के बावजूद सभी दल इस बात से सहमत हैं कि मौसम प्रक्रिया में बदलाव तय है और इसके परिणाम इतने गंभीर होंगे कि बांग्लादेश इससे अछूता नहीं रह सकता. पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे इस ग़रीब देश के लिए इलाक़ों का जलप्लावन, पानी के खारेपन में वृद्धि, नदियों के जलस्तर में लगातार अस्थिरता और विस्थापन जैसी नई समस्याओं की संभावना भी एक डरावनी सिहरन पैदा करती है. दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित 15वें सीओपी से मिली निराशा के बाद अब लोग 2010 में मेक्सिको में आयोजित होने वाले 16वें सीओपी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं. उन्हें लगता है कि इस बैठक में सदस्य राष्ट्र ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर किसी ऐसे समझौते तक पहुंच सकते हैं, जो क़ानूनी रूप से बाध्यकारी हो.

इस बीच, जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी को लेकर बांग्लादेश ने भी पहल शुरू कर दी है. अचानक आई आपदाओं से निबटने के लिए सौ मिलियन डॉलर की राशि अलग रख दी गई है. इसके साथ ही, बांग्लादेश ने युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) की प्रक्रियाओं में भी ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने का फ़ैसला किया है ताकि उत्सर्जन और इसे कम करने के लिए उठाए गए क़दमों से अल्पविकसित राष्ट्रों की समस्याओं को ज़्यादा मुखरता के साथ उठाया जा सके. सबसे ज़्यादा ध्यान जल प्रबंधन की ओर दिया जा रहा है. देश में बहने वाली अधिकतर नदियां पड़ोसी मुल्कों से होकर आती हैं, इस सच्चाई से सरकार पूरी तरह वाक़िफ़ है इसीलिए बांग्लादेश ने क्षेत्रीय स्तर पर इसके लिए पहल की है. भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में फैले गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना के इलाक़े में जल संसाधनों के बेसिन आधारित विकास और प्रबंधन की ज़रूरत महसूस करते हुए इसके लिए बातचीत शुरू कर दी गई है. इसका उद्देश्य केवल साझा नदियों के जल का सामंजस्यपूर्ण इस्तेमाल ही नहीं है, बल्कि निचले इलाक़ों में बसे बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों के लिए जल प्रदूषण की गंभीर चुनौती से निबटना भी है. सरकार के साथ-साथ पर्यावरण क्षेत्र में सक्रिय नागरिक संस्थाएं भी इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. जल प्रबंधन से जुड़े लोगों के बीच एक और नई चीज देखने को मिल रही है. उन्हें आख़िरकार यह अहसास होने लगा है कि बांग्लादेशी समाज के तक़रीबन हर तबके प्रभावित इलाक़ों के चारों ओर बांध बनाकर उन्हें नदियों से दूर करने की कोशिश अब तक विफल रही है. सच तो यह है कि इससे बाढ़, जल निकासी, खारापन, ताजे जल के रखरखाव, मत्स्य पालन, जलमार्गों की उचित व्यवस्था आदि से संबंधित समस्याओं में इज़ाफ़ा ही हुआ है. अब वहां की सरकार ज़्यादा खुले और ऐसा नज़रिया अपनाने की कोशिश कर रही है जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक तंत्र से मेल खाता हो. हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे.

पर्यावरण को बचाने के मुद्दे पर आम सहमति बनी तो बांग्लादेश ने जंगलों, पौधों एवं जानवरों की अनेक प्रजातियों की रक्षा के लिए भी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में क़दम आगे किए हैं. अच्छी बात यह है कि पड़ोसी देशों के साथ दक्षिण अफ्रीकी देशों की तर्ज पर साझा जंगलों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जो राजनीतिक सीमाओं से परे हों. ये संभावनाएं हक़ीक़त में बदलें तो वनों और जंगली जानवरों की प्रजातियों

के साथ-साथ जैव विविधता के संरक्षण की भी उम्मीद की जा सकती है. इस क्षेत्र में सक्रिय ग़ैर सरकारी और नागरिक संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर प्रयास करें तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. देश के अर्थशास्त्री भी यह मान चुके हैं कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दे सामाजिक एवं आर्थिक विकास का केवल अभिन्न अंग ही नहीं हैं, बल्कि यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रदूषण वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया का ही एक नतीजा है. उन्होंने कई बार स्पष्ट किया है कि प्रदूषण निजी उपभोग का एक पहलू है और इसको कम करने का एक तरीक़ा यह हो सकता है कि हम निजी के बजाय सामाजिक या सामूहिक उपभोग को अपनाएं. यह सही है कि इससे संसाधनों के इस्तेमाल में कमी आएगी जिससे वातावरण पर कम बुरा असर पड़ेगा. इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सलाह अच्छी है, लेकिन बांग्लादेश के लिए बिल्कुल नई है और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके लिए ज़रूरी सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव को कैसे अंजाम दिए जाते हैं. मेरे विचार में ऐसे बदलाव तभी संभव हो सकते हैं जब पर्यावरण सुरक्षा को विकास के विस्तृत लक्ष्यों के साथ जगह दी जाए, पर्यावरण के प्रति चिंताओं को विकास के लिए बनी योजनाओं के साथ जोड़ा जाए और उपभोग की ऐसी प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए जिससे पर्यावरण पर बुरा असर न पड़े. प्रदूषण से जुड़े एक और पहलू, जिसे टीवी चैनलों और अख़बारों-पत्रिकाओं ने उठाया है, को देश भर में खासी तवज्जो मिल रही है. यह मामला है औद्योगिक कचरे से जल और ज़मीन पर फैलने वाले प्रदूषण से मुक़ाबला. इसके लिए सरकार और ख़ुद प्रधानमंत्री ने भी अनेक क़ानूनी प्रावधानों के कड़े अनुपालन की ज़रूरत पर भी बल दिया है, लेकिन इसके बावजूद औद्योगिक प्रतिष्ठान नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं. लेकिन अब शायद आंखें मूंदें रहने का समय बीत चुका है. यह बेहद ज़रूरी है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर नज़र रखने वाले लोग इन प्रावधानों के अनुपालन को पूरी तरह सुनिश्चित करें. कृषि कार्यों, खासकर खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल में प्रदूषण नियंत्रित करने वाले कार्यक्रमों और पर्यावरण प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत है. इससे ज़मीन पर जल प्रदूषण की समस्या से निजात पाई जा सकती है. ऊर्जा संसाधनों की कमी और बिजली के स्वच्छ उत्पादन को विकास के एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का एक फल यह है कि आम जनता के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी ऊर्जा के ग़ैर-परंपरागत स्रोतों की ओर उन्मुख हो रही है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन के बेहतर इस्तेमाल और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है. इसके लिए विदेशों से भी आर्थिक सहायता मिल रही है और हम यह उम्मीद करते हैं कि इससे इस क्षेत्र में विकास की गति तेज़ होगी. जिस तरह 1980 और 1990 के दशकों में कपड़ा उद्योग ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, उसी तरह सौर ऊर्जा भी वर्तमान दशक में बांग्लादेश के विकास का इंजन साबित हो सकता है. पर्यावरण मुद्दे पर रणनीति बनाने में जुटे योजनाकार एक और पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. यह है घरेलू कचरे को उर्वरक या ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में और ज़्यादा प्रयास. इसके लिए ज़रूरी है कि स्थानीय संस्थाएं घरों से कचरे को जमा करने से लेकर उसके प्रबंधन और निस्तारण के प्रति गंभीर हों. इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण के लिए अलग और पर्याप्त व्यवस्था हो. इसके लिए नए सिरे से क्षमता निर्माण और लोगों को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत होगी. हम उम्मीद करते हैं कि विकास के मौजूदा संसाधनों से ही इसके लिए व्यवस्था संभव हो सकेगी. हालांकि, ये सभी चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब हम पर्यावरण से संबंधित क़ानूनी, व्यवस्था प्रबंधन और प्रशासनिक पहलुओं को मज़बूत करें और इसके मुताबिक़ संस्थाओं के गठन पर ध्यान दें. बाज़ार-आधारित उपायों के साथ पर्यावरण सुरक्षा उपायों का समुचित मिश्रण इसमें सहायक हो सकता है. इसके बाद संभव है कि इसी उद्देश्य से खास तौर पर गठित की जाने वाली पर्यावरण अदालतें पर्यावरण मानकों को कड़ाई से लागू करने में सक्षम हों.

मोहम्मद जमीर

(लेखक पूर्व सचिव और राजदूत हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

COACHING BY EXPERTS
PACIFIC SPORTS COMPLEX
MEMBERSHIP OPEN
Offers World Class Facilities in

Olympic Size Swimming Pool (50x21 m)

Taekwondo

Table Tennis

Ice Hokey
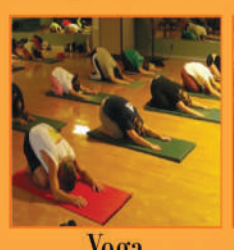
Yoga
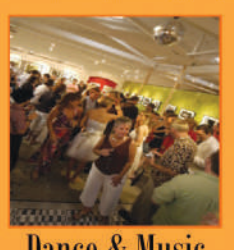
Dance & Music
Lajpat Nagar, Near L.S.R., Opp. G.K .- I Petrol Pump New Delhi
Call : 011-64640005, 64640006 , 26452747/48, 9911138192

दिल में नन्हीं सी चींटी, बोझा ढोने वाले जानवर और परिंदों के साथ ही पड़ोसी के लिए भी प्रेम का संदेश है. शिरडी के साई बाबा भी प्रायः जीवमात्र से प्रेम करने, आपस में भाईचारा रखने और सभी को अंहिसा का मार्ग दिखाया करते थे.

दिल्ली, 19 अप्रैल–25 अप्रैल 2010
चौथी दुनिया

परमेश्वर के संदेश वाहक हैं साईबाबा : आनंद सागर

विकास कपूर

इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने आचरण और अपने सौम्य–मृदु व्यवहार से अपनी आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा बन जाते हैं. आनंद सागरजी उन्हीं चन्द लोगों में एक हैं जिनसे एकबार मिलने के बाद उनके मृदु व्यवहार की स्मृति जीवन पर्यन्त बनी रहती है. युवा उनसे मिलकर अपने बारे में सोचने पर विवश हो जाते हैं. उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि जो उनसे मिलता है उसे बहुत कुछ मिल जाता है. भारतीय टेलिविजन पर पहला धार्मिक धारावाहिक बनाने और उसे जन–जन तक पहुंचाने वाले आधुनिक तुलसीदास स्व.श्रीरामानंद सागर के पुत्र श्री आनंद सागर स्वयं एक सफल निर्देशक और निर्माता हैं. फ़िल्म निर्देशक के रूप में आनंद जी ने हमराही (1974), राम भरोसे (1977), प्यारा दुश्मन (1980), अरमान (1981), जुल्फ के साये (1983) बादल (1984) आदि फ़िल्मों का सफल निर्देशन किया. वहीं टेलिविज़न पर भी उन्होंने कई कालजयी कृतियों के निर्माण और निर्देशन का सफल उत्तरदायित्व संभाला. रामायण, श्रीकृष्ण, जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी माता, रामायण (एनडीटीवी), महिमा शनिदेव की, अलिफ लैला, पृथ्वीराज चौहान और साईबाबा आदि. माता भगवती के साथ ही साथ साईबाबा का हृदय से आदर करने वाले आनंदजी से उनकी साईभक्ति पर पिछले दिनों उनके कार्यालय सागर हाऊस में लंबी बात–चीत हुई, जिसके कुछ अंश यहां प्रस्तुत हैं.

मुझे लगता है, अब भी यदि श्रद्धा के साथ धार्मिक धारावाहिक बनाए जाते हैं तो उनके लिए भी दर्शकों के पास रिमोट नहीं होता है.

साईराम आनंदजी.. ॐ साईराम..

आपने और आपकी कंपनी सागर आर्ट ने दूरदर्शन और टीवी के माध्यम से समाज में धार्मिकता की अलख जगाई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं.

हम नहीं, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं पापाजी, जो वास्तव में एक संत थे. मैने कई बार उन्हें भगवान का चरित्र पढ़ते–पढ़ते भाव–विभोर होते देखा है. वे हमेशा कहा करते थे कि जैसा लिखा है वैसा ही कैमरे से उतार दो अगर उसमें ज़रा सी भी चूक हो जाती थी तो पापाजी उसे रिजेक्ट करके रिशूट करवाते थे. उनके मन में हर चरित्र के प्रति प्रेम और आदर था. उनके साथ रहकर ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला.

दूरदर्शन पर आई रामायण ने भारतीय टेलीविज़न को एक नया आयाम दिया तब से लेकर अबतक आप और आपकी कंपनी लगातार धार्मिक धारावाहिकों का निर्माण करती आई है. तब और अब में आपको क्या अंतर दिखता है ?

कोई अंतर नहीं है. जब रामायण आई थी तब लोगों के पास रिमोट नहीं था और मुझे लगता है अब भी यदि श्रद्धा के साथ धार्मिक धारावाहिक बनाए जाते हैं तो उनके लिए भी दर्शकों के पास रिमोट नहीं होता है. वे उतनी ही श्रद्धा और भक्ति से उन धारावाहिकों को बिना चैनल चेंज किए देखते हैं.

क्या लोगों की श्रद्धा में कुछ अंतर आया है ?

नहीं, बिल्कुल नहीं. बल्कि पहले से श्रद्धा अब और अधिक बढ़ गई है. आश्चर्यजनक रूप से युवावर्ग पूजा और भक्ति की तरफ़ आकर्षित हुए हैं. उनके भीतर विश्वास की ज्योति प्रज्जवलित हुई है.

साईबाबा पर आपकी कंपनी ने स्टार टीवी पर एक सफल धारावाहिक का निर्माण किया. आप साईबाबा को किस रूप में देखते हैं ?

गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं जब–जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब–तब मैं अवतार लेता हूं. ठीक उसी प्रकार हम भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर प्रायः अपने संदेशवाहकों को भेजता है. साईबाबा भी हम सबका मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर के संदेशवाहक हैं.

शिरडी में रहते हुए साईबाबा ने जो संदेश दिया उन्हें आप किस दृष्टि से देखते हैं ?

उन संदेशों और बाबा की शिक्षा ने उन्हें परमेश्वर का संदेशवाहक नहीं, बल्कि स्वयं ही परमेश्वर के समान पूजनीय बना दिया. यह उसी प्रकार से है जैसे धर्म, ज्ञान और कला संस्कृति पर बहुत सारे लोगों ने वेद–पुराण और न जाने क्या–क्या लिखा, परंतु तुलसीदासजी ने जो लिखा वह केवल ग्रंथ बनकर ही नहीं रहा वरन् मुक्ति का महामंत्र बन गया.

आनंद शर्मा

साईबाबा के जीवन चरित्र से समाज को सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है ?

सबका मालिक एक, कहकर बाबा हमें यही समझाना चाहते थे कि धर्म–मज़हब, जात–पात तो बहुत छोटी चीज है. सच में बड़प्पन और बड़ी बात तो है इंसानियत. अगर हम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई बनने से पहले सच्चे इंसान बन जाएं तो हमने सही मायने में जीवन जी लिया और फिर हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि धर्म भले ही अलग–अलग हो, पर परमेश्वर एक है. मालिक एक ही है. ॐ साईराम.

feedback@chauthiduniya.com

हमारी भक्ति

साई बाबा के जीवन एवं सच्चरित्र और आपकी अपनी भक्ति से संबंधित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साई भक्त के विचार यहां प्रकाशित किए जाएंगे.

क्या आजकल तथाकथित आध्यात्मिक गुरु अपनी दुकान साईबाबा के नाम पर चला रहे हैं ?

आपके जवाब

1. (सर्वश्रेष्ठ विचार)

आजकल के हालात देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आज-कल के तथाकथित बाबा अपनी दुकान साईबाबा के नाम पर चला रहे हैं. कोई अपने को साई का अवतार बताता है तो कोई साई का बंदा, कोई साईभक्ति का प्रचार-प्रसार करके अपना उल्लू सीधा करता है. लेकिन ग़लती उन बाबाओं की नहीं हमारे समाज की है जिनके सामने शिरडी के साईबाबा जैसे सच्चे गुरू मौजूद हैं, फिर भी वह इन तथाकथित झूठे बाबाओं के चक्कर में घिर जाते हैं.

आकाश पवार, नई दिल्ली

2.जो लोग बाबा की आड़ में अपनी दुकान चलाकर ग़लत काम कर रहे हैं उन्हें इच्छाधारी बाबा के भंडाफोड़ के बाद सावधान हो जाना चाहिए. साईबाबा का सटका किसी दिन उनपर ज़रूर गिरेगा.

नीरा मेहरोत्रा, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

3.बाबा एक ऐसी शख़्सियत हैं जिनके नाम का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की नैया पार लग जाती है. अगर कुछ बाबा अपनी नैया पार करने के लिए साईबाबा के नाम का सहारा ले रहे हैं तो इसमें हर्ज़ ही क्या है ?

संजय बाजपेई, गाज़ियाबाद

आप अपने विचार sai4world@gmail.com पर मेल करें अथवा शिरडी साईबाबा फाउन्डेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर-17517, मोतीलाल नगर नम्बर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-58 पर डाक द्वारा भेजें या 09999989427 पर एसएमएस करें.

अगले सप्ताह का विषय
आपकी दृष्टि में साई बाबा कौन थे?

Giriraj
Sai Hills
Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

AUM Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.ssbf.in

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

प्रेम-मैत्री, अहिंसा और भाईचारे का संदेश देता है इस्लाम

शिरडी साईबाबा फाउंडेशन का साईभक्त परिवार पिछले कई वर्षों से समाज के अचेतन में साई की सच्ची भक्ति की चेतना जगाने जैसा पुनीत कार्य कर रहा है.

अपने अनुयायियों को एक सूत्र में पिरोने की जो शिक्षा इस्लाम देता है वह शायद विश्व का दूसरा कोई और मज़हब नहीं देता. अल्लाहताला के अदब में नमाज़ करते वक़्त न कोई राजा है और न कोई रंक, सब एक समान और एक ही मालिक (ख़ुदा) के बंदे हैं. इस्लाम अमीर–ग़रीब का बिल्कुल भेद नहीं करता.

पवित्र कुरान की शिक्षाओं की अनेक कहानियों में से एक शिक्षाप्रद कहानी पढ़ने को यह मिलती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम आम ख़रीद कर खा सकते हो, तो उसका कुछ भाग अपने पड़ोसी को भी दो. अगर पड़ोसी को देने की हैसियत नहीं है तो आम खाकर उसके छिलके और गुठलियां घर से दूर फेंककर आओ, ताकि तुम्हारा पड़ोसी उन छिलकों और गुठलियों को देखकर अफ़सोस न करे कि मालिक ने उसे आम खाने के लिए पैसे नहीं दिए. भाईचारे के लिए इससे अच्छी मिसाल मिलनी मुश्किल है.

एक और प्रेरक कथा पढ़ने को मिलती है. एक बड़ा काफ़िला लंबी यात्रा के बाद एक नदी के किनारे आकर ठहर गया. काफ़िले में शामिल लोग थके और भूखे थे. इसीलिए रुकते ही उन्होंने जल्दी–जल्दी सूखी लकड़ियां एकत्र करके आग जलाई और भोजन पकाना शुरू कर दिया. उस काफ़िले के सरदार किसी गहरी सोच में डूब गए, पास के एक पत्थर पर बैठे थे तभी उनकी निगाह जलते हुए चूल्हों पर गई. अचानक उन्होंने आदेश भरे स्वर में कहा, आग बुझा दो. तुरंत से भी पेशतर, उनके हुक्म की तामील हुई और आग बुझा दी गई. सरदार के पास खड़े लोगों ने जब आग बुझाने का कारण पूछा तो सरदार ने उस तरफ़ इशारा करते हुए कहा कि जिस जगह चूल्हा जलाया गया था वहां चीटियों की बांबी थीं. आग की तपिश से चीटियां झुलसने लगीं, जीव हत्या को रोकने के लिए ही मैंने आग बुझवा दी. इस काफ़िले के सरदार थे इस्लाम के उन्नायक और प्रणेता साल्ल. हज़रत मुहम्मद साहब.

एक बार सहाबी अबदुल्ला बिन उमर ने देखा कि कुछ लडके एक चिड़िया को बांधकर उस पर निशाना लगा रहे हैं. उमर को देखते ही वे लड़के इधर–उधर भाग निकले तब उमर ने कहा कि हज़रत ने उस व्यक्ति के लिए धिक्कार कहा है जो किसी जीव को निशाना बनाए. उमर ने बताया कि हुज़ूर ने फरमाया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जीव को बेमतलब मारेगा तो क़यामत के दिन वह अल्लाह से फ़रियाद करेगा कि ऐ रब, इसने मेरा क़त्ल किया था. सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि एक बार हज़रत मुहम्मद साहब के सामने से एक गधा गुज़रा, जिसके चेहरे को दागा गया था और नाक से ख़ून बह रहा था. गधे का दुख देखकर हुज़ूर को बड़ा गुस्सा आया. उन्होंने कहा कि उस पर धिक्कार है जिसने इस तरह की वहियात हरक़त की. उन्होंने घोषणा करवा दी कि न तो पशुओं के चेहरों को दागा जाए और न ही उनके चेहरे पर मारा जाए. हुज़ूर ने जानवरों से उनकी ताक़त से ज़्यादा काम लेने, जैसे उन पर ज़्यादा बोझा लादने, उनपर अत्याचार करने और उन्हें भूखा–प्यासा रखने से भी मना कर दिया .

इन उदाहरणों से पता चलता है कि इस्लाम की सोच कैसी है और वह किस कदर इंसानियत की मिसाल देता है. उसके दिल में नन्हीं सी चींटी, बोझा ढोने वाले जानवर और परिंदों के साथ ही पड़ोसी के लिए भी प्रेम का संदेश है.

शिरडी के साईबाबा भी प्रायः जीवमात्र से प्रेम करने, आपस में भाईचारा रखने और सभी को अंहिसा का मार्ग दिखाया करते थे. उन्होंने कभी जात–पात के आधार पर इंसान–इंसान में भेद नहीं किया. शिरडी साईबाबा फाउंडेशन का साई भक्त परिवार पिछले कई वर्षों से समाज के अचेतन में साई की सच्ची भक्ति की चेतना जगाने जैसा पुनीत कार्य कर रहा है.

हम इस पावन यज्ञ में आपका भी आह्वान करते हैं. आइए और अपनी भक्ति की समिधा श्री साई चरणों में अर्पित करने के अधिकारी बनिए. साईभक्त परिवार में शामिल होकर अपनी साईभक्ति को और अधिक दृढ़ करने और सद्गुरू साई समर्थ की कृपा का अधिकारी बनने के लिए आप अपना नाम साईभक्त..... .....और फोन नंबर..... कृपया 09999989427 पर एसएमएस करें. ॐ साईराम.

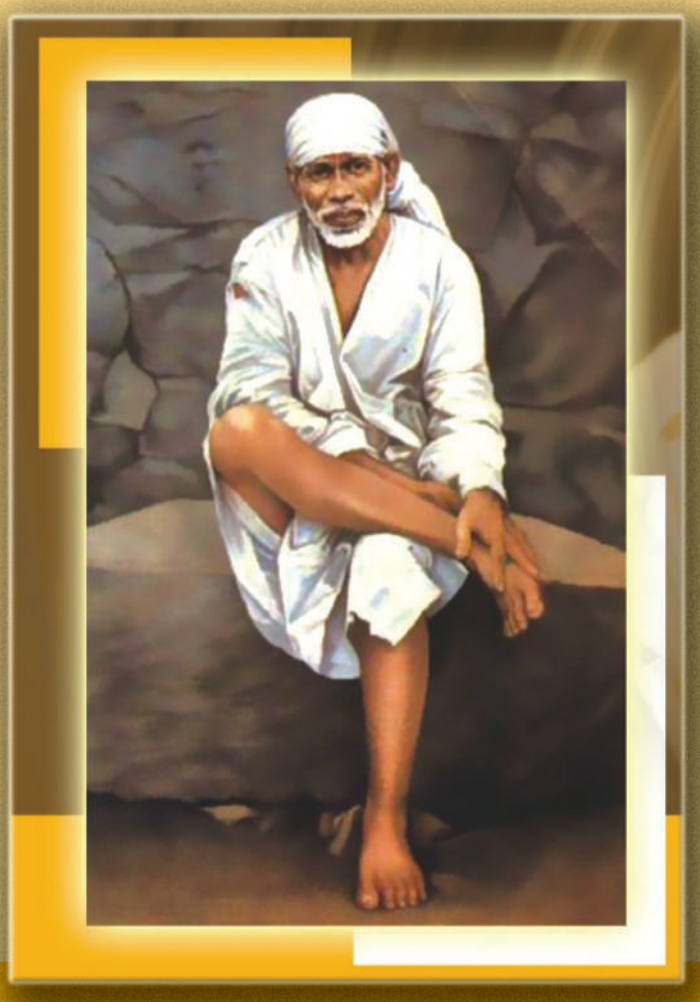

ऑसिम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

Shirdi Sai Baba Foundation
presents
LIFE IS HOPE
Center
Complete
Mind, Body & Soul
Rejuvenation

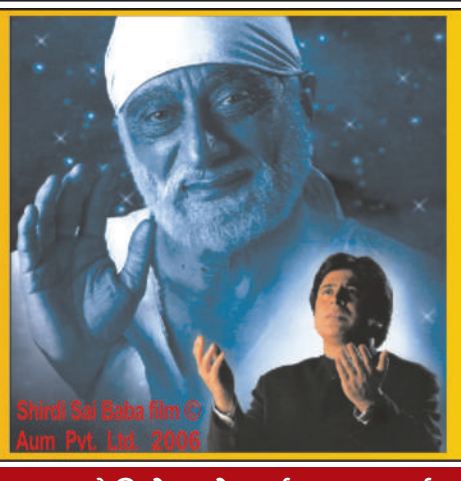

OFFERS CLASSES/SESSIONS FOR:
- Antrang Yoga
- Innovative Meditative Dancing
- Innovative, Healthy, Nutritious Cooking
- Pottery Making
- Stain Glass Painting / Painting (Ladies & Children)
- Theatre - Children
- Spiritual Healing with Aushim Khetarpal
- Discover yourself with Kanu Priya

"Oneness with GOD"
Come and experience the serenity and Connect with the DIVINE

At PACIFIC SPORTS COMPLEX - a World Class Sporting & Swimming facility, opposite Petrol Pump, G.K. - I, Andrews Ganj in South Delhi.

REGISTRATION NOW OPEN
Contact : 01164640005/06 Mobile : 9999041571
E-mail : shirdisaibabafoundation@gmail.com
Register Online at www.ssbf.in

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि वे अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना (कार्यक्रम, प्रबंधक, तिथि, स्थान और समय सहित) विकास कपूर को sai4world@gmail.com पर मेल कर सकते हैं.

मेलाधिकारी को असफल कराने में स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग की बड़ी भूमिका है. यही दोनों मेलों-ठेलों के सर्वाधिक दुधारू विभाग माने जाते हैं.

सफलता तलाशता विवाद

अनंत विजय

आमिर ख़ान, राजू हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा की फ़िल्म थ्री इडियट्स ने मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन कमाई के साथ-साथ इस फ़िल्म ने अंग्रेज़ी लेखकों के बीच प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष कर रहे चेतन भगत को हिंदी जगत में भी लोकप्रिय कर दिया. हुआ यह कि अपने द्वारा 2004 में लिखे उपन्यास *फाइव प्वाइंट समवन-व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी* पर आधारित फ़िल्म *थ्री इडियट्स* की सफलता के संकेत मिलते ही चेतन भगत ने फ़िल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर आरोपों की झड़ी लगा दी. चेतन को इस बात की तक़लीफ़ थी कि उन्हें फ़िल्म के क्रेडिट में उचित स्थान नहीं मिला. आरोप इस बात का लगाया गया कि फ़िल्म की शुरुआत में स्टोरी और स्क्रीनप्ले के क्रेडिट में सिर्फ़ राजू हिरानी और अभिजात जोशी का नाम दिया गया, जबकि चेतन भगत का नाम फ़िल्म के अंत में रोलिंग क्रेडिट में दिया गया. राजू हिरानी ने उनके आरोपों को ख़ारिज कर दिया था.

सफल फ़िल्म, सफल हीरो और अंग्रेजी के लोकप्रिय लेखक के बीच विवाद, आरोपों- प्रत्यारोपों की झड़ी. न्यूज़ चैनलों ने इस मुद्दे को लपक लिया और पूरे हफ्ते यह ख़बर प्रमुखता के साथ हर न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम पर चली. फ़िल्म को तो इसका लाभ मिला ही, चेतन भी ज़बरदस्त रूप से लाभांवित हुए. 2004 में छपी और लाखों की संख्या में बिक चुकी इस किताब की खोज में नए पाठक फिर से किताबों की दुकानों पर जाने लगे और थ्री इडियट्स की सफलता पर सवार होकर यह किताब एक बार फिर से हिट हो गई. चेतन भगत को दूसरा लाभ यह मिला कि उन्हें हिंदी के पाठकों के बीच एक पहचान मिली.

यह इस विवाद का एक ऐसा पहलू है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं पूरा का पूरा विवाद एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं था. कहीं यह हिंदी के विशाल बाज़ार में पैठ बनाने का योजनाबद्ध प्रयास तो नहीं था. हमें इस बात पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि भविष्य में बड़े पैमाने पर चेतन की किताबें हिंदी में अनूदित होकर बाज़ार में आ जाएं.

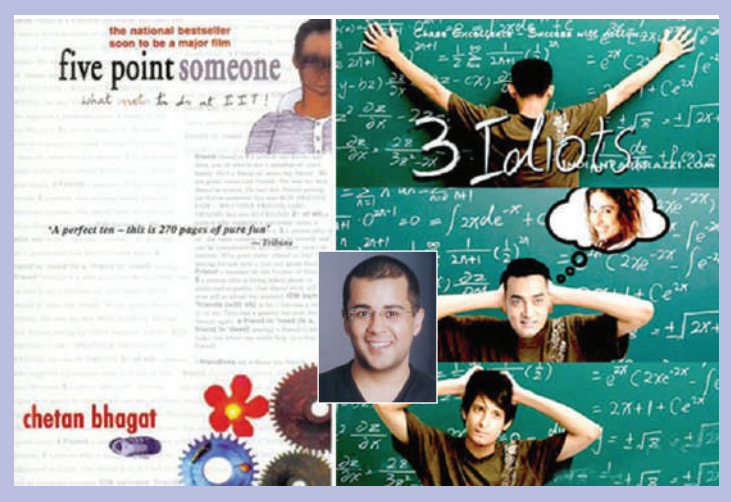

अब अगर हम चेतन की इस किताब, *फाइव प्वाइंट समवन-व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी* पर बात करें तो कृति के रूप में यह एक बेहद कमज़ोर किताब है. दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के पूर्व छात्र रह चुके चेतन भगत ने अपने कॉलेज के दिनों के अनुभवों को बेहद ही सरल और कैंपस की बोलचाल की भाषा में कलमबद्ध किया है. चेतन की इस किताब में हरि, रेयन और आलोक नाम के तीन ऐसे छात्रों की कहानी है, जो अपने-अपने इलाक़े के बेहद प्रतिभाशाली छात्र हैं. आईआईटी में एडमिशन लेते वक़्त तक उन्हें अपनी प्रतिभा पर बेहद गर्व होता है, लेकिन कॉलेज में दाख़िला लेने के बाद उनका गर्व मिट्टी में मिल जाता है, जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वहां ज़्यादा प्रतिभाशाली छात्रों की पूरी फ़ौज मौजूद है. इन तीनों की दोस्ती की नींव उस वक़्त पड़ती है, जब उनके सीनियर्स रात में उन्हें उनके कमरे से रैगिंग के लिए खींच ले जाते हैं. रैंगिग के पीड़ित उक्त तीनों कालांतर में बेहद क़रीबी दोस्त बन जाते हैं.

इन तीनों लड़कों के माध्यम से चेतन भगत ने एक ऐसी पीढ़ी की तस्वीर खींचने की कोशिश की है, जिसकी आंखों में सुंदर सपने हैं, जिसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है. रेयान, हरि और आलोक को केंद्र में रखकर चेतन ने कहानी का एक ऐसा ताना-बाना बुना है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर चोट करता प्रतीत तो होता है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं. इस किताब में शिक्षा व्यवस्था पर चोट नहीं की गई है, बल्कि उसे ऐसे युवाओं की आंख से देखने या दिखाने की कोशिश की गई है, जो अपनी सफलता के लिए एक शॉर्टकट की तलाश में हैं. जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में वे बेहद सफल हों. मेहनत भी करें, लेकिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे फन को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि फन तो उनका बर्थ राइट है. यह एक ऐसी पीढ़ी की स्टोरी है, जो अपने आप में भी मस्त रहती है. एक ऐसी पीढ़ी, जो प्यार-मोहब्बत भी देख-परख कर करती है. एक ऐसी पीढ़ी, जो *फक, स्क्रू, क्रैब, ऐसहोल, शिट* जैसे शब्दों का आपसी बातचीत में बिल्कुल बेफ़िक्री से इस्तेमाल करती है. चेतन की यह पूरी किताब घटना प्रधान है और पाठकों को चौंकाने का प्रयास करती चलती है. पाठकों को झटका देने के लिए लेखक पात्रों से बेहद दुस्साहसिक काम भी करवाता है. सफलता के इस सूत्र को पकड़ते हुए चेतन ने पात्रों से ऐसे ही दुस्साहसी काम करवाए भी हैं. मसलन तीनों लड़कों से अपने विभागाध्यक्ष के कमरे में रात में घुसकर क्वेश्चन पेपर चोरी की घटना और फिर रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी शर्मिंदगी का एहसास तक न होना. इन पात्रों और घटनाओं के अलावा लेखक ने अपनी कृति को सफल बनाने के लिए उसमें एक स्त्री पात्र भी डाला है. यह पात्र ठीक उसी तरह है, जैसे किसी बॉलीवुड फ़िल्म को सफल बनाने के लिए उसमें आइटम नंबर डाला जाता है. विभागाध्यक्ष की बेटी नेहा अपने पिता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लड़कों से दोस्ती करती है, वह एक ऐसी बिंदास और आज़ाद ख्याल वाली लड़की है, जिसे अपने ब्वॉय फ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई झिझक नहीं होती. उसके लिए तो यह संबंध फन ऑफ लाइफ है. कौमार्य भंग होने या फिर कुंवारी लड़की का लड़के से शारीरिक संबंध बनाने का कोई रिमोर्स नहीं, क्योंकि उसकी अपनी च्वाइस है. वह अपने फ़ैसले ख़ुद लेना चाहती है. चेतन भगत ने इसे ध्यान में रखते हुए इस पात्र के ज़रिए अपनी किताब में सेक्स का तड़का भी लगाया है. चेतन भगत का जो नैरेटिव है, उसमें एक पेस है, वाक्यों में पंच है, शब्दों में नयापन है, लेकिन लेखन की गहराई नहीं. छात्रों के बीच बोली जाने वाली भाषा को अपने लेखन में इस्तेमाल कर चेतन ने पाठकों के शब्द ज्ञान में भी इज़ाफ़ा किया है. इस किताब की सफलता की वजह पुराने विषय का नया ट्रीटमेंट, पात्रों और घटनाओं का रियलिटी के क़रीब होना है. कैंपस ह्यूमर से लबरेज इस किताब में कई दुखद घटनाएं भी हैं, लेकिन पात्र उनसे बेहद जल्द उबर जाते हैं.

इस किताब में बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आईआईटी में ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएटिविटी पर भारी है. लेकिन यह संदेश के तौर पर नहीं, बल्कि पाठकों के मन को क़रीब से पकड़ने के लिए किया गया है. इस वजह से ही ग्रेडिंग सिस्टम के फाइव प्वाइंट से इस किताब का शीर्षक उठाया गया है. कुल मिलाकर अगर हम एक कृति के तौर पर इस पर विचार करें तो यह बेहद हल्की, चालू क़िस्म की किताब है. मेरी राय में यह उसी तरह है, जिस तरह हिंदी में मेरठ से छपने वाले उपन्यास हैं, जो बिकते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन न तो उनका कोई स्थायी महत्व है और न ही गंभीर लेखकों एवं पाठकों के बीच स्वीकार्यता.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

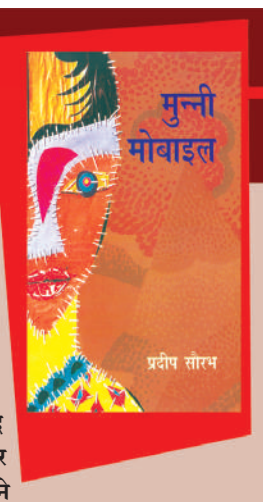

प्रदीप सौरभ

गाड़ी आगे बढ़ रही थी. महेसाणा गुजर चुका था. महेसाणा भी दंगों की चपेट में रहा था. कई बार वह यहां आ चुके थे. सब कुछ अपना-अपना और जाना-पहचाना सा लग रहा था. गुजरात सीमा से बाहर निकलने की जल्दी थी. कार के एक्सीलेटर पर वह दबाव बनाए हुए थे. कार फर्राटा मार कर दौड़ रही थी. आनंद भारती के साथ शाहआलम राहत शिविर चलाने वाले शरीफ पठान ने अपना ड्राइवर भी भेजा था. नाम था उनका मियां मिर्ची. बुजुर्ग थे. दंगों के दौरान एंबुलेंस चलाते थे. बुरे मंजरों के पहले गवाह रहे थे वह. शहर छोड़ने से पहले शरीफ पठान ने आनंद भारती की विदाई के मौके पर एक फेयरवेल भी रखी थी. काफी लोग आए थे. माहौल भावुक हो उठा था. उनके कई पत्रकार मित्र भी थे उसमें, जिन्होंने हिंदू ब्रिगेड की घिनौनी हरकतों के खिलाफ मोर्चा लिया था. उनके हमले भी सहे थे. पहली बार उस पार्टी से उन्हें लगा कि इस शहर में उनके चाहने वाले भी हैं. असल में वह अकेले नहीं हैं. अकेलापन उन्होंने ओढ़ रखा है. मियां मिर्ची बार-बार गाड़ी चलाने की जिद कर रहे थे. इसके पीछे उनका भाव था कि आनंद भारती को कोई तकलीफ न हो. वह उनसे काफी प्रभावित थे. उन्होंने दंगों के दौरान उन्हें ऐसे मौकों पर देखा था, जहां किसी हिंदू पत्रकार के जाने का साहस न हो. धुर मुस्लिम इलाकों में. उदयपुर आ चुका था. आनंद भारती ने गाड़ी का स्टेयरिंग छोड़ने का फैसला किया. मियां मिर्ची गाड़ी के रथी बन चुके थे. वह गजब की गाड़ी चलाते हैं. हर मौके पर उन्होंने छोटी-बड़ी गाड़ी चलाई है. कहते हैं, खुदा की रहमत इतनी रही है कि आज तक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ. दंगों में उन्होंने एंबुलेंस चलाई थी. दर्जनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया था. वह दंगों की कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहते हैं. लेकिन आनंद भारती उन यादों को फिलहाल फिर से सुनकर दिल्ली वापसी की अपनी खुशी पर ग्रहण नहीं लगाना चाहते हैं. इसीलिए वह मियां मिर्ची को टाल देते हैं.

आनंद भारती दिल्ली के सपनों में डूब जाते हैं. दिल्ली के साथ आनंद भारती की बेहद खट्टी-मिट्ठी यादें जुड़ी हैं. इसी शहर ने उन्हें कर्मक्षेत्र में प्रतिष्ठित किया. यह वह शहर है, जहां इलाहाबाद से रूठकर आनंद जब-जब आए... खुद की कलम को ईंधन बनाकर काम की भट्ठी में जो कुछ झोंका, वह तप कर, निखर कर निकला. उनकी पहचान को विस्तार मिला और तेवर को संतुष्टि. वह याद कर रहे थे कि अपनी पत्नी शिवानी के साथ दिल्ली में जब वह आए तो इस शहर में परिवार के प्रति दायित्व की अनुभूति उन्हें पहली बार हुई. इससे पहले विवाह पूर्व भी वह घर से लड़कर दिल्ली आए थे और कुछ महीनों तक फ्रीलांसिंग करते रहे थे, पर तब उनके अक्खड़-फक्खड़ स्वभाव के लिए ज्यादा टीमटाम की जरूरत नहीं थी. जहां चार यार मिल जाएं, वहीं रात दें गुजार की तर्ज पर आनंद भारती बेफ्रिक से रहते थे. पर पत्नी शिवानी के साथ घर बसाने की कल्पना ने उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया था. 1986 के आसपास वह इलाहाबाद से दिल्ली आए थे. उन्हें यहां उजाला-जागरण समूह की एक साप्ताहिक पत्रिका में नौकरी मिली थी. बाद में पत्रिका बंद हो गई तो वह उसी समूह के दैनिक में काम करने लगे थे. इसी दौरान उन्होंने अपना मकान बनाने की ठान ली थी. इधर-उधर से उधार लेकर उन्होंने दिल्ली के जमुनापार की जनता कालोनी में एक कमरे का मकान ले लिया था. उन्होंने उसे तोड़कर एक अच्छा लुक दे दिया था. उन दिनों जमुनापार इलाके को दिल्ली वाले अच्छी नजर से नहीं देखते थे. कहते, नानक सुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुनापार.

feedback@chauthiduniya.com

मेला व्यवस्था पर नहीं, आस्था पर टिका है

डॉ. कमलकांत बुधकर

ये पंक्तियां प्रकाशित होने तक उत्तराखंड के पहले महाकुंभ का मुख्य और अंतिम स्नान हरिद्वार में संपन्न हो चुका होगा. शासन, प्रशासन, पुलिस, हरिद्वार के नागरिक और स्थायी निवासी सभी लोग चैन की सांस ले रहे होंगे. महापर्व से सात दिन पहले के, जब यह आलेख लिखा जा रहा है, हालात देखते हुए सभी कामना कर रहे हैं कि यह महापर्व राजी-ख़ुशी निबट जाए. राजी-ख़ुशी का अर्थ है बिना किसी प्रकार की जन-धन की हानि के. क्योंकि, इस बार की कुंभ व्यवस्थाओं में मेलाधिकारी आनंद बर्द्धन का पूरा साथ उनके मातहत न जाने क्यों नहीं दे पाए हैं, ऐसा आम जनमत है. इस जनमत के पीछे अनेक कारण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं.

2010 के कुंभ महापर्व के लिए क़रीब साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. बताया जाता है कि इतनी बड़ी राशि के कुंभकार्यों में से अनेक कार्य तो शुरू नहीं हो पाए और अनेक कार्य मुख्य कुंभस्नान के ऐन पहले तक भी अधूरे पड़े हैं. इन हालात में कुंभ की व्यवस्थाओं के ऐन वक़्त पर चरमरा जाने की स्थिति भी बन सकती है, ऐसी आशंका कइयों के मन में है. मेलाधिकारी को नाकाम कराने में स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग की बड़ी भूमिका है. यही दोनों मेलों-ठेलों के सर्वाधिक दुधारू विभाग माने जाते हैं. इन विभागों ने इस बार के कुंभ मेले में जो भूमिका निभाई है, उसे लेकर हर जगह थू-थू हो रही है. सड़कों की दुर्दशा और मुख्य यात्री क्षेत्रों में सड़कों का न बनना, बनना भी तो अत्यंत घटिया स्तर की बनना सर्वत्र चर्चा का विषय है.

शहर भर में बड़े-बड़े अनावश्यक द्वार बनवाने वाला प्रशासन अगर हरकी पौड़ी तक पहुंचने वाली शहर के बीच की सड़क बनवा देता तो यात्रियों को सुविधा होती. सुविधा होती उन्हें, अगर पुलिस चौकी हरकी पौड़ी के नज़दीक के फर्श को सुंदर और समतल कर दिया जाता. सुविधा होती, अगर यात्रियों के जूता स्टाल को विस्तार देकर हरकी पौड़ी की पवित्रता को जूते-चप्पलों से अपवित्र करने से रोका जाता. हरकी पौड़ी पर बिजली के लटके और फैले तारों को अगर भूमिगत कर दिया जाता तो उस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से एक अच्छा संदेश जाता. काम को अधूरा छोड़ देने की पराकाष्ठा तो यह है कि गुरुकुल सिंहद्वार के पास नया नहर पुल तो बना दिया गया, पर मेले के एक सप्ताह पूर्व तक उस पर पहुंच मार्ग नहीं बनाए जा सके. आज तक यह सब नहीं किया गया और अब तो मेला निबट ही चला है.

इस बार हरिद्वार शहर और नव विकसित मेला क्षेत्र की गंदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है. इससे पहले के मेलों के साक्षी स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस बार गलियों-मुहल्लों की ही नहीं, मुख्य मार्गों की गंदगी भी ठीक से नहीं हटाई जा रही है. पिछले मेलों तक तो मक्खी-मच्छर विहीन कुंभ की चर्चा को साकार भी किया जाता था, पर इस बार कुंभ क्षेत्र के मक्खी-मच्छरों से कुंभ प्रशासन का कोई गुप्त समझौता हो गया लगता है. न मक्खियां हरिद्वार छोड़ने को तैयार हैं और न ही मच्छर. जगह-जगह कूड़े के ढेर अपनी कथा ख़ुद कह रहे हैं. हरिद्वार के उपनगरों ज्वालापुर, कनखल एवं भेल आदि को तो मानों कुंभ कार्यों और व्यवस्थाओं के नक़्शे से ही हटा दिया गया है. हरिद्वार-ज्वालापुर के बीच रेलवे लाइन के किनारे-किनारे शहर भर के कूड़े के लिए डंपिंग एरिया ज़रूर बना दिया गया है. गंगापार के द्वीपों में मेला क्षेत्र को विकसित करते हुए सौंदर्यबोध का अभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है. साधु-संतों के अस्थायी शिविर-बस्तियों तक पहुंचाने वाली एवं उन अस्थायी बस्तियों के बीच की सड़कों और उन पर सफाई का बुरा हाल है. गर्मियों की उड़ती धूल में आस्था ही है, जो श्रद्धालुओं को धूल और गंदगी भरी सड़कों पर लंबी-लंबी दूरियां तय करवा रही है.

चर्चा कुंभनगर की

पुलिस ने 13 अप्रैल को बैसाखी और 14 अप्रैल को मुख्य कुंभ स्नान के लिए नौ अप्रैल से ही अपना रोड प्लान लागू करने की घोषणा कर दी. इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय निवासियों सहित यात्रियों का हरकी पौड़ी तक पहुंचना अब मुहाल हो जाएगा. आपके पास अगर अधिक समय है और आप में लंबी दूरी पैदल तय करने की क्षमता है तो ही आप मंजिल तक पहुंच सकेंगे. वरना मीराबाई की ये पंक्तियां ही गुनगुनाते रहेंगे, गली तो चारों बंद हुई हैं, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए?

टेंटनगरों में आग के किस्से बार-बार हो रहे हैं. अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है तथा दर्ज़नों लोग झुलस कर घायल हो चुके हैं. लाखों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है. गनीमत है कि आग लगने की घटनाओं पर काबू पा लिया गया, वरना जन-धन की भारी हानि हो जाती. सरकारी नीतिगत आदेशों और घोषणाओं के बावजूद मेला क्षेत्र में वीआइपियों का आना नहीं रुक पा रहा है. हर रोज़ कहीं न कहीं से कोई न कोई विशिष्ट हस्ती कुंभनगर पहुंच कर व्यवस्थाओं में दख़ल देती है और आम व्यक्ति के यातायात को ध्वस्त करके लौट जाती है. आम आदमी और उसकी गाड़ियां घंटों का जाम झेलने को विवश हैं. परेशान यात्री और नगरवासी दोनों ही अब तक के कुंभ से आजिज़ आ चुके हैं, पर हम सबके ख़ून में घुली आस्तिकता यह सब सहज रूप से सहन और स्वीकार कर लेती है. गंगा मैया के दरस-परस से सब कुछ वरणीय हो जाता है. इस बार के कुंभ की एक विशेषता यह भी है कि उसे संभालने वाली उत्तराखंड पुलिस अनुभवी नहीं, किशोर पुलिस है. वह मेले की आत्मा और मर्यादा को समझने के स्थान पर उसे मौजमस्ती वाले मेले के रूप में अधिक ले रही है. लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुभवी पुलिसकर्मियों ने यह कमी पूरी कर दी है. फिर अन्यान्य सुरक्षाबलों के चुस्त-दुरुस्त जवानों से मेले और नगरवासियों को बहुत उम्मीदें हैं.

इस समय कुंभ का बूम है. हर वर्ग, वर्ण, संप्रदाय के हज़ारों साधु हरिद्वार में बसाए गए सैकड़ों तंबुओं में डेरा डाले हुए हैं. सर्वत्र भक्ति का वातावरण है. इस तंबू-शामियाने से लाउडस्पीकर सारे वातावरण में भजनिया धुनें बिखेर रहे हैं. कहीं रामकथा हो रही है तो कहीं भागवत चर्चा. कहीं रासलीला हो रही है तो कहीं राम, कृष्ण, शिव एवं हनुमान की झांकियां सज रही हैं.

देश भर से आने वाले आस्थावान जहां विभिन्न अखाड़ों में धूना रमाए नागाओं को देखने को आकुल-उत्सुक हैं, वहीं कुछेक साधु-संन्यासियों के शिविर भी भारी भीड़ खींच रहे हैं. इनमें वरिष्ठ संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि, जूनापीठाधीश आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरि, योगगुरु बाबा रामदेव, पायलट बाबा, सोहम बाबा, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी शिविर, विभिन्न शंकराचार्यों और रामानंदाचार्यों के शिविर, श्रीश्रीरविशंकर आदि प्रमुख हैं. बैसाखी पर मानव धर्म सम्मेलन आयोजित करने वाले सतपाल महाराज और आचार्य श्रीराम शर्मा का शांतिकुंज भी आस्थावानों की भीड़ जुटाने वालों में अग्रणी हैं.

इन और ऐसे अन्य सैकड़ों साधु-संतों और भावुक कुंभ यात्रियों की भावनाओं का दोहन करने के लिए भी यहां पूरे इंतज़ाम हैं. इस दिशा में विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे है. उसके नेता अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया इन दिनों तरह-तरह के सम्मेलन आयोजित करके राम मंदिर मुद्दे में नए प्राण फूंकने की तैयारी में हैं. विहिप के मार्गदर्शक मंडल की बैठकों में इन दिनों राम मंदिर के अलावा गोहत्या और गंगा के मुद्दे भी जोर पकड़े हुए हैं. विहिप के नेताओं को साधु-संतों की नब्ज़ भांपना, पकड़ना और उनसे अपने हित सधवा लेना बख़ूबी आता है. वे सब इन दिनों यहां एक बार फिर से साधु-संतों के कंधों पर रखकर अपनी बंदूकें चलाने की कोशिशों में मशगूल हैं.

बहरहाल, कोई अनहोनी न हुई तो अव्यवस्थाओं और अस्त-व्यस्तताओं के बीच 2010 का हरिद्वार कुंभ भी पूरा हो जाएगा और तब साधु-संत और उनके अखाड़े इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगला कुंभ प्रयाग कुंभ का होगा, जो 2013 में होना है.

kk@budhkar.in

अच्छी क्वालिटी का पिक्चर सीलिंग पर नज़र आने के लिए इसमें एडजस्टेबल फोकस के साथ ऑप्टिकल क्वालिटी के लेंस दिए गए हैं.

यह कैमरा है ख़ास

फुजीफिल्म इंडिया के महाप्रबंधक ए. राजकुमार व फुजीफिल्म इंडिया के प्रबंधक निदेशक कनीशी टनाका

फुज़ी फ़िल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने फोटो खींचने के अनुभव को ख़ास बनाने के लिए 14 नए प्रकार के डिजिटल कैमरे लांच किए हैं.

फुज़ीफ़िल्म द्वारा पेश ए सीरीज़ कॉम्पैक्ट (एवी 100, एवी 150, एएक्स 200 एवं एएक्स 250) के चार नए मॉडल में पहली बार शुरुआती स्तर पर हाई डेफिनिशन (एचडी) इमेज और वीडियो बनाने की सुविधा दी गई है. उपयोग में बेहद आसान ये कैमरे बेमिसाल हैं, अलग-अलग मेगापिक्सल रिजोल्यूशन के मिश्रण के साथ इन कैमरों के फुज़ीनॉन लेंस और एलसीडी स्क्रीन के साथ ग्राहकों को एक ऐसा कैमरा चुनने की आज़ादी होगी जो उनकी ज़रूरत और जेब दोनों लिहाज़ से ठीक हो. फुज़ीफ़िल्म की तमाम आधुनिक तकनीक जैसे ऑटोमैटिक सीन रिकगनीशन, फेस डिटेक्शन, डिजिटल इमेज स्टैबिलाइजेशन, उच्च स्तरीय आईएसओ सेंसिटिवीटी, पिक्चर सर्च (सीन मोड के अनुसार), और पैनोरमा शूटिंग मोड जिसकी मदद से तीन तस्वीरों को एक साथ जोड़ कर पैनोरमिक इमेज (चौड़े लैंडस्केप, बड़ी इमारतों या बड़े जन समूह के लिए फिट) प्राप्त किया जा सकता है.

फुज़ीफ़िल्म इंडिया के प्रबंध निदेशक केनीशी टनाका कहते हैं कि पालतू जानवर के शौकीन लोगों के लिए डॉग/पेट डिटेक्शन फीचर से लैस एफ80 ईएक्सआर मॉडल व एचएस 10 मॉडल में 30/ऑप्टिकल ज़ूम ख़ास व आधुनिक है.

फुज़ीफ़िल्म ने जे सीरीज़ कैमरों के चार स्लीक मॉडल (जेवी 100, जेवी150, जेएक्स200 और जेएक्स250) को पेश किया. इनसे हाई डेफनिशन तस्वीरें ली जा सकती हैं. फुज़ीफ़िल्म के बेहद चर्चित फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से चेहरे पर मुस्कान आते ही कैमरे का स्माइल एण्ड शूट मोड अपना कमाल दिखाता है. एक अन्य ख़ूबी ब्लिंक डिटेक्शन है. नए जेवी और जेएक्स मॉडल में एक नया फीचर भी है टार्गेटिंग एएफ जिसकी मदद से किसी गतिशील वस्तु की सटीक तस्वीर ली जा सकती है.

फुज़ीफ़िल्म ने एक लांग-ज़ूम कॉम्पैक्ट कैमरा- फाइनपिक्स जेजैड300 भी पेश किया है जिसमें स्टाइल है और किफ़ायती भी है. अपने 10/ऑप्टिकल ज़ूम, 28 मिमी वाइड-एंगल लेंस, आधुनिक सीसीडी-शिफ्ट इमेज स्टैबिलाइजेशन सिस्टम, एचडी इमेज और मूवी पिक्चर, 2.7इंच एलसीडी स्क्रीन और 12 मेगापिक्सल रिजॉल्यूशन के साथ जेजैड 300 इस श्रेणी का सर्वश्रेख़कैमरा है. इस कैमरे की अन्य ख़ास ख़ूबियों में टार्गेटिंग एएफ, सीन रिकग्निशन ऑटो, पिक्चर सर्च हैं. सोशल नेटवर्किंग यानी फेसबुक पर इमेज अपलोड करने या यूट्यूब पर वीडियो शेयर करने की ख़ास ख़ूबी वाला फुज़ीफ़िल्म का फाइनपिक्सजेड 700 कैमरा बढ़िया है.

हेलो किट्टी ले आइए अपना कलेक्शन बढ़ाइए

डिज़ाइनर कपड़े, डिज़ाइनर फुटवियर, डिज़ाइनर एक्सेसरीज और ना जाने क्या-क्या. फैशन जगत के बढ़ते प्रभाव ने खिलौनों और किताब-कॉपियों को भी नहीं छोड़ा है. ऐसे में भला तकनीक और तकनीकी उपकरण कैसे पीछे रह सकते हैं. जल्दी ही आप देखेंगे कि डिज़ाइनर सीडी कवर, डिज़ाइनर डेस्कटॉप और अब डिज़ाइनर फ्लैशड्राइव मार्केट में उपलब्ध होगा. जापान की प्रसिद्ध ऐनिमेशन आइकन हेलो किट्टी ने इस वर्ष अपने 35वें वर्षगांठ पर हेलो किट्टी के प्रशंसकों के लिए मिमोबॉट यानी डिज़ाइनर खिलौना यूएसबी फ्लैशड्राइव ला रही है. इसका मतलब है कि अब यूएसबी ड्राइव भी हेलो किट्टी के रूप में डिज़ाइनर होगा. 2.5 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई वाला डिज़ाइनर हेलो किट्टी की तीन वेरायटी यूएसबी अनेक आकर्षक विशेषताओं के साथ उपलब्ध है. रंग-बिरंगी हेलो किट्टी फ्लैश ड्राइव के तीन ख़ूबसूरत रूप बाज़ार में उपलब्ध हैं. इनमें लाल रंग में हेलो किट्टी एपल, हरे रंग में हेलो किट्टी फन इन फील्डस और सफेद रंग में हेलो किट्टी एक्स मॉडल हैं. इनकी क्षमता क्रमश: 2 जीबी, 4 जीबी और 8 जीबी है. हाईस्पीड यूएसबी 2.0 है. इसके अलावा इसमें प्रीलोडेड डीजिटल मेमोरी है जिसमें आप अवतार व अन्य वॉलपेपर और डेस्कटॉप आइटम देख सकते है. ये ख़ास स्क्रीनसेवर्स, वॉलपेपर्स और डेस्कटॉप आईकन केवल हेलो किट्टी मिमोबॉट फ्लैशड्राईव में ही उपलब्ध हैं. कंपनी ने हेलो किट्टी मिमोबॉट फ्लैशड्राईव की क़ीमत 25 अमरीकी डॉलर रखी है. इसके उपयोग के लिए आपके कंप्यूटर और दूसरे उपकरणों में डाटा ट्रांसफर के लिए क्यूट हेलो किट्टी का फ्लैसडिस्क उपयुक्त होगा.

घर में चांदनी रात हो

आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो..., जैसे ना जाने कितने रोमांटिक गानों में चांदनी रातों की ख़ूबसूरती का ज़िक्र है. इन गानों को सुनते ही हम ऐसी रातों की कल्पना करने लगते हैं, पर ये कल्पनाएं तब टूट जाती हैं जब हमें अहसास होता है हम भीड़-भाड़ वाले शहर में डब्बेनुमा घर यानी फ्लैट में रहते हैं. वो दिन लद गए कि जब खुले आसमान के नीचे लेट कर हम प्रकृति का आनंद लेते थे. पर ऐसे ही मनोरम क्षणों का अहसास कराने के लिए स्टार थियेटर प्रो होम प्लैन्टेरियम ने एक कृत्रिम कॉसमोस यानी ब्रह्मांड निर्मित किया है जिसमें सिर्फ़ एक बटन दबाने से ही आप चांदनी रात का आनंद उठा सकते हैं.

स्टार थियेटर प्रो होम प्लैनेटोरियम एक छोटा ऑप्टिकल स्टार प्लैनेटोरियम है जिसे आप अपने घर में भी लगा सकते है. इसमें आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप खुले ब्रह्मांड के नीचे है. एक अंधेरे कमरे में स्टार प्लेनेटेरियम को ऑन करके इसकी फ्लैश लाईट दीवार की सीलिंग की तरफ़ करें तो ऐसा लगता है कि जैसे सर के ऊपर सीलिंग नहीं सितारों की छावनी हो. इन सितारों को आप अपनी उंगलियों पर नचा भी सकते हैं, ये सितारे दस मिनट में 1 चक्कर पूरा करते है. इसके अलावा इसमें नैप टाइमर भी है, यानी आप टाइमर लगाकर सुस्ताते हुए सो जाएं और सेट किए वक़्त पर यह अपने आप बंद हो जाएगा.

अच्छी क्वालिटी का पिक्चर सीलिंग पर नज़र आने के लिए इसमें एडजस्टेबल फोकस के साथ ऑप्टिकल क्वालिटी के लेंस दिए गए हैं, और नैचुरल लाईटिंग के लिए तेज़ चमकदार सफेद लेड लाईट दी गई है. इसमें एडजस्टेबल प्रोजेक्शन एंगल और ईमेज रोटेशन के विकल्प भी उपलब्ध हैं. बिजली न रहने पर यह होम प्लैनेटोरियम बैट्री से भी चलता है.

ज़माना है माइलस्टोन फोन का

आधुनिक तकनीक से बने मोबाईल फोन का शौक किसे नहीं होगा. ऐसे ही तकनीक के शौक़ीन लोगों के लिए मोबाइल कंपनी मोटोरोला ने नया माइलस्टोन फोन बाज़ार में उतारा है जो मल्टी टास्किंग की ख़ूबियों से लैस है. यह मोबाइल यूजर्स और लवर्स को गूगल मोबाइल सेवाओं का संपूर्ण पैकेज उपलब्ध कराता है, जिसमें गूगल सर्च, गूगल मैप, जीमेल, और यूट्यूब शामिल हैं. इसके अलावा आप एंड्रॉयड मार्केट की हज़ारों एप्लीकेशंस और विजेट्स का लाभ भी उठा सकते है. इससे शहरों और प्रमुख राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गो पर सड़कों की आवाज़ निर्देशित जानकारी मिलती है. इसकी सहायता से शानदार होटलों, पेट्रोल पंपों, खाने के स्थानों, एटीएम, अस्पतालों और पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को आसानी से खोजा जा सकता है. इसमें जीपीएस नेविगेशन सेवा फ्री है और इसके लिए कोई डाटा चार्ज नहीं लगता. यह मोबाइल के नेटवर्क से भी मुक्त है और इसे सिम डाले बिना भी उपयोग में लाया जा सकता है क्योंकि नक्शे माइलस्टोन पर पहले से पूरी तरह लोड कर दिए गए हैं. 3.7 इंच की स्क्रीन, 854 पिक्सल की चौड़ाई पर हाई रिजोल्यूशन पिंच एंड ज़ूम डिसप्ले भी है. जिसपर पूर्ण स्क्रीन का वेब ब्राउजिंग किया जा सकता है. इसकी ख़ास विशेषता है इसका एंड्रॉयड 2.1 पावर. भारत में मोटोरोला के प्रमुख फैज़ल सिद्दिकी ने बताया कि माइलस्टोन एक स्मार्ट फोन है और इसके द्वारा वेब एवं मैसेजिंग भी किया जा सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि यह समझदार और सामाजिक रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए है. इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इस पर आप विभिन्न एप्लीकेशनों को एकसाथ इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी विशेषताओं में 5 मेगा पिक्सल कैमरा, डूएल एलईडी फ्लैश, ऑटो फोकस और इमेज स्टेब्लाइजेशन है. इसके अलावा स्टीरियो ब्लूटूथ/बीटी 2.1, यूएसबी 2.0 हाई स्पीड क्रिस्टल टॉक प्लस से श्रेष्ठ टॉक क्वालिटी और 8 जीबी की एक्सपैंडेबल मैमरी कार्ड हैं. मोटोरोला का यह माइलस्टोन फोन चुने हुए रिटेल आउटलेट्स पर 32,990 रुपये में उपलब्ध हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मोबाइल चला गांव की ओर

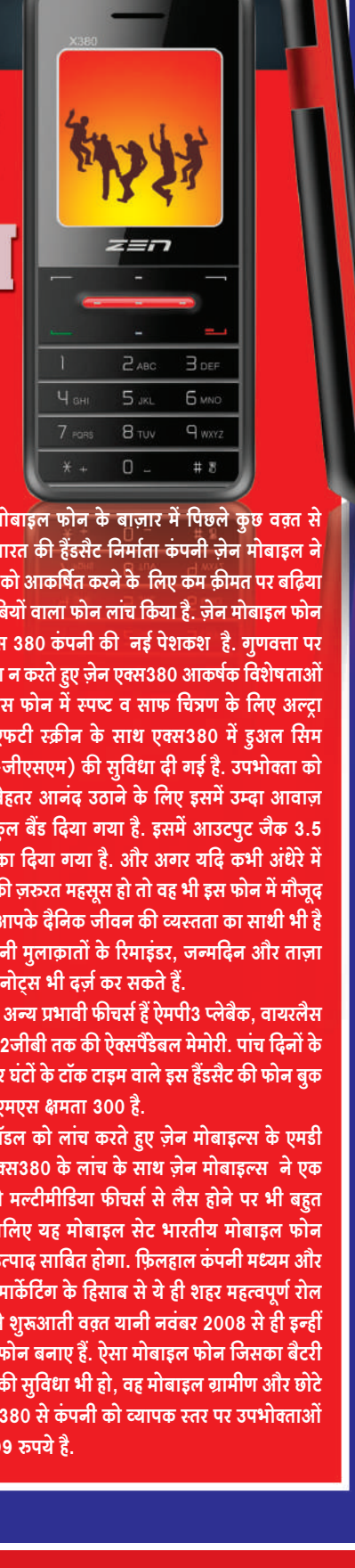

भारतीय मोबाइल फोन के बाज़ार में पिछले कुछ वक़्त से उभरी भारत की हैंडसैट निर्माता कंपनी ज़ेन मोबाइल ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम क़ीमत पर बढ़िया और ज़्यादा ख़ूबियों वाला फोन लांच किया है. ज़ेन मोबाइल फोन का मॉडल एक्स 380 कंपनी की नई पेशकश है. गुणवत्ता पर कोई समझौता न करते हुए ज़ेन एक्स380 आकर्षक विशेषताओं से लैस है. इस फोन में स्पष्ट व साफ चित्रण के लिए अल्ट्रा क्लैरिटी टीएफटी स्क्रीन के साथ एक्स380 में डुअल सिम (जीएसएम+जीएसएम) की सुविधा दी गई है. उपभोक्ता को संगीत का बेहतर आनंद उठाने के लिए इसमें उम्दा आवाज़ वाला पावरफुल बैंड दिया गया है. इसमें आउटपुट जैक 3.5 एमएम जैक का दिया गया है. और अगर यदि कभी अंधेरे में आपको टॉर्च की ज़रुरत महसूस हो तो वह भी इस फोन में मौजूद है. एक्स380 आपके दैनिक जीवन की व्यस्तता का साथी भी है इसमें आप अपनी मुलाक़ातों के रिमाइंडर, जन्मदिन और ताज़ा तरीन मौक़ों के नोट्स भी दर्ज़ कर सकते हैं.

एक्स380 के अन्य प्रभावी फीचर्स हैं ऐमपी3 प्लेबैक, वायरलैस एफएम रेडियो और 2जीबी तक की ऐक्सपैंडेबल मेमोरी. पांच दिनों के स्टैंड बाई टाइम व चार घंटों के टॉक टाइम वाले इस हैंडसैट की फोन बुक क्षमता 500 और एसएमएस क्षमता 300 है.

इस नए नवेले मॉडल को लांच करते हुए ज़ेन मोबाइल्स के एमडी दीपेश गुप्ता ने कहा कि एक्स380 के लांच के साथ ज़ेन मोबाइल्स ने एक ऐसा हैंडसैट पेश किया है जो मल्टीमीडिया फीचर्स से लैस होने पर भी बहुत कम क़ीमत पर उपलब्ध है. इसलिए यह मोबाइल सेट भारतीय मोबाइल फोन बाज़ार में एक अच्छा और उपयोगी उत्पाद साबित होगा. फ़िलहाल कंपनी मध्यम और छोटे शहरों को लक्ष्य कर रही है क्योंकि मार्केटिंग के हिसाब से ये ही शहर महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे. उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपने शुरूआती वक़्त यानी नवंबर 2008 से ही इन्हीं शहरों के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन बनाए हैं. ऐसा मोबाइल फोन जिसका बैटरी बैकअप मज़बूत हो और अन्य सुविधाओं के साथ टॉर्च की सुविधा भी हो, वह मोबाइल ग्रामीण और छोटे शहरों में बहुत काम का साबित होता है. इस नए मॉडल एक्स380 से कंपनी को व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी. इस ख़ास फोन की क़ीमत सिर्फ़ 1399 रुपये है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

युवा माइकल क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज है.

टी-20 वर्ल्ड कप : दावे में है दम

आदित्य पूजन

आईपीएल का तीसरा सीजन अभी अपने पूरे शबाब पर है. अंकतालिका में एक-दूसरे से ऊपर पहुंचने के लिए टीमों के बीच होड़ लगी है तो हर मुक़ाबले के बाद जीत का एक नया नायक उभर कर सामने आ रहा है. यहां राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, फिर भी क्रिकेट और ग्लैमर का यह संगम हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ की तरह देशवासियों के दिलोदिमाग़ पर पूरी तरह छाया हुआ है. लेकिन इस सबके बीच क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें कहीं और भी टिकी हैं. उन्हें इंतज़ार है 30 अप्रैल से शुरू हो रहे टी-20 वर्ल्ड कप का, जब 12 देशों के खिलाड़ी एक साथ जमा होंगे और फिर फ़ैसला होगा कि टी-20 की दुनिया का असली सरताज कौन है.

वेस्टइंडीज में आयोजित हो रहे तीसरे टी-20 वर्ल्ड कप के लिए सभी देशों ने अपनी-अपनी टीमों की घोषणा कर दी है. इनमें से अधिकांश खिलाड़ी तो फ़िलहाल आईपीएल में व्यस्त हैं, लेकिन साथ ही वे वर्ल्ड कप के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं. चार ग्रुपों में बंटी 12 टीमों पर नज़र डालने भर से इस प्रतियोगिता के प्रति उनकी गंभीरता का पता चलता है. सभी देशों की टीमों में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो फटाफट क्रिकेट के इस नवीनतम संस्करण के पैमाने पर खरे उतरते हैं. क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में योग्यता की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन टी-20 में साहस और जीत के जज़्बे का भी अपना अलग महत्व होता है. शायद यही वजह है कि एल्बी मोर्केल, युसुफ पठान, किरॉन पोलार्ड एवं डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी, जिन्हें टेस्ट या वनडे क्रिकेट में अक्सर राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधित्व से वंचित रहना पड़ता है, टी-20 में अपनी-अपनी टीमों के अहम सदस्य हैं और टीम की जीत-हार का दारोमदार काफी कुछ उनके कंधों पर होता है. लेकिन इन सबके बीच महत्वपूर्ण सवाल यह है कि टी-20 क्रिकेट के इस महाकुंभ के लिए भारतीय टीम की तैयारी कैसी है. क्या धोनी के धुरंधरों से हम एक और विश्व कप में खिताबी जीत की उम्मीद लगा सकते हैं?

सबसे पहले नज़र डालते हैं इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई भारतीय टीम पर. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली इस टीम में कई खिलाड़ी हालांकि छोटी-मोटी चोटों से परेशान हैं, लेकिन हमें यह मानने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि चुनी गई टीम फ़िलहाल सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध टीम है. टीम में युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और हरभजन सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो सुरेश रैना, रोहित शर्मा, युसुफ पठान और विनय कुमार जैसे युवा खिलाड़ियों को भी इसमें जगह दी गई है. टीम की गेंदबाज़ी आक्रमण का

फोटो-प्रभात पाण्डेय

दारोमदार ज़हीर ख़ान और हरभजन सिंह के अनुभवी कंधों पर होगा तो उनका साथ देने के लिए आशीष नेहरा, प्रवीण कुमार और पीयूष चावला भी मौजूद हैं. हालांकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में टीम इंडिया की वास्तविक शक्ति उसकी बल्लेबाज़ी होती है और चयन समिति ने इसका ख़ास खयाल रखा है, पर बॉलरों पर भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है. ऐसे में आशीष नेहरा के चयन पर उंगली उठ सकती है. वह जिस गति से अपने ओवरों में शार्ट पिच गेंदें फेंककर बल्लेबाज को रन बनाने का पूरा मौक़ा देते हैं, उससे कई बार कप्तान को बड़ी परेशानी होती है, ऐसा उनके चेहरे से लगता है. फिर भी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के रूप में टीम के पास सलामी बल्लेबाज़ों की ऐसी विस्फोटक जोड़ी मौजूद है, जो अकेले दम पर किसी भी मुक़ाबले का रुख़ बदलने का माद्दा रखती है. इसके बाद सुरेश रैना, युवराज, रोहित शर्मा और धोनी के रूप में टीम के पास ऐसा बैटिंग ऑर्डर है, जो किसी भी गेंदबाज़ी आक्रमण को निस्तेज कर सकता है. ऑलराउंडर की भूमिका के लिए चुने गए युसुफ पठान और रवींद्र जडेजा गेंद और बल्ले, दोनों के साथ अपने जलवे बिखेर सकते हैं.

काग़ज़ पर बेहद मज़बूत दिखने वाली इस टीम से खिताब की उम्मीद लगाना बेमानी नहीं है, बशर्ते टीम अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने में कामयाब हो. हालांकि इसके बावजूद टीम इंडिया की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि भारत के अलावा कम से कम तीन ऐसी टीमें हैं, जो मौजूदा फॉर्म के लिहाज़ से खिताब की प्रबल दावेदार हैं और जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और पिछली बार चैंपियन बने पाकिस्तान की टीम शामिल है.

युवा माइकल क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज है. टी-20 मैचों में टीम का हालिया प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है. साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक टी-20 के पांच मुक़ाबलों में शिरकत की है और उसे केवल एक में हार का सामना करना पड़ा. वह भी बॉल आउट में. हालांकि प्रमुख गेंदबाज़ों की कमी से टीम का गेंदबाज़ी आक्रमण थोड़ा कमज़ोर दिखता है, लेकिन चोट के बाद वापसी कर रहे ब्रेट ली यदि अपनी खोई लय हासिल करने में कामयाब होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी भी टीम के लिए टे खीर साबित हो सकता है. खिताब की दूसरी प्रबल दावेदार टीम दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि फरवरी के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबला नहीं खेला है, लेकिन टीम के अधिकांश खिलाड़ी आईपीएल में अपना जौहर दिखा रहे हैं. गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी में एक समान रूप से संतुलित दिखने वाली इस टीम में ग्रीम स्मिथ, हर्शेल गिब्स, डी विलियर्स और डेल स्टेन जैसे मैच जिताऊ खिलाड़ी मौजूद हैं. हालांकि, विश्व कप की शुरुआत से पहले हर बार दक्षिण अफ्रीकी टीम को प्रबल दावेदार माना जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आख़िरी पड़ाव पर यह टीम अपनी हिम्मत हार जाती है. वेस्टइंडीज में यदि टीम अपनी इस कमज़ोरी पर काबू पाने में कामयाब रही तो उसे खिताब से दूर करना मुश्किल हो सकता है.

इंग्लैंड में 2009 में खेले गए दूसरे टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था. यूनिस ख़ान की कप्तानी में पाक टीम ने हर मुश्किल को लांघते हुए श्रीलंका को फाइनल मुक़ाबले में शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया था. हालांकि, मैच फिक्सिंग और अनुशासनहीनता के आरोपों के बाद कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को इस बार टीम में जगह नहीं दी गई है. साथ ही टीम में गुटबाज़ी की ख़बरें भी आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को कम करके आंकने की ग़लती हम नहीं कर सकते. यदि सब कुछ ठीकठाक रहा तो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से सजी यह टीम कभी भी अपने प्रदर्शन से आश्चर्यचकित कर सकती है.

ज़ाहिर है, खिताब जीतने की मंशा लिए वेस्टइंडीज जाने वाली टीम इंडिया की राह इतनी आसान नहीं होगी. हालांकि, टीम के क़रीब-क़रीब सभी खिलाड़ी आईपीएल में शिरकत कर अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहना रहे हैं, लेकिन धोनी, युवराज और सहवाग जैसे बल्लेबाज़ अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे हैं. चोटिल खिलाड़ियों की समस्या तो है ही. भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वेस्टइंडीज की पिचें भारतीय उपमहाद्वीप की पिचों से काफी मिलती-जुलती हैं. इन पिचों पर तेज़ गेंदबाज़ों के लिए ज़्यादा मदद नहीं होती, जबकि स्पिन गेंदबाज थोड़ा-बहुत घुमाव मिलने की उम्मीद कर सकते हैं. भारत के पास हरभजन सिंह के रूप में विश्वस्तरीय स्पिनर मौजूद है और पीयूष चावला भी उनका भली भांति साथ दे सकते हैं. भारत को दक्षिण अफ्रीका और अफ़ग़ानिस्तान के साथ ग्रुप सी में रखा गया है और सुपर 8 में अपनी जगह बनाने के लिए इसे ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए. लेकिन असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होगी जब अफ़ग़ानिस्तान और आयरलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमज़ोर टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी और सेमीफाइनल में जगह बनाने को लेकर रस्साकसी होगी.

यदि इस मुक़ाम पर टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बरक़रार रखते हुए युवा खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने में कामयाब हुए तो टीम इंडिया दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 19 अप्रैल–25 अप्रैल 2010

बाबू जी ज़रा धीरे चलो से चर्चा में आईं याना आजकल सिंगल हैं और अपने करियर को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश में लगी हुई हैं.

मुझे ख़ुद से प्यार है

बॉलीवुड में इस समय विदेशी बालाओं की एंट्री ज़ोरों पर हैं. सलमान ख़ान की खोज कैटरीना एवं ज़रीन ख़ान से लेकर रामू की जिया एवं निगार ख़ान तक, सभी बॉलीवुड में अपनी दुकान जमाए हुए हैं. एक वक़्त था, जब सिर्फ़ हेलन ही थीं, जो इन विदेशी बालाओं की जगह अकेले टिकी थीं. पर अब समय बदल चुका है. सांग सीक्वेंस पर पीछे नाचने वाली जूनियर आर्टिस्ट से लेकर लीड हीरोइन तक के रोल में कई अलग-अलग विदेशी सुंदरियों को आज़माया जा रहा है. इस दौर की शुरुआत जिन विदेशी तारिकाओं ने की थी, उनमें एक याना गुप्ता भी थीं. बाबू जी ज़रा धीरे चलो से चर्चा में आईं याना आजकल सिंगल हैं और अपने करियर को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश में लगी हुई हैं. इंडिया आने की वजह बताते हुए याना भावुक हो जाती हैं. कहती हैं कि वह भारत मॉडलिंग के उद्देश्य से आई थीं, लेकिन अब यहीं की होकर रह गई हैं. यहीं पर उन्हें अपना पहला प्यार और पति मिला. ग़ौरतलब है कि याना ने भारतीय पेंटर सत्यकाम गुप्ता से शादी की थी. इसी के बाद उन्होंने अपना सरनेम गुप्ता जोड़ा था. लेकिन अब जबकि दोनों में अलगाव हो चुका है तो याना अपना सरनेम हटाना चाहती हैं. उनके मुताबिक़, हम दोनों का तलाक हो चुका है और अब मुझे सिर्फ़ याना के नाम से जाना जाए. हालांकि शादी टूटने के बाद उनका अफेयर आफताब शिवदासानी के साथ भी कई दिनों तक चला, पर यह रिश्ता किसी मुक़ाम तक पहुंचने से पहले ही टूट गया. फ़िलहाल याना सिंगल हैं और प्यार के मामले में किसी साथी के बजाय ख़ुद से कनेक्ट रहना पसंद करती हैं.

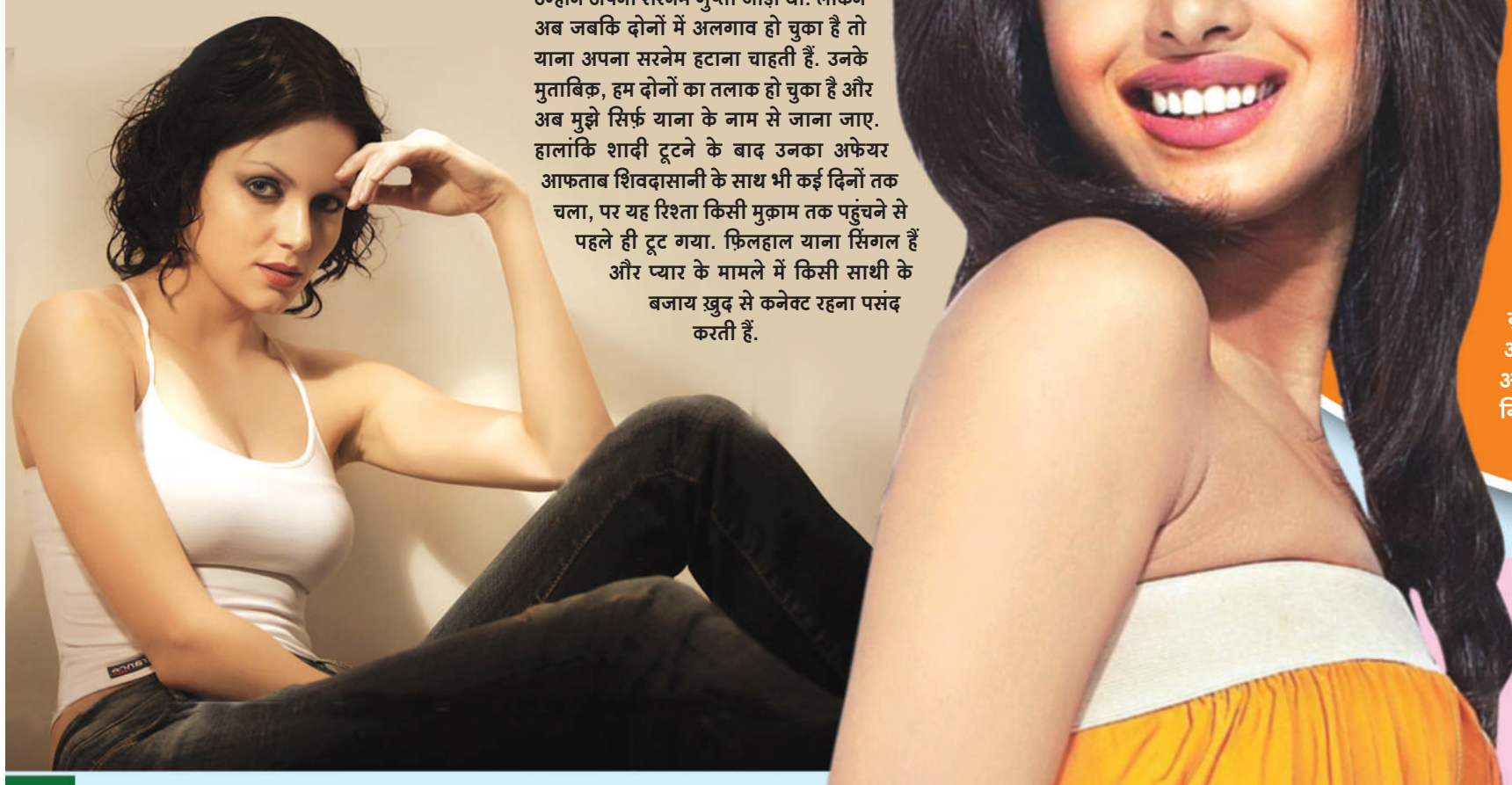

सात ख़ून करके प्रियंका चली ब्राजील की ओर

प्रियंका चोपड़ा की इन दिनों चांदी ही चांदी है. उनकी झोली में बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं. अब उन्होंने विज्ञापन और टीवी जगत में घुसपैठ का इरादा बना लिया है. इसलिए एक के बाद एक विज्ञापन के ज़रिए उन्होंने मोटी रक़म वसूली. अब वह कलर्स के हिट सीरियल ख़तरों के खिलाड़ी सीजन-3 में बतौर एंकर पेश होने जा रही हैं. सुना है, अक्षय कुमार को रिप्लेस करने के बदले कलर्स ने उन्हें अच्छे-खासे अमाउंट पर साइन किया है. ग़ौरतलब है कि प्रियंका अभी हाल में विशाल भारद्वाज की फ़िल्म सात ख़ून माफ की शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर में थीं. फ़िल्म एतराज के बाद वह एक बार फिर इस फ़िल्म में निगेटिव किरदार में नज़र आएंगी. प्रियंका के मुताबिक़, इस फ़िल्म में उन्हें वह सब करने को मिल रहा है, जो उनके अब तक के करियर में नहीं मिला. प्रियंका कहती हैं कि इस फ़िल्म में उनके स्पेशल मेकअप के लिए हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म पाइरेट ऑफ कैरेबियंस की टीम बुलाई गई है. सात ख़ून माफ में उनके अपोजिट सात कलाकार होंगे, जिनमें इरफान खान भी हैं. फ़िल्म का शेड्यूल निपटा कर प्रियंका सीधे ब्राजील के लिए रवाना होंगी. अगर आप सोच रहे हैं कि प्रियंका छुट्टियां मनाने के इरादे से ब्राजील जा रही हैं तो यह ग़लत है. दरअसल, प्रियंका का यह ब्राजील ट्रिप ख़तरों के खिलाड़ी के लिए है. वह अपनी टीम के साथ ब्राजील की ख़ूबसूरत लोकेशंस पर डेडली स्टंट करती हुई नज़र आएंगी. इस ट्रिप से प्रियंका को डबल फ़ायदा है. पहला यह कि वह शूटिंग निपटाएंगी और दूसरा यह कि इसी बहाने मुफ्त में सैरसपाटा भी हो जाएगा. मतलब यह कि कश्मीर में सात ख़ून करके मैडम ब्राजील को चली हैं.

कभी-कभी कमर्शियल फ़िल्में भी करता हूं : राहुल बोस

राहुल बोस जब भी किसी फ़िल्म में अभिनय करते हैं, वह चर्चा का विषय बन जाती है. उनकी ऐसी ही एक आने वाली फ़िल्म है जैपनीज वाइफ. संगीत कंपनी सारेगामा द्वारा निर्मित इस फ़िल्म की निर्देशिका हैं अपर्णा सेन. लेखक कुणाल बसु के उपन्यास पर आधारित इस फ़िल्म में राहुल के साथ राइमा सेन एवं जापानी अभिनेत्री चिगुसा तकाकू मुख्य भूमिका निभा रही हैं. पिछले दिनों राहुल से एक लंबी बातचीत हुई. पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

सबसे पहले आप फ़िल्म जैपनीज वाइफ के बारे में बताएं.

यह एक स्कूल शिक्षक की कहानी है. उसकी शादी को 17 साल हो चुके हैं. यह फ़िल्म पति-पत्नी के बीच समर्पण, प्यार, ख़ुशी और उनके दुःख की है.

ऐसा क्या विशेष था कि आपने इसमें काम करना पसंद किया?

मुझे इसकी कहानी ने बहुत प्रभावित किया. एक अनोखी प्रेम कहानी है इसमें. आजकल ऐसी प्रेम कहानियां कहां देखने- सुनने को मिलती हैं. अपर्णा सेन इसे निर्देशित कर रही थीं तो जैसे सोने पे सुहागा वाली बात हो गई.

क्या इस फ़िल्म के लिए आपको अवार्ड की उम्मीद है?

मैं कोई भी फ़िल्म केवल इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई अवार्ड मिले. मैं उन्हीं फ़िल्मों में काम करना पसंद करता हूं, जिनसे मुझे संतुष्टि मिलती है.

अभिनय के अलावा और क्या करते हैं?

मुझे रग्बी खेलना पसंद है, लिखने का शौक़ है, सामाजिक कार्यों में मेरी दिलचस्पी है. हाल में ही मैंने बांग्ला फ़िल्म अनुरारन में एक गीत गाया है. कुल मिलाकर कुछ न कुछ नया करने की फिराक में रहता हूं.

हिंदी फ़िल्मों के लिए कोई गाना नहीं गाया अब तक?

दरअसल मुझे हिंदी गाने पसंद नहीं हैं. मुझे अंग्रेजी गाने पसंद हैं और वैसे भी मैंने बांग्ला फ़िल्म में इसलिए गाया कि वह उस फ़िल्म की ज़रूरत थी.

आपने हास्य से लेकर कला फ़िल्मों तक काम किया है. आगे किस तरह की फ़िल्में करना चाहेंगे?

मैं ऑफबीट फ़िल्में करना पसंद करता हूं, जिनमें कुछ सामाजिक संदेश भी हों. कभी-कभी कमर्शियल फ़िल्में भी करता हूं, जिनमें मोरालिटी हो. मणिरत्नम और शेखर कपूर के साथ फ़िल्म करने की ख्वाहिश है. इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में एक्शन फ़िल्म करना चाहूंगा, जिसका मौक़ा मुझे अब तक नहीं मिल पाया है.

आज के दौर में देखा जा रहा है कि कई फ़िल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित होती हैं. क्या फ़िल्म बनाने के लिए कहानियों की कमी पड़ गई है या इंडस्ट्री में इस दिशा में टैलेंट की कोई कमी है?

कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जो पढ़ते वक़्त मन में बस जाती हैं. अगर एक फ़िल्म डायरेक्टर को कोई भी किताब पढ़ते वक़्त उसकी कहानी मन को छू जाती है और वह महसूस करता है कि इसे दुनिया के सामने लाया जाए तो वह उसे फ़िल्म का रूप दे देता है. इसका फ़ायदा लोगों को भी है कि उन्हें उनकी पसंदीदा कहानी का विजुअल ट्रीट देखने को मिल जाता है.

आने वाली फ़िल्में?

एक हॉरर फ़िल्म है, जिसका नाम तय नहीं हुआ है. इसके अलावा मुंबई चकाचक और आई एम एंड कुछ लव जैसा मेरी आने वाली फ़िल्में हैं.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

स्मृति शेष: गुलशन बावरा

मेरे देश की धरती सोना...

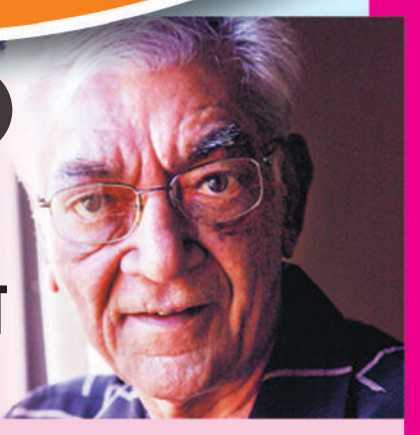

वर्ष 1973 में आई फ़िल्म जंजीर का वह दृश्य याद कीजिए, जिसमें एक जोशीला नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर (अमिताभ बच्चन) सड़क हादसे में स्कूली बच्चों की मौत की गवाह एवं चाकू-छुरी में धार रखकर अपना जीवनयापन करने वाली लड़की (जया भादुड़ी) को अपने घर में शरण देता है. इसी दौरान एक दिन दोनों कमरे की खिड़की पर खड़े होते हैं, तभी बाहर सड़क पर दो स्ट्रीट सिंगर हारमोनियम और ढोलक के सहारे फिज़ा में संगीत का रस घोल रहे होते हैं. इन स्ट्रीट सिंगर्स के गीत के बोल क्या हों, जो इन दोनों के दिलों के तारों को छेड़ दें, जिनके बीच तब प्यार नामक कोई चीज़ थी ही नहीं! यही चुनौती थी किसी गीतकार के लिए इस दृश्य में. इस चुनौती को हंसते-हंसते स्वीकार किया था गीतकार गुलशन बावरा ने और फिर गीत जन्मा था, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए...बस मुहब्बत भरी एक नज़र चाहिए. किसी भी सिचुएशन और किसी भी मूड के गीत को बिना हिचक-झिझक और सद्अर्थी लिखने वाले इस फनकार यानी गुलशन बावरा ने 72 वर्ष की अवस्था में पिछले साल यानी 7 अगस्त 2009 की सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.

लाहौर (पाकिस्तान) से 30 किलोमीटर दूर शेखूपुरा में अप्रैल 1937 को जन्मे गुलशन बावरा का असली नाम गुलशन कुमार मेहता था. उनके पिता भवन निर्माण के व्यवसाय से संबद्ध थे. उनका परिवार देश विभाजन के बाद हुए दंगे का शिकार हो गया था. गुलशन की आंखों के सामने ही उनके माता-पिता दंगाइयों के हाथों मारे गए थे. काफी दूर तक पैदल, फिर सेना के ट्रक द्वारा वह अपने बड़े भाई के साथ जयपुर पहुंचे, जहां उन्हें उनकी बड़ी विवाहित बहन ने अपने घर में शरण दी. धीरे-धीरे वक़्त ने करवट ली और फिर बड़े भाई की नौकरी लगने के बाद गुलशन दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने पहले मैट्रिक और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की. कॉलेज जीवन के दौरान ही गुलशन ने ज़ोर-शोर से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं. यूं तो वह छह वर्ष की आयु से ही कविता लिखा करते थे और माता विद्यावती के साथ भजन कार्यक्रमों में बड़े चाव से हिस्सा लिया करते थे. गुलशन फ़िल्मी दुनिया में अपनी क़िस्मत आज़माना चाहते थे. ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन किया. परीक्षा-साक्षात्कार में वह सफल भी हुए और उन्हें कोटा में नियुक्त किया गया. लेकिन, जब गुलशन वहां पहुंचे तो जगह भर चुकी थी. उन्हें अगला मौक़ा मिला 1955 में और संयोग से उनकी नियुक्ति हुई मायानगरी मुंबई में. यहां आने के बाद उन्होंने नौकरी करने के साथ ही फ़िल्मों में काम पाने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी. बतौर गीतकार गुलशन को पहला मौक़ा 1959 में दिया कल्याण जी वीरजी शाह (आनंद जी के जोड़ीदार) ने, फ़िल्म चंद्रसेना में. गीत था, मैं क्या जानूं कहां लागे यह सावन मतवाला रे... इसे आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने. इसके बाद इसी वर्ष एक फ़िल्म और आई, सट्टा बाज़ार. यह कल्याण जी-आनंद जी की पहली संयुक्त फ़िल्म थी. इसमें गुलशन की कलम ने जमकर कमाल दिखाया और तुम्हें याद होगा, कभी हम मिले थे..., आंकड़े का धंधा... और चांदी के चंद टुकड़ों के लिए... जैसे गीत तब देखते ही देखते लोगों की ज़ुबान पर छा गए थे.

वर्ष 1961 में गुलशन ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह गीत लेखन में ही जुट गए. यह वह समय था, जब हिंदी फ़िल्म जगत में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जैसे गीतकारों की तूती बोलती थी. अपने 42 साल के करियर में गुलशन बावरा ने 240 गीत रचे. वह बहुत ज़्यादा काम करने में विश्वास नहीं रखते थे. लेकिन, अपने काम के साथ उन्हें कोई भी समझौता मंजूर नहीं था और न ही दाम यानी मेहनताने के साथ. वह अपने समय के सबसे महंगे गीतकार माने जाते थे. उस समय वह एक फ़िल्म के गीत लिखने के लिए 90 हज़ार रुपये लिया करते थे, जब एक बड़ा और अच्छा फ्लैट केवल 65 हज़ार रुपये में मिल जाता था मुंबई में. गुलशन के आधे से ज़्यादा गीतों को संगीत से संवारा था पंचम दा यानी आरडी बर्मन ने. उनका अंतिम चर्चित गीत वर्ष 1995 में आई फ़िल्म हक़ीक़त का, आ पपियां झपियां पा लें हम, अंखियों से पेंच लड़ा लें हम, था जिस पर अश्लील और फूहड़ होने के आरोप लगे थे. जबकि उनकी अंतिम फ़िल्म थी ज़ुल्मी, जो वर्ष 1999 में रिलीज हुई थी.

कैसे बने बावरा?

सट्टा बाज़ार के निर्माण के दौरान फ़िल्म के वितरक शांतिभाई पटेल ने गुलशन जी को बावरा की उपाधि से नवाजा था. वजह, उन्नीस-बीस साल के गुलशन अक्सर चटख रंगीन एवं डिज़ाइनदार कपड़े पहना करते थे. एक दिन शांतिभाई ने कहा, मैं इसका नाम गुलशन बावरा रखूंगा, क्योंकि यह बावरा (पागल) जैसा दिखता है. शांतिभाई गुलशन जी के गंभीर लेखन के कायल थे. और, जब यह फ़िल्म मुंबई में रिलीज हुई तो इसके पोस्टरों पर भी तीन ही नाम प्रमुख थे-रवींद्र दवे, कल्याण जी-आनंद जी और गुलशन बावरा.

व्याकरण के पाबंद

गुलशन हमेशा सार्थक, सद्अर्थी और गंभीर लेखन के पक्षधर रहे. वह अवधारणा रहित और व्याकरण की नज़र से अशुद्ध रचना को पसंद नहीं करते थे. एक बार उन्होंने नामचीन गीतकार शैलेंद्र की रचना, आवारा हूं, आवारा हूं या गर्दिश में हूं आसमान का तारा हूं को अर्थरहित बताते हुए इसे कुछ यूं संशोधित किया था, आवारा हूं, आवारा हूं में गर्दिश में भी आसमान का तारा हूं... गुलशन जी का मत था कि प्राकृतिक अथवा शाश्वत सत्य को अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से घुमाया-फिराया नहीं जाना चाहिए. यह स्थिति लेखन की कसौटी पर भी खरी नहीं उतरती.

सम्मान

1967	मेरे देश की धरती सोना उगले-उपकार-फ़िल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार
1973	यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी-जंजीर-फ़िल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार

चुनिंदा नग्मे

चांद को क्या मालूम	:	लाल बंगला
मेरे देश की धरती	:	उपकार
यारी है ईमान मेरा	:	जंजीर
सनम तेरी कसम	:	सनम तेरी कसम
अगर तुम न होते	:	अगर तुम न होते
आती रहेंगी बहारें	:	कसमें वादे
जीवन के हर मोड़ पर	:	झूठा कहीं का
वादा कर ले साजना	:	हाथ की सफाई
आ पपियां झपियां	:	हकीकत

महेंद्र अवधेश
m_awdhesh@chauthiduniya.com

फ़िल्म रिव्यू

हाउसफुल

वर्ष 2007 में फ़िल्म हे बेबी बना चुके साजिद खान इंटरटेनमेंट के लगभग हर सेगमेंट अभिनय, गायन, एंकरिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में काम कर चुके हैं. इसलिए जब उन्होंने फ़िल्म निर्देशक बनने का ज़िम्मा लिया तो इन सब चीजों में हाथ भी आज़माया. 30 अप्रैल को उनकी फ़िल्म हाउसफुल प्रदर्शित हो रही है. फ़िल्म में वे सभी मसाले हैं, जो एक कमर्शियल फ़िल्म में होते हैं. स्टारकास्ट में अक्षय कुमार, दीपिका, लारा, रितेश, जिया, अर्जुन रामपाल और बोमन ईरानी जैसे सितारे हैं. कॉमेडी थीम पर बनी इस फ़िल्म को ख़ूबसूरत विदेशी लोकेशंस और मधुर संगीत के ज़रिए आकर्षक बनाने की पूरी कोशिश की गई है. कहानी आरुष की है, जो परिस्थितिवश एक नहीं, तीन पत्नियों को साथ रखने पर मजबूर हो जाता है. अब एक ही घर में तीन ख़ूबसूरत बीवियों को रखना और वह भी एक दूसरे को बताए बिना. मुश्किल तो है, पर आरुष के लिए नामुमकिन नहीं. हालांकि इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने के खेल में वह अपने दोस्त की मदद लेता है. इसी क्रम में कई हास्यास्पद स्थितियां पैदा होती हैं, जो दर्शकों का मनोरंजन करेंगी. अक्षय कुमार गरम मसाला के बाद अपनी कॉमिक टाइमिंग और छवि के अनुरूप किरदार में वापसी कर रहे हैं. वहीं रितेश भी कॉमेडी किरदार में फब रहे हैं. ग्लैमर का तड़का मारने के लिए तीन-तीन बिकनी बेब भी हैं. कुल मिलाकर साजिद अपनी बहन फरहा के नक्शे क़दम पर चल रहे हैं. संगीत शंकर अहसान लॉय का है. निर्माता हैं अक्षय के चहेते साजिद नाडियाडवाला. प्रोमो के दृश्य देखकर कुछ लोग इसे हॉलीवुड कॉमेडी फ़िल्म हैंगओवर से प्रभावित मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है. अब देखना दिलचस्प होगा कि हाउसफुल अपनी रिलीज के बाद कितने दिनों तक हाउसफुल रहती है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 19 अप्रैल–25 अप्रैल 2010

www.chauthiduniya.com

नीतीश को मिला ब्रह्मास्त्र

लालू-राबड़ी के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई के नए ख़ुलासे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा झुनझुना थमा दिया है, जिसके सहारे वो राजद के साथ-साथ कांग्रेस को भी एक साथ कठघरे में खड़ा करने में सफल हो सकते हैं.

नीतीश कुमार

लालू प्रसाद यादव

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

यह लड़ाई से पहले की रणभेरी है और सभी लड़ाके खम ठोंक कर मैदान में उतर आए हैं. लालू–राबड़ी के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई के एक खुलासे ने राजद के साथ–साथ कांग्रेस को भी बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया है. कांग्रेस सारे मामले से अपना हाथ खींचने की कोशिश में लगी है तो लालू जवाबी हमले के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को हुआ है. चुनावी वर्ष में सीबीआई ने बैठे–बिठाए उनके हाथों में एक ब्रह्मास्त्र थमा दिया है और अब वो इसी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का समीकरण बनाने लगे हैं.

जैसा नीतीश कुमार चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो गया है. सीबीआई ने उन्हें बैठे–बिठाए एक ऐसा चुनावी ब्रह्मास्त्र थमा दिया, जिससे बचने के लिए उनके राजनीतिक विरोधियों को नाको चने चबाने पड़ेंगे. सुशासन, विकास और केंद्र के सौतेले रवैये जैसे तीरों को नीतीश कुमार हर चुनावी महासंग्राम में आजमा रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार के एक सनसनीखेज खुलासे से नीतीश कुमार के हाथ चुनावी ब्रह्मास्त्र लग गया.

अश्विनी कुमार ने खुलासा किया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में लालू प्रसाद एवं राबड़ी देवी के ख़िलाफ़ जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं और अगर केंद्र सरकार इज़ाज़त देती तो सीबीआई निश्चित रूप से विशेष अदालत के फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देती. सीबीआई के रुख़ साफ़ होते ही सूबे की सियासत में हड़कंप मच गया. नीतीश ने बिना देर किए मोर्चा खोलते हुए कहा कि मैं बार–बार यह कहता रहा हूं कि लालू प्रसाद व कांग्रेस कभी अलग हुए ही नहीं. दोनों एक ही हैं और केवल जनता को भ्रम में डालने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते रहते हैं.

सीबीआई के खुलासे से कांग्रेस और लालू प्रसाद की मिलीभगत की पोल खुल गई. नीतीश के इस हमले से कांग्रेस जहां दुविधा में है, वहीं लालू प्रसाद बैकफुट पर आ गए हैं. पहले बात कांग्रेस की. पार्टी को बिहार में जिंदा करने के लिए आलाकमान ने राज्य के कांग्रेसियों और जनता का मूड भांपते हुए राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने का नीतिगत फ़ैसला लिया. इसका असर भी हुआ और जनता का भरोसा जीतने में पार्टी कामयाब होने लगी. वर्षों से बेजान पड़ी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं में भी उम्मीद जगी कि अब पुराने दिन आने ही वाले हैं. आंकड़ों में देखें तो लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा. नीतीश और लालू से नाराज़ अगड़ी जातियों का एक बड़ा समूह कांग्रेस की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहा था. लालू से नाराज़ मुसलमान भी कांग्रेस का हाथ थामने लगे थे, लेकिन सीबीआई के ताज़ा ख़ुलासे ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया. लालू एवं नीतीश से खफ़ा अगड़ी जातियों के बीच यह संदेश गया है कि अगर कांग्रेस चाहती तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में लालू प्रसाद के ख़िलाफ़ सीबीआई ज़रूर अपील दायर करती. यानी कहीं न कहीं अभी भी कांग्रेस के दिल में लालू प्रसाद के लिए जगह बनी हुई है. इसलिए उन्हें यह डर सताने लगा है कि कांग्रेस के माध्यम से कहीं एक बार फिर सत्ता की चाबी लालू प्रसाद के हाथ न लग जाए. क्योंकि खुलासा ख़ुद सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमान ने ही किया है. इसलिए भरोसा न करने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है. कल तक अगड़ी जाति के जो नेता कांग्रेस के लिए ताना–बाना बुनने में लगे थे, उनके क़दम भी फिलहाल ठहर गए हैं. नीतीश से विक्षुब्ध नेताओं ने कांग्रेस को लेकर जो रणनीति बनाई थी, उस पर पुनर्विचार का दौर शुरू हो गया है. मतलब कांग्रेस को दोतरफा नुक़सान हो रहा है. नीतीश बार–बार लालू और कांग्रेस की दोस्ती का मुद्दा उछाल रहे हैं, ताकि जनता के बीच विकल्प के तौर पर कांग्रेस की जो छवि बन रही थी, वह पूरी तरह बिगड़ जाए. सीबीआई निदेशक के ख़ुलासे में इतना मसाला तो है ही कि वह कांग्रेस की सूरत संवरने नहीं देगा. पहले ही गुटबाजी एवं टांगखिंचाई से जूझ रही कांग्रेस के लिए इस संकट से उबरना आसान नहीं होगा.

जहां तक लालू प्रसाद का सवाल है तो उन्हें अब उन इल्जामों का भी जवाब देना होगा, जिनके लिए नीतीश कुमार केंद्र सरकार को निशाना बनाते रहे हैं. नीतीश का कहना है कि कुछ बिहारी नेताओं का केंद्र में इतना प्रभाव है कि उनके दबाव में आधी रात को कैबिनेट की बैठक हो जाती है. इतना अच्छा प्रभाव और इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद बिहार के साथ अन्याय होता रहा और ऐसे नेता चुप रहे तो जनता उनसे हिसाब तो मांगेगी ही. केंद्र सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी कहां चली गई, कुछ पता ही नहीं चला.

नीतीश को मौक़ा मिल गया है और वह इसे खोना नहीं चाहते. इसलिए लालू प्रसाद पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमलों का नया दौर शुरू कर दिया गया है. आज़माई हुई बात है कि लालू प्रसाद का विरोध नीतीश कुमार की ताक़त में इजाफा करता है, लेकिन इस बार तो फुलटॉस मिला है, नीतीश जैसा खिलाड़ी छक्का मारने से कैसे चूकेगा? नीतीश कुमार की चुनावी गणित तभी हिट होगी जब कांग्रेस और लालू एक साथ नज़र आएंगे.

निदेशक का खुलासा ऐसा है कि न चाहते हुए भी दोनों एक मंच पर खड़े नज़र आने लगे हैं. राजनीति की बिसात पर वास्तविकता कुछ भी हो, जनता उसी को सच मानती है जो सामने नज़र आता है. और फिलहाल ऐसी परिस्थिति बन गई है कि लालू और कांग्रेस का अलग–अलग दिखना मुश्किल लग रहा है. मगर, लालू प्रसाद का राजनीति करने का अपना स्टाइल है. इसलिए उनके समर्थकों को लगता है कि यह कोई बड़ा मसला नहीं है. राजद नेता व लालू के खासमखास छोटू सिंह का कहना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला आ चुका है, इसलिए इस पर विवाद बेकार है. राजद नेताओं का आरोप है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए यह सब बातें हो रही हैं. विकास के नाम पर धोखा दिया जा रहा है और बिहार की ग़रीब जनता को ठगा जा रहा है. बिहार की छवि चमकाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार जनता के पैसे से अपनी छवि चमकाने में लगे हैं. डैमेज कंट्रोल के तहत राजद ने आंकड़ों के माध्यम से विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार की पोल खोलने का काम भी शुरू कर दिया है.

राजद ने विश्व बैंक के हवाले से कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल में राज्य की स्थिति दयनीय है. यहां काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है. नरेगा व सर्वशिक्षा अभियान का अस्सी फ़ीसदी पैसा ठेकेदारों और अफसरों की जेबों में जाता है. अमीरी–गरीबी की खाई बहुत गहरी है, जिससे सामाजिक टकराव की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा है. मतलब साफ़ है कि राजद भी जवाबी वार के लिए अपने को तैयार कर रहा है. केंद्र की राजनीति की जो भी मजबूरी हो पर राज्य में तो पार्टी को यह ज़रूर साबित करना होगा कि लालू नीतीश से बेहतर हैं. लालू प्रसाद के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी है क्योंकि इस बार उनका सामना नीतीश के ब्रह्मास्त्र से है.

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश को मौक़ा मिल गया है और वह इसे खोना नहीं चाहते. इसलिए लालू प्रसाद पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमलों का नया दौर शुरू कर दिया गया है. आज़माई हुई बात है कि लालू प्रसाद का विरोध नीतीश कुमार की ताक़त में इज़ाफ़ा करता है, लेकिन इस बार तो फुलटॉस मिला है, नीतीश जैसा खिलाड़ी छक्का मारने से कैसे चूकेगा? नीतीश कुमार की चुनावी गणित तभी हिट होगी जब कांग्रेस और लालू एक साथ नज़र आएंगे.

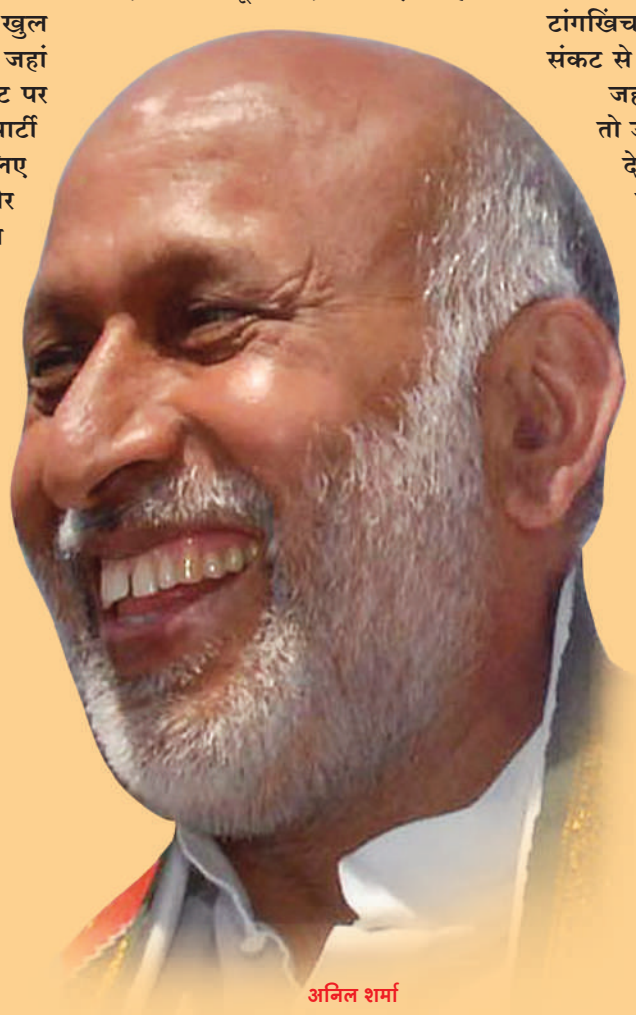

अनिल शर्मा

नेपाल की सीमा से सटे भारतीय प्रभाग के सलेशपुर भीमनगर पुनर्वास पर पदयात्रियों की यात्रा ख़त्म तो हुई, लेकिन यह यात्रा विस्थापितों के अधिकार के लिए कई सवाल छोड़ गई.

सूरजभान सिंह और अनंत सिंह को राजनीति में लाने का श्रेय जद (यू) के बागी सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जाता है.

सीवान : राजग में घमासान

धनंजय मिश्र

सीवान में विकास से ज़्यादा विरोध की राजनीति होने लगी है. विरोध की राजनीति विकास मद की राशि को लेकर शुरू हुई है. इस विरोधाभासी राजनीति से यहां एनडीए में घमासान मचा हुआ है, जो सड़कों पर उग्र प्रदर्शन और चौक-चौराहों पर नेताओं द्वारा एक-दूसरे के पुतला दहन तक पहुंच गया है. राजग में यह राजनीति एक साल पहले वाकयुद्ध से शुरू हुई थी. हालांकि राजग के बड़े नेता और मंत्री विरोध की इस राजनीति से एनडीए गठबंधन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने का बयान दे रहे हैं और नेताओं-कार्यकर्ताओं को यह नसीहत भी दे रहे हैं कि हम आपस में लड़ बैठे तो नुकसान हमारा ही होगा, लेकिन आपसी अंतर्विरोध कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जिससे एनडीए कहीं-न-कहीं कमज़ोर पड़ रहा है. हालिया घटनाक्रम की शुरुआत पिछले 27 मार्च को हुई जब ज़िला परिषद (जिप) में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ. विगत एक माह से अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर ज़िला पार्षद दो गुटों में बंटे हुए थे. मतदान के दौरान एक पार्षद द्वारा क्रॉस वोटिंग के कारण ज़िला परिषद अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए, जबकि उपाध्यक्ष मंजू देवी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाईं. यहीं से विरोध की राजनीति सड़कों और चौराहों पर आ गई. जीत-हार के बाद शुरू हुए आत्ममंथन ने इस विरोध की राजनीति को हवा दे दी. आत्ममंथन से यह निष्कर्ष निकाला कि एक माह पहले कुल 21 जिप पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. फिर कैसे एक पार्षद की क्रॉस वोटिंग से नंद प्रसाद चौहान अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो गए. इस वादाखिलाफी और दगाबाज़ी का आरोप ज़िला पार्षद देवेशकांत सिंह पर लगाया जाने लगा. जीरादेई के जदयू विधायक श्याम

देवेशकांत सिंह

नंद प्रसाद चौहान

ओमप्रकाश यादव

बहादुर सिंह

व्यास देव प्रसाद

शिवप्रसन्न यादव

बहादुर सिंह के इस बयानबाजी के बाद उनके समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और देवेशकांत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदान के बाद ज़िला परिषद में ही उनका पुतला दहन किया. इस घटना से नाराज़ हुए देवेशकांत के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने नगर के जेपी चौक और बड़हरिया में विधायक श्याम बहादुर सिंह का पुतला फूंका. कुल 41 जिला पार्षदों में प्रद्युम्न राय एक आपराधिक मामले में अभियुक्त होने की वज़ह से क़रीब तीन साल से फरार हैं, जबकि आपराधिक मामले में ही एक अन्य पार्षद विनोद तिवारी सीवान मंडल कारा में बंद हैं. हसनपुरा की पार्षद गीता देवी उक्त मतदान के दो दिन पूर्व ही कथित तौर पर अगवा कर ली गई थीं, उनके छोटे पुत्र ने अपहरण की प्राथमिकी एमएच नगर हसनपुरा थाना में दर्ज़ कराई थी. इस घटना में जिप अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान और एक अन्य व्यक्ति को अभियुक्त भी बनाया गया था, लेकिन गीता देवी ने बाद में पुलिस के सामने यह बयान दिया कि उनका अपहरण हुआ ही नहीं था, वह तो इलाज के लिए पटना गई थीं. जानकारों की मानें तो इस फर्जी अपहरण के पीछे उच्च राजनीतिक साजिश थी. इसी प्रकार नंद प्रसाद चौहान की कुर्सी बचाने के निहितार्थ, मतदान से बचने और अपना राजनीतिक नफा-नुक़सान का आकलन एवं आश्वासन पाकर मतदान के एक दिन पूर्व ही 16 ज़िला पार्षद सपरिवार 15 बोलेरो से विंध्याचल तीर्थाटन के लिए कूच कर गए. इस तीर्थाटन के कारवां में कथित जिप अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान भी मौजूद थे. जानकारों के मुताबिक, नंद प्रसाद चौहान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति और उसके बाद मचे इस घमासान की हक़ीकत यह है कि चालू वित्तीय साल के लिए राज्य सरकार द्वारा सीवान ज़िला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु लगभग 64 करोड़ रुपए मिलना है. हालांकि, एनडीए की इन दुश्वारियों के तार कहीं न कहीं पिछले लोकसभा चुनाव से भी जुड़े हैं. गत लोकसभा चुनाव में ओमप्रकाश यादव को जब जदयू से टिकट नहीं मिला, तो वह बागी बनकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े और भारी मतों से विजयी भी हो गए. तभी से वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्थानीय विधायक श्याम बहादुर सिंह, सीवान के विधायक एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री व्यासदेव प्रसाद और विधान पार्षद शिवप्रसन्न यादव के खिलाफ आलोचनात्मक बयान और भाषण देने लगे तथा कांग्रेस के पक्ष में बोलने लगे. हालांकि, व्यासदेव प्रसाद डेढ़ दशक पूर्व कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, जबकि पांच साल पहले पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की मदद से ओमप्रकाश यादव कांग्रेस से ही नाता तोड़कर जदयू से जुड़े थे. टिकट कटवाने के लिए एनडीए के तीन प्रमुख नेताओं को जिम्मेदार मानते हुए यादव ने उनके खिलाफ आरोप लगाना भी शुरू कर दिया. यहीं से एनडीए के भीतर ही भीतर बिखराव प्रारंभ हो गया. इस बिखराव की मुख्य वज़ह उपेक्षा और अपमान बताई जा रही है, जिससे आक्रोशित होकर भाजपा के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंदर ही अंदर व्यासदेव प्रसाद के विरुद्ध एक मजबूत लॉबी तैयार कर ली है और उन्हें मात देने के लिए सांसद ओमप्रकाश यादव के साथ लामबंद हो गए हैं. बताया जाता है कि भाजपा विरोधी इस लॉबी ने अपनी योजनाबद्ध रणनीति से नंद प्रसाद चौहान की कुर्सी बचाई. चौहान सांसद ओमप्रकाश यादव के अंतरंग हैं, इसीलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में नंद प्रसाद चौहान की जीत को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, जबकि दूसरे गुट की कमान एनडीए के पार्षद त्रिदेव नेता के हाथों में थी. भाजपा की इस नाराज़ लॉबी ने नंद प्रसाद चौहान की कुर्सी बचाकर अपनी कूटनीतिक सूझ-बूझ और हैसियत से वरीय नेताओं की उस तिकड़ी को भी हैरान कर दिया. राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भाजपा की यह नाराज़ लॉबी अभी से ही अगले विधानसभा चुनाव में उन नेताओं को फिर से शिकस्त देने की तैयारी में लग चुकी है. एनडीए ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कदम नहीं उठाए तो इसका लाभ राजद या अन्य दलों के प्रत्याशियों को मिल सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश ने बिहारियों को धोखा दिया : पासवान

रामविलास पासवान हाजीपुर से भले ही लोकसभा का चुनाव हार गए हों, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन गुज़रता है जब उनके पटना स्थित आवास पर वहां के लोगों की भीड़ न देखी जाए. बात करने पर पता चला कि हाजीपुर से उनका रिश्ता चुनावी जीत-हार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रामविलास का क्षेत्र के लोगों के साथ भरोसे और विश्वास का मज़बूत बंधन है. लोगों की समस्याएं सुनने और उसे निपटाने के साथ ही पासवान नीतीश कुमार को चुनावी शिकस्त देने की रणनीति बनाने में मशगूल दिखे. इसी दौरान उन्होंने बिहार के प्रति अपनी चिंता और नीतीश कुमार के अब तक के शासन पर बात की. प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश.

नीतीश कुमार कहते हैं कि वह तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखते हैं.

बिल्कुल झूठ, दलित से महादलित बन गया, क्या इसे जोड़ना कहते हैं. पासवान को अलग रखा गया, क्या इसे जोड़ना कहते हैं. देखिए, नीतीश कुमार की न तो नीति साफ़ है और न ही नीयत. यही वजह है कि ग़रीब जनता पांच साल पहले जहां थी, आज भी वहीं है. उन्हें जो सपना दिखाया गया था, वह सपना ही रह गया. इस पर हक़ीक़त का रंग नहीं चढ़ पाया. लोग भूखों मर रहे हैं और सरकार फ़िज़ूलख़र्ची में लगी है.

> जनता बार-बार धोखा नहीं खाएगी. उन्होंने देख लिया कि नीतीश शासन में उनके दुख-दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है. उन्हें वाजिब हक़ भी नहीं मिला. इसलिए जनता ने मन बना लिया है और अगले चुनाव के बाद लोजपा-राजद गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी.

राज्य में विकास के दावे पर आपकी क्या राय है?

नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है. विकास होता तो यहां लोग भूख से नहीं मरते. पेट पालने के लिए पंजाब और दिल्ली नहीं जाते. पलायन की दर से पता चलता है कि ज़मीनी स्तर पर कितना विकास हुआ है. न तो कोई बड़ा उद्योग लगा और न ही बिजली संकट का कोई समाधान यह सरकार निकाल पाई. हां, जनता के पैसे से अपनी छवि चमकाने में नीतीश कुमार ने कोई कमी नहीं छोड़ी. शिक्षा का हाल सब जान ही रहे हैं. अफ़सरशाही इस क़दर हावी है कि ग़रीबों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है. बिचौलियों की तिजोरी भरी जा रही है और ग़रीब का पेट खाली है.

क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? आपके गठबंधन की क्या संभावना है?

जनता बार-बार धोखा नहीं खाएगी. उन्होंने देख लिया कि नीतीश शासन में उनके दुख-दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है. उन्हें वाजिब हक़ भी नहीं मिला. इसलिए जनता ने मन बना लिया है और अगले चुनाव के बाद लोजपा-राजद गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी. जनता इतनी परेशान है कि नीतीश सरकार के दो तिहाई मंत्री एवं विधायक चुनाव हार जाएंगे. उपचुनाव में इसकी बानगी सबने देख ली है. इस सरकार की विदाई हर क़ीमत पर तय है.

पिछली बार आप मुस्लिम सीएम की बात कह रहे थे. आपकी गठबंधन की सरकार बनी तो सीएम कौन होगा?

इस पर अभी क्या कहें. हमलोग आपस में मिल-बैठ कर नेता तय करेंगे. सारा काम लोकतांत्रिक तरीक़े से होगा. जनता के जनमत का पूरा सम्मान किया जाएगा. राजद और लोजपा ही ऐसी पार्टी है, जिसमें कोई गुटबाजी नहीं है. हर फ़ैसले में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है. दोनों दलों में बेहतर तालमेल है. दोनों ही पार्टियां मिलकर बिहार के मान-सम्मान को बहाल करेंगी और बिहार का वास्तविक विकास करेंगी.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

आपके राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है. क्या आपने मन बना लिया है?

अभी तो समय है. बिहार के बाहर से मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने का न्यौता मिला था, लेकिन मैंने साफ़ मना कर दिया. मैं बिहार से ही चुनाव लड़ूंगा. अभी तो राज्यसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है. समय आएगा तो फ़ैसला किया जाएगा. मगर इतना तय है कि बिहारियों के दुख-दर्द को कम करने के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा.

अधिकारियों के बड़े पैमाने पर हुए तबादले को लेकर विवाद छिड़ा है. आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है.

नीतीश कुमार को अपनी विदाई का एहसास हो चुका है. उपचुनाव के नतीजों के बाद वह किसी न किसी तरह अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं. राज्य में रातोंरात बड़े पैमाने पर चुनावी तबादले कर दिए गए. इन तबादलों में यादव एवं पासवान जाति के अधिकारियों को उपेक्षित कर दिया गया. सरकार भीतर से डरी हुई है और अफसरों की मदद से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है. यह बात तय है कि चुनाव के बाद राज्य में लोजपा-राजद गठबंधन की सरकार बनेगी.

जदयू और नीतीश से नाराज़ कई नेताओं की लोजपा में शामिल होने की चर्चा है. इसमें क्या सच्चाई है.

सवाल केवल नाराज़ नेताओं का नहीं है. हम उन सभी लोगों का सहयोग लेने के लिए तैयार हैं, जो बिहार को बचाना चाहते हैं. इस राज्य को बचाने एवं बनाने की ज़िम्मेदारी सबकी है, जो इससे भागेंगे या धोखा करेंगे, जनता उनसे हिसाब मांगेगी. इसलिए मसला व्यक्ति विशेष का नहीं बिहार के हित का है और सभी को खुले दिल से सोचना व काम करना होगा. लोजपा-राजद ने तो संकल्प ले लिया है, अब बाकी लोगों को सोचना है.

सरोज सिंह
feedback@chauthiduniya.com

सिर छिपाने के लिए छत तो दो भाई

पूर्वी कोसी तटबंध के किनारे बसे मसोमात नगिया देवी का घर भी उजड़ गया. अस्थाई झोपड़ी भले ही तत्काल उसे सिर पर छत होने का एहसास करा रही हो, लेकिन वह जगह भी उसे खाली करनी पड़ेगी. पूर्वी कोसी तटबंध पर हो रहे पुनर्निर्माण के चलते चंदेल मरीचा गांव की नगिया मसोमात ही नहीं, बल्कि मोहम्मदपुर के विकलांग ललित यादव, सुपौल ज़िले के लालकन पट्टी के कारी सादा एवं विशुनदेव पासवान के सामने भी सिर छिपाना एक बड़ी समस्या बन चुकी है. हज़ारों ग़रीब, भूमिहीन, दलित और महादलित परिवार इस पुनर्निर्माण से उजड़ गए हैं. मसोमात तारा देवी अपनी जवान बेटी के कारण रात भर अस्थाई झोपड़ी में सोती नहीं हैं. हमेशा डर सताते रहता है. एक अज्ञात भय की आशंका ने आगे की ज़िंदगी को पहाड़-सा बना दिया है.

दर्द के इसी एहसास के बीच कोसी पीड़ित पुनर्वास मंच के बैनर तले 125 किलोमीटर की पद यात्रा ने इन विस्थापित और पीड़ित परिवारों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने का काम किया. मंच के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और संयोजक सह युवा लोजपा के ज़िला अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने पद यात्रा के दौरान हज़ारों पीड़ित परिवारों की व्यथा सुनी. भूमिहीन आख़िरकार जाएं तो जाएं कहां? सरकार दावा करती है कि तटबंध निर्माण (1956) के समय ही पीड़ित परिवारों का पुनर्वास करा दिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवारों की संख्या और पुनर्वास के तौर पर वितरित भूखंड से सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार के दावे में दम नहीं है. 380 गांव में, 10 लाख से अधिक विस्थापितों की आबादी के मध्य 630 हेक्टेयर ज़मीन पुनर्वास के रूप में वितरित की गई. कोसी परियोजना के पुनर्वास स्थलों की संख्या 134 है, जिसमें 60 पुनर्वास स्थल कोसी तटबंध के पूरब और 74 पुनर्वास स्थल तटबंध के पश्चिम में हैं. इन पुनर्वास स्थलों पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 570 हेक्टेयर ज़मीन आज भी खाली पड़ी है, जबकि पुनर्वास के लिए कुल 12 सौ हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था. सरकार की अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार लगभग आधा पुनर्वास स्थल खाली है. आख़िर विस्थापित परिवार खाली पड़े पुनर्वास स्थलों पर क्यों नहीं जाना चाहते? इसके पीछे कारण हैं, ये पुनर्वास स्थल जलजमाव वाले क्षेत्र में है और यहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. इसका मतलब साफ़ है कि सरकार पुनर्वास के रूप में हमेशा से खानापूर्ति ही करती आ रही है.

नेपाल की सीमा से सटे भारतीय प्रभाग के सलेशपुर भीमनगर पुनर्वास पर पदयात्रियों की यात्रा ख़त्म तो हुई, लेकिन यह यात्रा विस्थापितों के अधिकार के लिए कई सवाल छोड़ गई. इस यात्रा में मंच के प्रवक्ता विपिन यादव सम्राट, मो. राजा, लखन शर्मा, अरुण यादव, मो. अब्बास, डोमी पासवान, मो. अमिसा खातुन, मसोमात जैनूला, राम कुमार राम, रंजीत कुमार राम, विशुनदेव राम आदि भी शामिल थे. पुनर्वास की उचित व्यवस्था की बाट जोह रहे पीड़ित लोगों की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब पूर्वी कोसी तटबंध के जीर्णोद्धार और मज़बूतीकरण समेत सड़क निर्माण कार्य शुरू होने की वज़ह से जहां एक ओर तटबंध के किनारे दशकों से निर्वासित ज़ीवन बिता रहे गरीब-गुरवा एवं दलितों के समक्ष सिर छुपाने की समस्या विकराल बन गई है, वहीं सरकार द्वारा पुनर्वास हेतु आवंटित ज़मीन पर क़ब्ज़ा पाने के लिए आपस में ही सिर फुटौव्वल करने को भी वो विवश हैं. तटबंध पर सड़क बनाने वाली एजेंसी के कर्मचारी तटबंध के किनारे रह रहे लोगों को ज़बरन हटा रहे हैं. लेकिन पुन: विस्थापित होने वाले ग़रीब-गुरवा एवं दलितों की बेटी, बहू और परिवार के अन्य लोग कहां रहेंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है. हाल में नवहट्टा प्रखंड के पंचायत कासिमपुर के गांव त्रिखुटी के महादलितों के बीच पुनर्वास की ज़मीन को हड़पने के लिए आपस में मारपीट हुई.

महादलितों में किसी को दिसंबर 2001, तो किसी को 18 जून 2003 को बिहार सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा 144 रुपये प्रति एकड़ की दर से 0.23 डिसमिल ज़मीन की बंदोबस्ती की गई, जबकि कइयों को 0.38 डिसमिल ज़मीन की स्थाई बंदोबस्ती की गई है. फिर भी ग़रीबों के बीच इन दिनों बंदोबस्त ज़मीन की ख़ातिर टकराहट शुरू हो गई है. इस मसले पर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है. अगर सरकार एवं प्रशासन इन बंदोबस्तधारियों का सही रूप से पुनर्वास नहीं कराती है, तो भविष्य में इस तरह की टकराहटों को टालना काफी मुश्किल होगा. कोसी पीड़ित पुनर्वास मंच के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह कहते हैं कि हम तो उन लोगों की हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके साथ प्रकृति ने भी न्याय नहीं किया. उन्होंने कहा कि जबतक सही मायनों में पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा. मंच के संयोजक एवं लोजपा नेता महेंद्र शर्मा ने कहा कि मेरे नेता रामविलास पासवान सबसे आखिरी घर में चिराग जलाने की बात कहते हैं और मैं उनके इसी दिखाए रास्ते पर चल रहा हूं. लोजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसने पुनर्वास के मसले को उठाया है और जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक लोजपा एवं मेरा संघर्ष जारी रहेगा. कोसी क्षेत्र में लोजपा के लिए दिन रात संघर्ष करने वाले महेंद्र शर्मा ने ऐलान किया है कि जब तक बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास नहीं हो जाता है, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा.

पुनर्वास के इंतजार में विस्थापित परिवार.

एस सोनी
feedback@chauthiduniya.com

नौतन विधानसभा क्षेत्र

मतदाताओं का मन टटोलने में जुटे नेता

चुनावी साल में अन्य क्षेत्रों की तरह पश्चिम चंपारण के नौतन में भी चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है. विभिन्न दलों के नेता टिकट पाने की होड़ में अपनी दावेदारी को मज़बूत करने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियां अपनी ज़मीन तलाश रही हैं और मतदाताओं को लुभाने की हरसंभव कोशिश कर रही हैं.

कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले पश्चिम चंपारण के नौतन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी है. आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी नेता जोर-शोर से लगे हैं. यह क्षेत्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडेय का कार्यक्षेत्र रहा है. यहीं से कुख्यात दस्यु सरगना भागड़ यादव ने अपने भाई सतन यादव को विधायक बनाने में कामयाबी हासिल की थी. हालांकि बेटे को विधायक बनाने की उसकी लालसा पूरी नहीं हो सकी. इस क्षेत्र में क़रीब तीन दशकों तक उसका वर्चस्व कायम रहा, लेकिन नीतीश के शासनकाल में भागड़ यादव को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा. फिलहाल वह सलाखों के पीछे है. नौतन विधानसभा क्षेत्र पर केदार पांडेय के बाद वामपंथी नेता रेवाकांत दूबे ने क़ब्ज़ा जमाया. उसके बाद वर्ष 1995 में भागड़ यादव ने अपने भाई सतन यादव को विधायक बनाया. वर्ष 2000 के चुनाव में भागड़ यादव ने अपने पुत्र अमर यादव को मैदान में उतारा, लेकिन अपराध एवं अपराधियों के ख़िलाफ़ मुहिम की बात कहकर बैद्यनाथ प्रसाद महतो इस क्षेत्र से विधायक बने और अमर यादव को मुंह की खानी पड़ी. वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में पुन: बैद्यनाथ प्रसाद महतो इस क्षेत्र से चुने गए और राज्य में ग्रामीण विकास मंत्री का ओहदा प्राप्त किया. हालांकि परिसीमन के बाद बने वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से चुने जाने के बाद उन्हें बीच में ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी. परिणामस्वरूप नौतन विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2009 में उपचुनाव कराया गया, जिसमें बसपा के नारायण साह ने शेष सभी दलों को पटखनी देते हुए विधायक की कुर्सी पर क़ब्ज़ा जमाया. इधर अब अगले विधानसभा चुनाव में बसपा को पटखनी देने के लिए अभी से ही प्राय: सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. इन्हीं चर्चाओं के बीच कई संभावित प्रत्याशी भी अपनी उम्मीदवारी पक्की कराने के लिए धरना-प्रदर्शन, पर्चाबाजी और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं. हालांकि ज़िले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में यहां बैनर युद्ध कम देखने को मिल रहा है.

मनोरमा देवी

सत्येंद्र शरण

नारायण प्रसाद

मुखी सहनी

राजनैतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार ज़िले के नौ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी गठबंधन के हिसाब से भाजपा और जदयू के बीच सीटों के फेरबदल होने की संभावना दिख रही है, जिसके तहत जदयू के हिस्से में मौजूद नौतन विधानसभा क्षेत्र भाजपा के हिस्से में तो भाजपा के हिस्से में शामिल सिकटा विधानसभा क्षेत्र जदयू के हिस्से में जाने की संभावना है. इस फेरबदल की संभावना इसलिए बनती दिख रही है क्योंकि सिकटा के विधायक खुर्शीद आलम का झुकाव जदयू की ओर ज्यादा देखा जा रहा है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी के विरुद्ध आग उगलने वाले खुर्शीद आलम किसी भी सार्वजनिक सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कसीदे काढने में पीछे नहीं रह रहे हैं. नौतन विधानसभा क्षेत्र में इस फेरबदल की हालत में भाजपा के कई दावेदार सामने आने लगे हैं. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव और ज़िला प्रवक्ता सत्येंद्र शरण इस दौड़ में अपने को सबसे आगे दिखा रहे हैं. इसके अलावा अन्य कई नेता भी हैं जो अपनी दावेदारी को लेकर गंभीर हैं. मुखी सहनी भी इस क्षेत्र से अपने को प्रबल दावेदार बता रहे हैं. चर्चाओं के अनुसार भाजपा के हाथ से यह सीट जाने के बाद सुगौली के विधायक एवं राज्य के भूतत्व एवं खनन मंत्री रामचंद्र सहनी इस क्षेत्र से प्रत्याशी बन सकते हैं. इधर अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तरह इस विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के दावेदारों की संख्या काफी ज़्यादा है. हालांकि विगत उपचुनाव में यहां से शिवरतन यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन वह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर प्रसाद, शेख कामरान, उमेश कुमार वर्मा आदि टिकट की दौड़ में अपने को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं. इधर राजद की ओर से अमर यादव फिर चुनाव मैदान में आने के लिए बेचैन दिख रहे हैं. उनका कहना है कि विगत चुनाव में यहां के मतदाताओं की नाराज़गी पूर्व विधायक बैद्यनाथ प्रसाद महतो से थी, जिसका खामियाजा जदयू के उम्मीदवार को उठाना पड़ा और विकल्प की तलाश में लोगों ने बसपा के प्रत्याशी नारायण प्रसाद को विजयश्री दिला दी, जबकि उपचुनाव में किसी भी दल की ओर से सही एवं उचित प्रत्याशी नहीं दिए जाने के कारण ही बसपा उम्मीदवार की जीत हुई थी. हालांकि उपचुनाव में जीत का सेहरा पहने नारायण साह अपनी जीत के लिए सभी मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और दावा करते हैं कि लोगों ने जिस उम्मीद से मुझे चुनाव जिताया था, मैंने अल्पकाल में उन उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास किया है और आगे भी पूरी निष्ठा एवं तन मन से लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का कार्य करुंगा. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आएं. मुझे एक मौका और दें. इधर नौजवानों की टोली का नेतृत्व कर रहे पूर्व प्रमुख श्रीकांत सिंह ने अभी अपने पत्ते तो नहीं खोले है, लेकिन दावा कर रहे हैं कि वह चुनाव मैदान में उतरेंगे. दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में नामांकन पर्चा रद्द करा चुकी हाईप्रोफाइल महिला नेता ममता निषाद अभी से ही नौतन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता बैठकों के बहाने अपना क्षेत्र बनाने में जुट गई हैं. उनका भी दावा है कि इस बार वह चुनाव लड़ेंगी. बहरहाल, नौतन विधानसभा चुनाव में वामपंथी भी कमर कसने में मशगूल हैं और भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को सामने लाने और खेतिहर मज़दूरों को एक बैनर तले आने की अपील कर रहे हैं.

मीना कुमारी
feedback@chauthiduniya.com

एक साथ ताल ठोकेंगे अनंत-सूरजभान

दिव्या कुमारी

राजनीति में कुछ भी संभव है. संभावनाओं के खेल पर यदि यकीन किया जाए तो अगले विधानसभा चुनावों में बाढ़-मोकामा के दो चर्चित चेहरे एक साथ नज़र आ सकते हैं. हालांकि, राजनीति के मैदान में इनकी प्रतिद्वंद्विता किसी से छुपी नहीं है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर ये दोनों ही अपनी पुरानी रंजिश भुलाकर एक-दूसरे का हाथ थामने के लिए तैयार हो रहे हैं. ये चेहरे हैं जदयू के कद्दावर विधायक अनंत सिंह और लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह. राज्य की राजनीति में जो खिचड़ी पक रही है, उसमें इन दोनों की भी अपनी-अपनी भूमिका है. यह बात दीगर है कि राजनीति और बाहुबल के इन कद्दावर लड़ाकों को उनके राजनीतिक गुरुओं ने अभी मौन रहने का आदेश दिया है. कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के क्षत्रप रहे ये दोनों अभी आज्ञाकारी शिष्य की तरह मौन हैं, लेकिन आगे की लड़ाई के लिए अपने प्यादों को तैयार करने में जुटे हैं.

सर्वविदित है कि सूरजभान सिंह और अनंत सिंह को राजनीति में लाने का श्रेय जद (यू) के बागी सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जाता है. सूरजभान को बेऊर जेल से और अनंत सिंह को टाल से विधानसभा तक ललन सिंह ही ले कर आए थे. सूरजभान को तब समर्थन दिया गया था, जब राजद के तत्कालीन ताकतवर प्रत्याशी दिवंगत दिलीप सिंह को पटखनी देनी थी. रणनीति के तहत सन् 2000 के विधानसभा चुनावों में सूरजभान ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल किया था और तत्कालीन समता पार्टी ने घोसवरी के दिलीप पटेल को मैदान में बतौर डमी उम्मीदवार उतारा था. जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार की पहल पर गैंगवार में शामिल अपराधियों के बीच गैंगवार समाप्त करने पर सहमति बनी थी. अरुण कुमार की मौजूदगी में नंदकिशोर राम मैदान में आयोजित मिलन समारोह में दिलीप पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर सूरजभान को समर्थन देने की घोषणा की थी. मिलन समारोह में सूरजभान और नाटा सिंह के भाईयों ने एक-दूसरे को माला पहनाकर और गले लगाकर गोलियों की तड़तड़ाहट पर रोक लगाने और शांति स्थापित करने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि 2000 के विधानसभा चुनावों से पूर्व आपस में मौसेरे भाई सूरजभान और नाटा सिंह ने ही गैंगवार की कमान संभाल रखी थी. मोकामा से विधायक बनने के बाद सूरजभान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पर लग गए और रामविलास की सदारत कबूल कर सूरजभान लोजपा के टिकट पर 2004 में बलिया से चुनाव जीतकर सांसद बन गए. इसके बाद अनंत सिंह को राजनीति में सूरजभान की कमी को पूरा करने के लिए लाया गया था. सूरजभान 2000 के विधानसभा चुनावों में और अनंत सिंह 2005 के विधानसभा चुनावों में मोकामा से विधायक बने थे. पच्चीस वर्षों तक नीतीश के साथ रहे ललन सिंह अब मोहभंग होने के बाद नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं और उनका पहला हथियार बटाईदारी बिल है.

सूरजभान सिंह

ललन सिंह

अनंत सिंह

अपनों के बीच ललन खुलकर कहते हैं कि नेता को पहले अपना पुराना जनाधार मजबूत करना चाहिए और फिर नया जनाधार तैयार करना चाहिए. जाहिर तौर पर ललन सवर्णों की उपेक्षा और नीतीश के अतिपिछड़ा-महादलित-मुस्लिम प्रेम पर निशाना साधने की जुगत में हैं. साथ में वह यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दर्जनों बार नीतीश को बंधोपाध्याय आयोग को भंग करने के लिए कहा था, लेकिन वे हर बार यह कह कर उनकी बात को टालते रहे कि एक नया इतिहास बनेगा. नीतीश को घेरने की तैयारी में लगे बांका के सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाले लोक मोर्चा द्वारा दो मई को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को भी ललन सिंह का भरपूर समर्थन मिल रहा है. ललन सिंह को पटना पूर्वी के अतिरिक्त लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर जैसे जिलों से भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है. 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान जोड़-तोड़, तिकड़म, दांव-पेंच और प्रबंधन का बेहतरीन कौशल दिखाने वाले ललन सिंह ने अपने सिपहसलारों को भी सक्रिय कर दिया है. गौरतलब है कि 2009 का लोकसभा चुनाव पहला अवसर था जब बाढ़ से लेकर मुंगेर तक के सभी बाहुबलियों ने एक घाट पर पानी पिया था और ललन सिंह की रिकार्ड तोड़ जीत सुनिश्चत हुई थी. इसी कड़ी में सूरजभान और अनंत सिंह ने एक बार फिर जिम्मा संभाला है. प्रबंधन और जोड़-तोड़ के माहिर खिलाड़ी ललन सिंह अंतिम दांव चलने से पहले अपना हर कील-कांटा दुरुस्त कर लेना चाहते हैं. सूरजभान और अनंत सिंह के समर्थक किसान महापंचायत में न सिर्फ शामिल होने की बात करते हैं, बल्कि भीड़ जुटाने का प्रयास करने की बात भी स्वीकार करते हैं. अनंत सिंह के करीबियों की माने तो ललन सिंह लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान को राजद से अलग कर कांग्रेस के करीब लाने का जाल बुन रहे हैं. तर्क यह है कि कांग्रेस बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट देने से इंकार करेगी, तो वैसे लोगों को लोजपा में शामिल कर नीतीश के उम्मीदवारों को परेशानी में डाला जाएगा. इस संभावना को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि ललन सिंह के एक क़रीबी भी यह कहते सुने जा रहे हैं कि यदि अनंत सिंह और सूरजभान एक साथ आ जाएं तो पटना से भागलपुर और बेगूसराय, खगड़िया जैसे इलाकों तक में विरोधियों को कड़ी चुनौती दी जा सकती है.

इन संभावनाओं को सिरे से खारिज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि सूरजभान और अनंत सिंह ख़ुद को ललन सिंह के क़रीबी बताते हैं और उनकी इच्छा को सर्वोपरि बताते हैं. अनंत सिंह और सूरजभान सिंह से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया, लेकिन यह ज़रूर जोड़ा कि फैसला समय आने पर होगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह ठोक बजाकर ही लिया जाएगा. विगत लोकसभा चुनावों में भी ललन के मुंगेर से चुनाव लड़ने की इच्छा पर सूरजभान ने अपनी पत्नी को नवादा से लड़ाया था. इससे पूर्व रामविलास पासवान की मौजूदगी में ही मोकामा के जयप्रकाश चौक पर ललन सिंह को अपना राजनीतिक गुरु बताया था और कहा था कि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ वह कोई कदम नहीं उठा सकते हैं. इसी तरह अनंत सिंह भी अपनों के बीच यह कहते सुने जाते हैं कि आज वह कुछ भी हैं तो ललन बाबू की बदौलत और उनका साथ वह किसी भी क़ीमत पर नहीं छोड़ सकते. लोजपा नेता सूरजभान के भाई हरिओम उर्फ गुड्डू भी कहते हैं कि अभी सारी ऊर्जा किसान महापंचायत की सफलता में लगानी है और आगे का निर्णय इसके बाद लिया जाएगा. इसी प्रकार मोकामा विधायक अनंत सिंह के विधायक प्रतिनिधि चंचल कुमार और अन्य समर्थक बताते हैं कि वे हर हाल में ललन सिंह के साथ रहेंगे और उनका भी तर्क है कि आगे की रणनीति किसान महापंचायत के बाद ही तय होगी. प्रदेश जदयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अनंत सिंह ने अपने सरकारी आवास पर ललन समर्थकों को दावत देकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे. देखना यह है कि दबंग पृष्ठभूमि से आने वाले सूरजभान और अनंत सिंह के राजनीतिक गुरू ललन सिंह का अगला क़दम क्या होगा, लेकिन संभावनाएं और लगातार बदलती राजनीतिक फिज़ा अनंत सिंह और सूरजभान के साथ आने की ओर इशारा कर रही है.

feedback@chauthiduniya.com

बिहार मिनरल्स इंडस्ट्रीज लखीसराय
की तरफ से चौथी दुनिया बिहार-झारखंड की टीम व पाठकों को
हार्दिक बधाई

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 19 अप्रैल–25 अप्रैल 2010

दुनिया चाहे महिला सशक्तिकरण एवं आरक्षण पर लाख ढिंढोरा पीट ले, लेकिन बीसोडिहरी गांव के एक कोने में पड़ी पूर्व ज़िला पार्षद कंचन देवी की कहानी सबसे इतर है.

बहुत कुछ कहती है कंचन की कहानी

कहीं महिला सशक्तिकरण पर उठ रही है आवाज़ तो कहीं सदन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर चल रही बहस पर थपथपा रही हैं मेजें. लेकिन, यहां राजनीतिक दहलीज़ पर कुछ क़दम चलने के बाद एक महिला यूं थककर निढाल हो गई कि आज वह दाने-दाने को मोहताज़ है. जी हां, यह कहानी है रोहतास ज़िले के करगहर प्रखंड अंतर्गत करगहर पश्चिमी ज़िला परिषद क्षेत्र की एक दलित महिला की, जो कभी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी. नाम है कंचन देवी. लोगों की मानें तो कंचन शुरू से ही पढ़ाई-लिखाई में अव्वल रही. प्रखंड के बीसोडिहरी गांव में गाजे-बाजे के साथ दुल्हन बनकर पहुंची कंचन के घरवालों ने उसे 2001 में राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के मैदान में उतार दिया. चूंकि यह क्षेत्र दलित महिलाओं के लिए आरक्षित था और बाकी उम्मीदवारों में कंचन तेजतर्रार भी थी. इसीलिए जनता ने कंचन को लगभग एक हज़ार मतों के अंतर से जिताकर ज़िला परिषद में भेज दिया. पांच वर्षों तक क्षेत्र का विकास हुआ. कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. फूल-मालाओं से लोगों ने अपनी प्रतिनिधि का स्वागत किया. कंचन देवी के लच्छेदार भाषणों पर जमकर तालियां भी बजीं, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि राजनीति की पहरुआ बनकर क्षेत्र की वकालत कर रही इस दलित महिला के पेट में अन्न का दाना है भी या नहीं. किसी तरह से पांच वर्ष बीत गए. दोबारा हुए चुनाव में धन बल के सामने उसकी एक न चली. चुनाव हारकर कंचन देवी की दिनचर्या चूल्हा-चौकी के फेरे लेने लगी. पति को उत्तर बिहार के सीमांचल ज़िले में पंचायत शिक्षक की नौकरी तो मिली, लेकिन महंगाई की मार के चलते उसे मिल रहा वेतन भी कम पड़ने लगा. नतीजतन, वह आज तक एक फूटी कौड़ी भी अपने परिवार के लिए नहीं भेज सका. इधर अपने चार बच्चों के साथ घर में किसी तरह जीवनयापन कर रही कंचन को मनरेगा में मजदूरी पाने के लिए भी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं. अंत में गांव के बगल में चल रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना के एक ठेकेदार ने उसके दर्द को समझा, तब जाकर उसे मजदूरी का काम मिला. वह काम भी कुछ दिनों तक ही चला और फिर बंद हो गया. यह दर्द भरी कहानी पता चलने पर बीसोडिहरी पहुंची इस संवाददाता को देखते ही कंचन की आंखें छलक उठीं. उसने सिसकते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आरक्षण दे या आसमान में बैठा दे, इससे मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है. मैं तो यहां अपने बेबस बच्चों के पेट में उठ रही भूख शांत करने के लिए दिन भर तपती धूप में अपने जीवन को जला रही हूं. दुनिया चाहे महिला सशक्तिकरण एवं आरक्षण पर लाख ढिंढोरा पीट ले, लेकिन बीसोडिहरी गांव के एक कोने में पड़ी पूर्व ज़िला पार्षद कंचन देवी की कहानी सबसे इतर है. यहां न तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और न ही कोई बहुत बड़ी राजनीतिक सोच. बस समाजसेवा की एक निस्वार्थ भावना ने यहां असमय दम तोड़ दिया, जो पंचायती राज व्यवस्था पर एक कुठाराघात है.

कंचन कभी ज़िला पार्षद थीं, आज दाने-दाने को मोहताज है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र से दूर है बैद्यनाथ धाम

यह विडंबना नहीं तो क्या है कि जिस बाबानगरी में लाखों श्रद्धालु हर माह पहुंचते हों, उसका नाम आज भी राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में नहीं है. और, न ही इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय नेता भी इस दिशा में उदासीन बने हुए हैं.

द्वादश ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर बैद्यनाथ की नगरी बैद्यनाथ धाम आज भी राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र से दूर है. सावन महीने में भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने का विशेष महत्व है, इसलिए साठ लाख से अधिक श्रद्धालु सिर्फ़ इसी महीने बाबानगरी आते हैं. पुराणों में बैद्यनाथ धाम को हृदयपीठ एवं चिताभूमि भी कहा गया है, क्योंकि विष्णु के सुदर्शन चक्र से खंडित सती का हृदय यहीं गिरा था और भगवान शिव ने उनका अंतिम संस्कार यहीं किया था. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विश्वकर्मा ने यहां मंदिर का निर्माण किया था. यहां कई ऐतिहासिक मंदिर एवं सांस्कृतिक धरोहर भी हैं. 1948 में अष्टधातु से बना नौ लाख मंदिर बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की तरह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. इसके नज़दीक ही स्वामी बालानंद का आश्रम है, जिनके हज़ारों अनुयायी देश-विदेश में फैले हैं. शहर के नज़दीक ही महर्षि वाल्मीकि एवं रावण की तपोस्थली तपोवन है, जहां 350 वर्ष पुराना शिव मंदिर है. महर्षि बालानंद स्वामी ने यहीं सिद्धि प्राप्त की थी. प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत त्रिकूट पर्वत भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. ठाकुर अनुकूल चंद्र ने 1946 में यहीं सत्संग नगर की स्थापना की थी, जहां देश-विदेश में बसे उनके लाखों अनुयायी समारोह में हिस्सा लेने आते रहते हैं. इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध रिखिया योगपीठ में वर्ष पर्यंत हज़ारों भक्तों का आना-जाना लगा रहता है. योगपीठ में आने वाले भक्तजनों में अधिकांश का संबंध संभ्रांत वर्गों से होता है. राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ भी देवघर का अमूल्य संस्थान है, जहां हज़ारों विद्यार्थी विद्या अर्जन कर उच्च पदों पर देश की सेवा में कार्यरत हैं.

इतना महत्वपूर्ण तीर्थस्थल होने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार ने बैद्यनाथ धाम देवघर को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की. आलम यह है कि आसनसोल रेल डिवीजन के अंतर्गत बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन से देश के किसी भी महानगर तक की सीधी रेलसेवा नहीं है. निकटतम जसीडीह स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में आरक्षण मिलना काफी मुश्किल रहता है. बिना आरक्षण के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सफर करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. हालांकि रेलमंत्री रेल बजट-2010 में तीर्थस्थलों को सीधे रेल सेवा से जोड़ने की प्रशंसनीय पहल की है, लेकिन इसमें बैद्यनाथ धाम को शामिल नहीं किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जोड़ने की पहल अब तक नहीं की गई. स्थानीय सड़कें भी निम्नस्तरीय हैं. यहां एक भी उच्च क्षमता वाला विश्रामगृह नहीं है. सबसे दु:खद स्थिति है पेयजल आपूर्ति की, जिसका समाधान आज तक नहीं हो सका. लचर विद्युत आपूर्ति भी यहां की समस्याओं में है. जबकि विभाग प्रति वर्ष करोड़ों रुपये ख़र्च कर रहा है. राजनीतिज्ञों ने भी इस ओर अब तक ठोस इच्छाशक्ति नहीं दिखाई, ताकि बैद्यनाथ धाम देवघर को राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर स्थान मिल सके और बाबानगरी का सर्वांगीण विकास हो.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भोजपुरिया अंदाज़ भाता है

फ़िल्म अशोका में शाहरुख के अपोजिट काम कर चुकी स्वीट एंड सिंपल गर्ल ऋषिता भट्ट आजकल भोजपुरिया फ़िल्मों में छाई हुई हैं. बॉलीवुड से भोजपुरी आने पर सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें उनकी इमेज के चलते मिला. दरअसल हिंदी फ़िल्मों में उनके द्वारा निभाई गईं ज़्यादातर भूमिकाएं सीधी-सादी लड़कियों की थीं और भोजपुरी फ़िल्मों में क्षेत्रीय लुक वाली अभिनेत्रियों को तरजीह दी जाती है, इसलिए उन्हें निर्माता-निर्देशकों ने हाथों-हाथ लिया. अपनी शुरुआत ही उन्होंने भोजपुरिया बाहुबली रवि किशन के साथ फ़िल्म बाबुल प्यारे से की. फ़िल्म जबरदस्त हिट भी रही. इस फ़िल्म में उनके साथ राजबब्बर ने भोजपुरी में क़दम रखा था. गौरतलब है कि यह फ़िल्म पिता और पुत्री के संबंधों पर आधारित थी. ऋषिता और राजबब्बर ने बतौर लीड, पिता और पुत्री की भूमिका अदा की. जबकि रवि किशन दामाद की भूमिका में थे. इस फ़िल्म की भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी शूटिंग लंदन की उन लोकेशंस पर की गई थी, जहां शूटिंग के लिए अनुमति आसानी से नहीं मिलती. इस बिग बजट फैमिली ड्रामा के बाद उनकी अगली फ़िल्म दिल दीवाना तोहार हुवा भी बॉक्स आफिस पर हिट रही. मशहूर कोरियोग्राफर सरोज ख़ान द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में उनके साथ प्रीति झिंगियानी भी मुख्य भूमिका में थीं. बावजूद इसके ऋषिता के किरदार को भरपूर सराहना मिली. ऋषिता के मुताबिक, मुझे जब बाबुल प्यारे का ऑफर मिला, तब कई लोगों ने कहा कि हिंदी फ़िल्मों को छोड़ कर भोजपुरी में जाने का फैसला ग़लत है. लेकिन मुझे फ़िल्म की कास्ट और कहानी के अलावा भोजपुरिया अंदाज़ इतना पसंद आया कि मैं मना नहीं कर पाई. आज मुझे खुशी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है. यहां काम करने वाले सितारों का स्टारडम विदेशों तक फैल रहा है. मैं अभी भी एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही हूं. अच्छी स्टोरी मिलते ही आपको भोजपुरिया अंदाज़ में दिखाई दूंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

दिल्ली, 19 अप्रैल–25 अप्रैल 2010

www.chauthiduniya.com

निवेशक भाग रहे हैं

मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश जैसे उपनामों से भले ही सजाते रहें या यह दावा करते रहें कि भविष्य में राज्य का चेहरा बदलेगा पर असलियत कुछ और ही बयां करती है. आर्थिक विकास के लिए जिन औद्योगिक इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया था, अब वो सरकारी लालफीताशाही के शिकार हैं. लिहाज़ा ज़्यादातर इकाईयां अपना बोरिया-बिस्तर समेटने पर मजबूर हैं.

विनय दीक्षित

मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और राज्य में आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए सरकार देश-विदेश से पूंजी निवेश कराने के लिए पिछले पांच वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रीगण आला अफ़सरों के साथ देश-विदेश के दौरे भी कर चुके हैं. राज्य में निवेशकों का मेला लगाकर उन्हें सब्जबाग़ भी दिखाए गए. इससे प्रभावित होकर कई निवेशकों ने राज्य सरकार पर भरोसा कर भारी-भरकम पूंजी निवेश के लिए सहमति भी जता दी, लेकिन थोड़े ही दिनों में राज्य सरकार के कामकाज का जायज़ा लेने के बाद कई समझदार निवेशकों ने अपने पूंजी निवेश संबंधी प्रस्ताव वापस ले लिए या जानबूझकर रद्द कर दिए. कुछ ने सरकारी विभागों में व्याप्त लालफीताशाही एवं नौकरशाही के सुस्त और टालू रवैये से तंग आकर, तो कुछ ने भ्रष्टतंत्र से उकताकर राज्य में पूंजी निवेश करने से तौबा कर ली है.

अधिकृत सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में 1389.8 अरब रुपयों के पूंजी निवेश संबंधी करार किसी न किसी कारण से रद्द हो चुके हैं. इनमें 1259 अरब रुपयों के पूंजी निवेश प्रस्ताव विभिन्न बिजली परियोजनाओं से संबंधित थे. घोर बिजली संकट झेल रहे मध्य प्रदेश प्रशासन को बिजली उत्पादन के लिए मिले निजी क्षेत्र के सहयोग का लाभ उठाना भी पसंद नहीं आया और अनेक अड़ंगे लगाकर प्रशासन तंत्र ने पूंजी निवेशकों को राज्य से भगा दिया. इस हक़ीक़त के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में विकास और पूंजी निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेन्डली माहौल होने का दावा कर रहे हैं. उनके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री और पूर्व उद्योग मंत्री बाबूलाल गौर का भी दावा है कि निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. निवेशकों की तमाम शिकायतों और समस्याओं को ग़लत बताते हुए राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव सत्यप्रकाश कहते हैं कि सरकार का इन्वेस्टर्स के प्रति सहयोगात्मक रुख है. प्रदेश के विकास के लिए हम भी चाहते हैं कि निवेश हो. यदि निवेशकों से कहीं कोई कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो इसकी शिकायत करनी चाहिए थी. अभी तक रिश्वत मांगने की हमारे पास कोई शिकायत नहीं है और न ही किसी ने मौखिक जानकारी दी है. इस तरह शासन और प्रशासन पर आरोप लगाना ग़लत है.

उल्लेखनीय है कि जनवरी 2010 में राज्य सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों को राज्य में पूंजी निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था. इस सम्मेलन में भाग लेने आए एक प्रवासी भारतीय पीसी त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से राज्य में फैले भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर कहा था, तब मुख्यमंत्री ने राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होने की दलील देकर भरोसा दिलाया था कि सरकार निवेशकों की पूरी सहायता करेगी. लेकिन निवेशकों के अनुभव कुछ और ही कहते हैं. वे मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर आला अफ़सर तक कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि राज्य के प्रशासन में हर स्तर पर भ्रष्टाचार मौजूद है.

मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासन के आला अफ़सरों का बयान भले ही उनकी ज़िम्मेदार हैसियत के कारण सही हो, लेकिन करोड़ों रुपया निवेश करके राज्य के विकास में रुचि लेने वाले निवेशक भला अनुकूल माहौल छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, इसपर गंभीरता से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. मेसर्स लोरेडा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रतिनिधि ए दलाल का कहना है कि धार ज़िले में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए 450 करोड़ रुपयों का करार किया गया था, लेकिन जब हमारे अधिकारी ज़मीन देखने गए तो ज़िला कलेक्टर से लेकर निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों तक का रवैया असहयोगात्मक और अड़ंगे लगाने वाला था. ज़मीन के लिए हमने पांच आवेदन पत्र लगाए, लेकिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी. इस बारे में उद्योग मंत्री जयंत मलैया से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक शिकायत की गई, लेकिन कोई सकारात्मक सहयोग नहीं मिला. इस कंपनी ने 2007 में गुजरात में 355 करोड़ रुपयों का निवेश पर्यटन के क्षेत्र में करने का क़रार किया था. वहां गुजरात सरकार से उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिला, इसलिए वहां कंपनी का प्रोजेक्ट भी जल्दी ही शुरू होने वाला है. जिंदल इंडिया थर्मल पॉवर लिमिटेड के ए के सहदेव का कहना है कि 9000 करोड़ रुपयों की लागत से 2000 मेगावाट का बिजली संयंत्र सीधी ज़िले में लगाने का क़रार किया गया था, लेकिन कोयले की उपलब्धता की कमी और अन्य वज़हों से कंपनी ने निवेश का इरादा बदल दिया है. इसी तरह मेघालय सीमेंट लिमिटेड के एचसी कपिल का कहना है कि सरकार में सामंजस्य न होने से वे 600 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाने का क़रार रद्द करना चाहते हैं. कंपनी के हित में और अनुशासन के कारण वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं. मेसर्स भूषण स्टील लिमिटेड के महाप्रबंधक एम जे धर का कहना है कि सरकार द्वारा ज़मीन उपलब्ध कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई. इसीलिए इन्वेस्टमेन्ट करना बेकार है.

एक अन्य पूंजी निवेशक संस्था के प्रतिनिधि ने अपना नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के अफ़सर बड़े-बड़े आश्वासन तो देते हैं, और सरकार की तारीफ़ के पुल भी बांधते हैं, लेकिन जब निवेश संबंधी क़रार संपन्न हो जाता है, तो उनकी नज़रें बदल जाती हैं और सभी वायदों को भुला दिया जाता है. इसलिए हम भी क़रार तोड़ना ही उचित समझते हैं.

आर्थिक विकास के इस नये दौर में भारत तेज़ी से तरक़्क़ी करना चाहता है और कई राज्यों में तरक़्क़ी की नई मंज़िलें तय की जा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश आज भी देश के पिछले और ग़रीब राज्यों की जमात में शर्म से सिर झुकाए खड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके प्रचार-प्रबंधक, अख़बारों और मीडिया में बार-बार *स्वर्णिम मध्य प्रदेश* और *आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश* का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन जब कभी प्रदेश के विकास के लिए कोई ठोस प्रयास होते हैं, तो उनमें अड़ंगे लगाने वाली दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने में मुख्यमंत्री अपनी शक्तियों का उपयोग करना भूल जाते हैं. यही वज़ह है कि मुख्यमंत्री के वायदों पर भरोसा कर राज्य में करोड़ों रुपयों का निवेश करने के इच्छुक देशी-विदेशी पूंजीपति मध्य प्रदेश से तौबा करके भाग रहे हैं.

प्रमुख पूंजी निवेश के निरस्त हुए क़रार

सत्यप्रकाश
आईएएस अधिकारी

पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के अफ़सर बड़े-बड़े आश्वासन तो देते हैं और सरकार की तारीफ़ के पुल बांधते हैं, लेकिन जब निवेश संबंधी क़रार संपन्न हो जाता है, तो उनकी नज़रें बदल जाती हैं और सभी वायदों को भुला दिया जाता है. इस कारण निरस्त हुए क़रारों के नाम नीचे देखे जा सकते हैं.

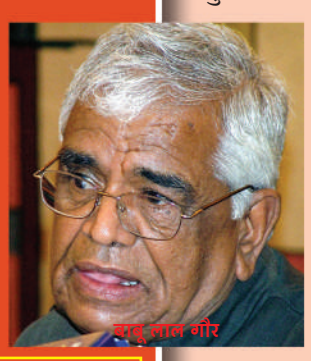

बाबूलाल गौर

- मेघालय सीमेन्ट प्राइवेट लि. कोलकाता - 4 हज़ार 500 करोड़ रुपये
- मे. वीनस मार्केन्टाइल कंपनी प्राइवेट लि. मुम्बई - 1100 करोड़ रुपये
- मे. भूषण स्टील प्राइवेट लि. प्रस्तावित निवेश - 3 हज़ार करोड़ रुपये
- इलेक्ट्रोथर्म प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद - 700 करोड़ रुपये
- रेहावा रिसोर्स प्राइवेट लि. - 2100 करोड़ रुपये
- मे. सिम्बाली शुगर प्राइवेट लि. - 400 करोड़ रुपये
- नोवा एण्ड फेरो एलॉय प्राइवेट लि.- 100 करोड़ रुपये
- करेली शुगर मिल लि.- 200 करोड़ रुपये
- लोरेडा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.- 425 करोड़ रुपये
- ईआरएस इन्वॉयरमेंट रिसर्च एण्ड सर्विसेस लंदन - 918 करोड़ रुपये
- आईटीएल इंडस्ट्रीज लि. - 52 करोड़ रुपये
- ऑटोमेटिव एक्सेल लि. - 119 करोड़ रुपये
- मे. यूके लैण्ड बैंक लि. - 1600 करोड़ रुपये
- लेंड कॉर्प पार्टनर - राशि नहीं दी गई
- जिंदल पाईप्स लि. गुड़गांव, 1000 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट - 3 हज़ार 983 करोड़ रुपये
- लैंको इन्फ्राटेक लिमिटेड, 1200 मेगावाट क्षमता पॉवर प्लांट - 5000 करोड़ रुपये
- टोरेन्ट पॉवर लि. अहमदाबाद, 1000 मेगावाट क्षमता पॉवर प्लांट - 4000 करोड़ रुपये

24 बिजली कंपनियां क़रार करके ग़ायब

उधर ऊर्जा विभाग के सूत्रों का कहना है कि 24 विद्युत उत्पादन कंपनियों ने राज्य में 26135 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र लगाने के लिए 1,25,925 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश करने के क़रार किए थे, लेकिन 31 मार्च बीत जाने के बाद भी इन कंपनियों ने क़रार की शर्तों के अनुसार न तो कोई काम किया और न ही काम करने में कोई रुचि दिखाई. इतना ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा किए गए पत्र व्यवहार का भी इन कंपनियों ने कोई जवाब नहीं दिया. क़रार की समयावधि 31 मार्च 2010 को पूरी हो गई है, लेकिन इन 24 कंपनियों ने सरकार को अपनी प्रगति रिपोर्ट तक पेश नहीं की है. इस कारण सरकार इन कंपनियों के ख़िलाफ़ कठोर क़दम उठा सकती है.

ऊर्जा सचिव एसपीएस परिहार ने भी माना है कि 24 कंपनियों ने सरकार के साथ किए गए क़रार की शर्तों का पालन नहीं किया है. हर महीने इन कंपनियों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने की शर्त अनुबंध में थी, लेकिन कंपनियों ने यह शर्त पूरी नहीं की. इसीलिए क़रार की समयावधि 31 मार्च को पूरी हो जाने के बाद सरकार आगामी कार्यवाही के बारे में विचार करेगी. हालांकि, निवेशकों की राय में ख़ुद सरकार ही इसके लिए ज़िम्मेदार है. उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें जो भी आश्वासन दिए थे, उनके अनुरूप ज़मीनी अधिकारियों ने सहयोगात्मक रुख़ नहीं अपनाया, इसीलिए निराश होकर क़रार तोड़ना पड़ रहा है.

क़रार कर लेने के बाद विद्युत संयंत्र स्थापित न करने से राज्य को 26135 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लाभ से वंचित होना पड़ेगा और 125925 करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश भी अब राज्य में होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं. इन कंपनियों द्वारा अब तक निवेश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने के कारण राज्य सरकार ने उन्हें अघोषित चेतावनी देते हुए मंत्रालय तलब किया था. इन कंपनियों ने अबतक न ज़मीन ख़रीदने की कोशिश की है और न ही बिजली यूनिटों के लिए पानी का कोई बंदोबस्त किया है. इनमें से किसी

(शेष पृष्ठ 18 पर)

ज़्यादातर राज्यमंत्रियों की शिकायत है कि उनके ऊपर बैठे कैबिनेट मंत्री उन्हें न तो कोई काम देते हैं और न ही उनकी सुनी जाती है.

प्रधानमंत्री ने इस प्रकरण की जांच के लिए राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन की अध्यक्षता में 6 सांसदों की समिति भी गठित की थी.

कोटवारों को इंसाफ कब मिलेगा

[illegible]

ज़िले में मेरी नई पोस्टिंग है, पर मैं मानता हूं कि कोटवार की समस्याएं गंभीर हैं, जिसके लिए अगले सप्ताह अधिकारियों एवं संबंधित विभाग की बैठक बुलाकर उस पर विचार करके समाधान किया जाएगा. तकनीकी कारणों से कोटवारों को भूमि आवंटन में समस्या आ रही है.

गुलशन बामरा, कलेक्टर जबलपुर

के नाम की यह ज़मीन सेवा भूमि के नाम पर ही दर्ज़ चली आ रही है. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन 9632/2000 में 11 कोटवारों को भूमि स्वामी अधिकार जारी करने के निर्देश दिए गए थे. इसी प्रकार 1985 में राजस्व निर्णय 228 में जबलपुर उच्च न्यायालय ने भी कहा था

[illegible]

आरती पटेल
feedback@chauthiduniya.com

घरेलू काम भी करते हैं कोटवार

[illegible]

[illegible]

[illegible]

महुआ संग्रहण

आत्मनिर्भरता की ओर एक क़दम

आदिवासी क्षेत्रों में रोज़गार पाना एक गंभीर समस्या है. आधारभूत संरचनाओं के अभाव और औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़े आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और परिवर्द्धन कर रोज़गार की संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महुआ फूलों को संरक्षित कर रोज़गार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जा रही है. विभिन्न औषधीय उपयोगों के लिए महुआ के फूलों को संग्रहित कर सुखाया जाता है, ताकि इसे विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जा सके. इसी का नतीज़ा है कि केवल एक ज़िले में महुआ के फूलों से 17 लाख रुपये से अधिक आर्थिक लाभ अर्जित कर इस क्षेत्र के कई ग्रामीण अपनी जीविका चला रहे हैं.

सिंगरौली ज़िले में महुआ वृक्ष बड़ी संख्या में उपलब्ध है. वनमंडल, सिंगरौली के मुताबिक़, इस क्षेत्र में 13 लाख महुआ के वृक्ष हैं, जो वनक्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की वृक्षों का लगभग 4.16 प्रतिशत है. इतना ही नहीं, राजस्व क्षेत्र में भी महुआ के वृक्ष पर्याप्त संख्या में हैं. इस ज़िले में प्रतिवर्ष 1.30 लाख टन महुआ का उत्पादन होता है, जो इस क्षेत्र की ग़रीब जनता के लिए आय का प्रमुख ज़रिया है.

राज्य शासन के वन विभाग के सौजन्य से आदिवासी क्षेत्र सिंगरौली में महुआ फूलों के संग्रहण से लेकर सुखाने तक की व्यवस्था के साथ उसकी बिक्री-दर में सुधार की आवश्यकता का परीक्षण कर एक योजना तैयार की गई थी. इसके अंतर्गत, पिछले दो वर्षों में इसके उत्साहजनक परिणाम भी सामने आए हैं. परिणामों से प्रभावित वन विभाग ने इस वर्ष के लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है. वनमंडल सिंगरौली में स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से 2008 में महुआ फूल संग्रहण कार्य प्रारंभ हुआ. इसके अंतर्गत 1157.42 क्विंटल महुआ फूलों का संग्रहण 7 क्षेत्रों के 36 समूहों के माध्यम से कराया गया. वर्ष 2009 में 132 समूहों के ज़रिए 1585 क्विंटल महुआ फूल का संग्रहण किया गया. इसमें से 2.65 क्विंटल नेट के माध्यम से किया गया.

महुआ फूलों के संदर्भ में चर्चा करते वन अधिकारी

महुआ फूलों को ले जाती महिला

महुआ के फूल

नेट के ज़रिए महुआ फूल संग्रहण की योजना इस क्षेत्र में प्रभावशाली रही है. इस प्रक्रिया में महुआ के पेड़ के नीचे मच्छरदानी की नेट का उपयोग कर फूलों को ज़मीन में गिरने से पहले धूल रहित संग्रहित कर लिया जाता है. फूलों में कचरा न होने के कारण बाज़ार में उसकी अच्छी क़ीमत मिलती है. वर्ष 2009 में 1584 क्विंटल महुए से संग्रहकों को 17.42 लाख रुपए का भुगतान किया गया. इस संग्रहण से 13.35 लाख रुपये की शुद्ध आय लघु वनोपज संघ को हुई है.

इस वर्ष महुआ संग्रहण के लिए 132 समूहों के अलावा 332 नए समूहों का गठन कराया गया है. पूर्व में गठित समूहों को प्रशिक्षित कर संग्रहण एवं प्रसंस्करण में पारंगत किया गया है. नए समूहों को आधुनिक एवं उन्नत तरीक़े से संग्रहण, सुखाई, भंडारण और भराई कार्यों आदि के लिए प्रशिक्षित किया गया है. अब सिंगरौली ज़िले में महुआ संग्रहण के कार्य को कुल 462 स्वयं सहायता समूह पूरा कर रहे हैं.

सिंगरौली ज़िले में महुआ संग्रहण एक व्यापार की तरह तेज़ी से प्रगति कर रहा है. दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण स्वयं इस योजना के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि सिंगरौली ज़िले में राज्य का सबसे अधिक महुआ उत्पादन होता है. इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पैर फैलाने के कारण दूर-दराज के आदिवासियों को अपने परंपरागत व्यवसायों को सुनियोजित करने में लघु वनोपज संघ मदद कर रहा है.

एस बी सिंह
feedback@chauthiduniya.com

सार-संक्षेप

दो अभ्यारण्य संकट में

सतना ज़िले में बनने वाले दो अभ्यारण्य इन दिनों सरकारी दस्तावेजों के मध्य कहीं गुम हो गए हैं. वन्य प्राणियों को सुरक्षित करने के नाम पर इन अभ्यारण्यों का निर्माण मार्कन्डे और सर्भंग ऋषि के नाम पर किया गया था. इन प्राकृतिक स्थानों के लिए राज्य शासन द्वारा की गई पहल से यह उम्मीद जगी थी कि इनके माध्यम से उपेक्षित रामनगर क्षेत्र में स्थित मार्कन्डे ऋषि का पूर्व आश्रम और सर्भंग ऋषि के आश्रम का भी उद्धार हो जाएगा. राज्य शासन द्वारा इस काम के लिए गौचर भूमि भी उपलब्ध करवाई जा रही थी. सूत्रों के अनुसार आठ माह पहले बनी योजना को तैयार करने वाला वन विभाग ही अब इस योजना में कोई रूचि नहीं रखता है. ये दोनों ही आश्रम नदियों के क़रीब बनने थे, जिससे जानवरों की पेयजल समस्या का भी स्थाई निदान किया जाना था. योजना यहां तक थी कि इन अभ्यारण्यों की स्थापना के बाद पर्यटन स्थलों को भी इसी अनुसार विकसित किया जाएगा, जिससे ज़िले के विकास में मदद मिलेगी.

अफ़सरों का भ्रष्टाचार जारी है

मध्य प्रदेश के आई.ए.एस., आई.पी.एस अधिकारियों में बढ़ती भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का कोई हल नहीं मिल रहा है. टीनू जोशी, अरविन्द जोशी के प्रकरण के बाद से अब भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे राज्य की बे-लगाम और भ्रष्ट अफ़सरशाही का नया चेहरा सामने आ रहा है. पिछले दिनों झाबुआ के पूर्व कलेक्टर द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के पैसों में की गई हेराफेरी राज्य में चर्चा का विषय बनी है. करोड़ों रुपये की इस हेराफेरी में कई बड़े राजनेताओं सहित राज्य सचिवालय में पदस्थ बड़े अफ़सरों के नाम शामिल है. इसके अतिरिक्त लोकायुक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा सहित भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम चलाने वाले संगठन इन दिनों ख़ासे सक्रिय हैं. कई जगहों पर तो पकड़े गए भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भी व्यापक भ्रष्टाचार किये जाने की ख़बरे प्राप्त हो रही हैं. प्रदेश शासन इन दिनों पूर्णत: अस्थिर है. राजनीति एवं प्रशासन दोनों ही आम व्यक्ति के लिए प्रश्न बन चुके हैं.

सुषमा, विदिशा मनरेगा से असंतुष्ट

भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता और लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज को अब पता चला है कि मध्य प्रदेश का प्रशासन किस तरह काम करता है. सुषमाजी विदिशा से लोकसभा सदस्य हैं और वे अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी रुचि भी ले रही हैं. अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार की क़ाग़जी उपलब्धियों और सरकारी प्रचार से ख़ुश और संतुष्ट सुषमाजी को हाल ही विदिशा में प्रशासन की करतूतों का जब पता चला, तो वे बड़ी दुखी और नाराज़ हुईं. संसद सदस्य के नाते सुषमा स्वराज पिछले दिनों ज़िला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुई थीं. इस बैठक में महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और अधिकारियों ने योजना के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट में जब यह बताया गया कि ज़िले के लगभग 200 गांवों में किसी भी ग्रामीण ने रोज़गार की मांग नहीं की, इसलिए इस योजना के तहत कोई काम नहीं कराया गया, इस पर सुषमा आश्चर्य चकित रह गईं. ज़ाहिर है, चुनाव प्रचार अभियान के दौरान तथा जनसंपर्क दौरों में उन्होंने स्वयं विदिशा ज़िले के प्राय: सभी गांवों में ग़रीबी और बेरोज़गारी का दुखदायी मंजर देखा है. वे समझ गईं कि यहां भी कहीं न कहीं कोई घपला-घोटाला चल रहा है. वास्तविकता यह है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के कारण ग्रामीणों की रुचि कम हो रही हैं. विदिशा ज़िले में लगभग दो सौ ऐसे गांव हैं, जिनमें इस योजना के अंतर्गत रोज़गार पाने के लिए एक भी ग्रामीण ने मांग नहीं की. राज्य में ऐसे अनेक ज़िले हैं जहां सरकारी अफ़सरों ने दर्ज़ कर रखा है कि गांवों में रोज़गार चाहने वालों की कमी के कारण रोज़गार गारंटी योजना के तहत कोई काम नहीं कराया गया है. विगत वित्त वर्ष में विदिशा ज़िले में इस योजना के अंतर्गत जो काम कराते थे, उनमें 85 प्रतिशत काम साल भर बाद भी अधूरे ही पड़े हुए हैं. ज़िले में जॉब कार्डधारकों में से केवल 11.5 प्रतिशत कार्डधारियों ने ही रोज़गार की मांग की. विदिशा ज़िले में एक अप्रैल 2008 से यह योजना शुरू हुई है. इसे प्रशासन के ज़मीनी अधिकारियों की लापरवाही कहिए या ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव, यही वजह है कि इन ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. वर्ष 2009-10 में ज़िले में 3794 निर्माण कार्य शुरू कराए गए, लेकिन 540 काम ही पूरे हो सके हैं. बैठक में पूरी कार्यवाही और सरकारी रिपोर्ट देखने के बाद सुषमा स्वराज ने मनरेगा की प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष और अप्रसन्नता ज़ाहिर करते हुए उन्होंने अफ़सरों को फटकार लगाई. सुषमा स्वराज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबों और खेतीहर मज़दूरों को रोज़गार दिलाने तथा छोटे-छोटे सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कार्य कराने के लिए केन्द्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया है और इसके लिए अरबों रुपया हर साल ख़र्च किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार ने प्राय: सभी ज़िलों में इस योजना को लागू किया है और पर्याप्त धन आवंटन भी किया है, लेकिन दुख की बात है कि इस योजना का लाभ ज़रूरतमंद ग्रामीण, ग़रीबों, अति छोटे किसानों और खेतीहर मज़दूरों को नहीं मिल रहा हैं, इसके लिए प्रशासन तंत्र ज़िम्मेदार है.

मध्य प्रदेश बन रहा है धन प्रदेश

ग़रीबी, बेरोज़गार और तमाम अभावों से पीड़ित मध्य प्रदेश में धनपति भी हर साल बढ़ रहे हैं, यह एक अच्छी ख़बर है. मध्य प्रदेश में धनपतियों की सूची में इस वर्ष साठ नए करोड़पतियों के नाम शामिल हो गए हैं. [illegible]

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

निवेशक भाग रहे हैं

पृष्ठ 17 का शेष

भी कंपनी को केंद्र से कोल लिंकेज भी नहीं मिला है.

दूसरी ओर, इन कंपनियों ने अपनी ओर से अब तक कार्य में प्रगति नहीं होने के संबंध में अपनी कुछ दिक्कतें बताई हैं. कुछ कंपनियों ने पसंदीदा ज़मीन के फॉरेस्ट लैण्ड होने का ज़िक्र करते हुए भूआवंटन न होने को कारण बताया है. उनका कहना है कि अब नए स्थल का चयन करने में समय लग रहा है. इन कंपनियों ने यह भी सफ़ाई दी कि कोल लिंकेज के लिए आवेदन दिया गया है, लेकिन न तो ज़मीन है और न पानी का बंदोबस्त. ऐसे में कोल लिंकेज का मिलना, संभव नहीं है. लिहाज़ा, ऊर्जा सचिव ने स्थल चयन के काम को शीघ्र पूरा करने की सलाह दी थी. इन कंपनियों से करार की अवधि सितम्बर में समाप्त हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने उस समय करार रद्द करने के बजाए इसकी अवधि को 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया था. सरकार इससे पहले भी ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली तीन कंपनियों, जिंदल पाइप, लेंका इंफ्राटेक और टोरेंट पावर के 12983 करोड़ के करार विभिन्न कारणों से रद्द कर चुकी है.

पिछले पांच वर्षों में खजुराहो, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर के अलावा अमेरिका में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित कर सरकार ने लगभग सवा तीन लाख करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश संबंधी करार संपन्न कराने में सफलता पाई थी, लेकिन राज्य विधानसभा में सरकार की ओर से बताया गया कि इस अवधि में केवल 2932 करोड़ रुपयों के निवेश ही मिल पाए हैं. इन निवेशकों ने तो काम शुरू भी कर दिया है. अबतक कुल 3250 अरब रुपयों के निवेश के करारों में से 1389 करोड़ रुपयों के निवेश करार या तो रद्द हो चुके हैं या रद्द होने की कगार पर हैं.

feedback@chauthiduniya.com

प्रशासनिक अनुशासनहीनता और अराजकता का चरम दौर

संध्या पांडे

मध्य प्रदेश में इन दिनों शासन-प्रशासन में अनुशासनहीनता और अराजकता का चरम दौर चल रहा हैं. मंत्री आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तत्व सरकारी कर्मचारी, विधायकों और मंत्रियों से खुलकर लड़ झगड़ रहे हैं. राज्य सरकार के ज़्यादातर राज्यमंत्रियों को शिकायत है कि उनके ऊपर बैठे कैबिनेट मंत्री उन्हें कोई काम नहीं देते हैं और विभाग में आला अफ़सर उनकी ज़रा भी नहीं सुनते हैं. कई राज्य मंत्रियों ने तो मंत्रालय में अपने कक्षों में बैठना ही बंद कर दिया है. एक राज्यमंत्री का कहना है कि कक्ष में फालतू बैठे रहने से क्या फ़ायदा? यदि हम कक्ष में बैठते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक हमसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलते हैं, लेकिन जब विभाग में अफ़सर हमारी सुनते ही नहीं हैं, तो हम उनकी समस्याओं का निपटारा कैसे कर सकते हैं? वरिष्ठ और कनिष्ठ मंत्रियों के बीच का यह विवाद राज्य प्रशासन के लिए नया नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ग्वालियर में अचानक ही इसने विष्फोटक रूप ले लिया. गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ग्वालियर में अपने गृह राज्यमंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के घर उनके भाई के निधन पर शोक जताने गए थे, लेकिन कई दिनों से मंत्रीजी द्वारा लगातार उपेक्षा और तिरस्कार सह रहे कुशवाहा मंत्रीजी को देखकर भड़क गए, उन्होंने गुप्ताजी को खूब ख़री-खोटी सुनाई. कुशवाहा ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा-अब क़ानून व्यवस्था पर न तो आप (गृहमंत्री) क़ाबू पा सकते हैं और न ही मुख्यमंत्री. पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट मंत्री पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हैं, तो राज्य में बिगड़ती क़ानून व्यवस्था की स्थिति के लिए भी वे ही ज़िम्मेदार हैं.

उल्लेखनीय हैं कि नारायण सिंह कुशवाहा कई बार शिकायत कर चुके हैं कि उच्च पुलिस अधिकारियों और गृह विभाग के आला अफ़सरों के साथ की जाने वाली विभागीय बैठक में उन्हें भाग लेने नहीं दिया जाता हैं और यदि कभी किसी बैठक में बुलाया भी जाता है, तो बोलने नहीं दिया जाता है. कुशवाहा के गुस्से के कई कारण हैं. गत 27-28 मार्च को उनके निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क़ानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर धरना दिया था. उस समय उनका छोटा भाई अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार था, तब भी कांग्रेसजनों ने उनका और उनके परिवारजनों का रास्ता रोककर उन्हें अस्पताल नहीं जाने दिया. पुलिस भी राज्यमंत्री की कोई सहायता नहीं कर पाई. क़ानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में गृह राज्यमंत्री ने पुलिस के आला अफ़सरों से कुछ पुलिस कर्मचारियों को बदलने की आवश्यकता बताई थी, लेकिन अफ़सरों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. गृह विभाग में कोई महत्व न दिए जाने की शिकायत कुशवाहा ने गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता से की, तो उन्होंने उसे अनसुना कर दिया. बाद में उन्होंने यही शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से की तो उन्होंने बड़े सामान्य तरीक़े से, देख लेंगे और इस बारे में बात करेंगे कहते हुए नारायण सिंह कुशवाहा को टाल दिया. गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के चले जाने के बाद ग्वालियर में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर गृह राज्य मंत्री कुशवाहा ने कहा कि चूंकि मुसीबत के समय कांग्रेसजनों ने उनके घर के सामने धरना दिया था और उन्हें जानबूझकर परेशान किया था, इसलिए अब वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर निवास पर 48 घंटे का धरना देंगे. पार्टी उनका साथ दे या न दे, वे धरना पर ज़रूर बैठेंगे. राज्य में क़ानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर कुशवाहा ने कहा कि इस सरकार में राज्यमंत्री के अधिकार कितने हैं, यह भाजपा के नेता अच्छी तरह जानते हैं. एक प्रश्न के उत्तर में कुशवाहा ने कहा कि यदि धरना देने के कार्यक्रम में उनका मंत्री पद बाधक है, तो वह त्यागपत्र देकर धरना पर बैठेंगे. लेकिन जानकारों का कहना है कि कुशवाहा त्याग पत्र देने वाले नहीं हैं. वह केवल मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के लिए यह तमाशा कर रहे हैं.

नारायण कुशवाहा

विजय शाह

मंत्रीजी पिटते-पिटते बचे

शिवपुरी में 5 अप्रैल को आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह की उपस्थिति में विधायकों, भाजपा नेताओं और सरकारी अमले पर लोगों ने हमला किया. इस हमले से बचने के लिए कोई अपने जूते छोड़कर भागा तो किसी ने आसपास के घरों में छिपकर जान बचाई. मंत्री विजय शाह भी हमले से बचने के लिए विधायक रमेश खटीक के साथ पास ही एमएल शिवहरे के मकान में छिपकर बैठे रहे. बाद में हालात सामान्य होने पर वे पुलिस सुरक्षा में बाहर निकले.

इस बारे में बताते हैं कि मंत्रीजी को शिकायत मिली थी कि अंत्योदय व्यवसायी योजना के तहत दिए गए ऋण के मामले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है. यह मामला विधानसभा में भी उठा था और मंत्रीजी ने स्वयं जांच करने का आश्वासन भी दिया था. इसीलिए वे मामले की जांच करने गए थे. इस बारे में बताया जाता है कि एक ही परिवार के सदस्यों को लगभग 27 लाख रुपयों के ऋण विभिन्न व्यवसायों के लिए दिए गए थे, लेकिन ऋण लेने के बाद भी किसी ने व्यवसाय शुरू नहीं किया था. मंत्री विजय शाह इस बारे में प्रत्यक्ष जायज़ा लेने पहुंचे थे. उनके पहुंचते ही वहां ऋण लेने वाले हितग्राही भड़क उठे और सबसे पहले उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता महेश चंद्र डागौर को गंदी गालियां देते हुए उससे मारपीट शुरू कर दी. कुछ लोगों ने उसे बचाना चाहा लेकिन इसी बीच पूर्व विधायक ओमप्रकाश खटीक, विधायक रमेश खटीक और माखनलाल राठौर तथा उनके साथ गए सरकारी अफ़सरों और कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया. हमले से बचने के लिए सब इधर-उधर भागने लगे और अफरा-तफरी मच गई. मंत्रीजी भी जान बचाकर भागे और पड़ोस के एक मकान में छिप गए. बाद में मंत्री विजय शाह ने पत्रकारवार्ता में कहा कि वे भ्रष्टाचार के मामले की जांच करेंगे और सरकारी अमले पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी. इधर मारपीट करने के आरोपी अनुसूचित जाति, जनजाति कर्मचारी संघ के नेता कमलकिशोर कोड़े ने मंत्री विजय शाह, विधायक रमेश खटीक, विधायक माखनलाल राठौर, पूर्व विधायक ओमप्रकाश खटीक एवं शासकीय अमले पर आरोप लगाया है कि ये सभी बिना सूचना के उनके घर में घुसे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की. श्री कोड़े का आरोप है कि डागौर ने उनके घर में लूटपाट भी की, जिसके उपरांत महिलाओं व परिजनों ने इनके साथ मारपीट की. हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़ पूरे घटनाक्रम के दौरान मंत्री या विधायक कोड़े के घर में घुसे ही नहीं थे. बिजली संकट, गेहूं ख़रीद में मंडियों में अव्यवस्था को लेकर राज्य भर में जहां-तहां, जब-तब पीड़ित जनता और सरकारी अमले तथा जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद होते रहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

बीस करोड़ की कोयला चोरी पकड़ी गई

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार तो मानो राज्य प्रशासन की पहचान बन गया है. ऐसा लगता है कि हर सरकारी विभाग चोरी और घोटालों में ही पनप रहा है. इस बार बारी है कोयला विभाग की. पिछले कई सालों से कोयला खदानों से ताप बिजली घरों तक कोयले की आपूर्ति करने के काम में लगी परिवहन व्यवसाय से जुड़ी एक निजी कंपनी समूह ने मात्र चार माह में लगभग बीस करोड़ से अधिक का कोयला चोरी कर बेच दिया. मामले के प्रकाश में आने पर सीबीआई ने अपनी जांच में इस घोटाले का पर्दाफ़ाश किया. इस घोटाले को खुलने में छह साल का समय लग गया.

छत्तीसगढ़ में मेसर्स आयरन कोल बेनीफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे आयरन कंपनी के नाम से जाना जाता है, विगत 15 वर्षों से कोयले के परिवहन के कार्यों में संलग्न थी. इस कंपनी ने कोयला खदानों से ताप विद्युत घरों तक परिवहन के दौरान करोड़ों रुपए का उच्च श्रेणी का कोयला चोरी कर बाज़ार में बेचा है. यह तथ्य सीबीआई द्वारा की गई जांच से सामने आया है. और यह तो केवल शुरुआती आंकडे हैं. 15 वर्षों के दौरान इस कंपनी द्वारा किए गए वास्तविक घोटाले पर से पर्दा उठना अभी शेष है. 9 सितम्बर 2009 को कोरबा स्थित दो ढुलाई केंद्रों, तापीय विद्युतगृहों, कंपनी के निदेशकों के आवासों, बिलासपुर के फील्ड कार्यालय और गुड़गांव हरियाणा में कॉरपोरेट कार्यालयों पर एक साथ छापा मारा गया. सीबीआई ने महाप्रबंधक और भारत सरकार के साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि. के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जीसी मृग के अलावा कंपनी के निदेशकों रूद्रसेन और वीरसेन सिन्धु सहित राजस्थान राज्य विद्युत निगम से संबद्ध ट्रान्सपोर्ट कंपनियों के ख़िलाफ़ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज़ की है.

प्राथमिकी में कहा गया है कि राजस्थान के कोटा और सूरतगढ़ विद्युत गृहों के लिए वर्ष 2006 में अप्रैल से जुलाई तक सीईसीएल से आयर्न कंपनी ने कोयला उठाया था, पर सीईसीएल और पूर्व सैनिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों से मिलीभगत कर 73488.64 मीट्रिक टन कोयला वहां नहीं भेजा गया. छापे में इससे संबंधित काग़ज़ात जब्त कर लिए गए हैं.

मामले के प्रकाश में आने के बाद प्रधानमंत्री ने इस प्रकरण की जांच के लिए राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन की अध्यक्षता में 6 सांसदों की समिति भी गठित की थी. समिति के मतानुसार कंपनी द्वारा 20 हज़ार टन कोयला प्रतिदिन बग़ैर हिसाब के निकाल लिया जाता था, जिसकी क़ीमत दो करोड़ रुपये प्रतिदिन होती. आयर्न कोल कंपनी द्वारा खाली दीपिका गेवरा खदान में से 1.25 लाख से 1.50 लाख टन कोयले का लोडिंग परिवहन कार्य किया जाता था. समिति की जांच के अनुसार अच्छी क्वालिटी का ए-ग्रेड कोयला वासरी में लाया जाता था. कोयले की धुलाई के समय ही अच्छे ग्रेड का कोयला ताप विद्युत गृहों को न भेजकर निम्न श्रेणी का कोयला और कोयले की राख सप्लाई की जाती थी. कंपनी खदान से ही 31 प्रतिशत राख वाला कोयला सीधे ऊर्जा संयंत्रों को भेज देती थी. समिति के अनुसार दोनों श्रेणी के कोयले की कीमतों में करीब 800 रुपये प्रति टन का अंतर था. अभी तक यह कंपनी क़रीब सिर्फ़ गुणवत्ता के आधार पर चार करोड़ टन कोयला उठाकर 3200 करोड़ रुपये की कोयले की हेराफेरी कर चुकी है.

समिति के अनुसार इस कार्य में आयर्न कंपनी के ट्रक ही उपयोग किए जाते थे. मेसर्स आयर्न को 1998-99 में 12 एकड़ भूमि कोयला ढुलाई केंद्र स्थापित करने के लिए दी गई थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 14 जुलाई 2003 को हिण्डाल्को को बेचे गए चार लाख टन कोयले की जांच का आग्रह सीबीआई से किया था. छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव राघवन ने 31 जुलाई 2003 को कोयला मंत्रालय के सचिव से जांच की मांग की थी. इस घोटाले पर से पर्दा उठाने की मांग सांसदों, पूर्व सांसदों द्वारा भी की गई थी. सीबीआई ने वर्ष 2004 में भोपाल परिक्षेत्र के डीआईजी सुधीर मिश्रा के नेतृत्व में जांच के बाद आयर्न कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी. इसके बाद कोल इंडिया ने 5 नवम्बर 2004 को अपनी जांच के बाद ट्रान्सपोर्ट कंपनी की हेराफेरी और सीबीआई की जांच पर उंगली उठाई थी.

वर्ष 2005 में गुजरात विद्युत बोर्ड ने भी एक कमेटी बनाकर जांच कराई, जिसके अनुसार रिजेक्ट के नाम पर अच्छे कोयले की लगातार बिक्री का मामला सामने आया. आयर्न कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा काटा और पर्ची धारकों पर की जा रही हेराफेरी का प्रकरण जानकारी में आने के बाद कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया गया.

साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि.

कोरबा और गेवरा के बीच सर्वमंगला पुल पर 17 जुलाई 2003 को कोयले की मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें क्षमता से डेढ़ गुना अधिक कोयला पाया गया. सीबीआई ने 8 जुलाई 2005 को दूसरी रिपोर्ट में कोल इंडिया लिमिटेड को इस कोयला चोरी को रोकने हेतु सतर्कता बरतने की सलाह दी. कोल इंडिया ने पुन: सीबीआई से मामले की जांच का आग्रह किया तो तत्कालीन उपनिदेशक अश्विनी कुमार ने शिकायतों को निराधार बताकर पल्ला झाड़ लिया. उन्होंने कहा कि सीबीआई को आयर्न कंपनी समूह के निज़ी खातों की जांच का अधिकार नहीं है.

एम पी दीक्षित, सीएमडी, एसईसीएल

आयरन कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लि. समूह में ही पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को काम के अवसर देने के नाम पर कंपनियों का एक समूह खड़ा किया गया था. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में घपलों-घोटालों की कोई कमी नहीं है. लातूर भूकंप, उड़ीसा चक्रवात, कारगिल युद्ध, आन्ध्र प्रदेश चक्रवात और गुजरात भूकंप पीड़ितों तथा कोसी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों का एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान कर ख़ूब वाहवाही लूटी, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए केवल एक करोड़ नौ लाख रुपये की राशि ही भेजी गई, जबकि हक़ीक़त यह है कि कोयला कामगारों के एक दिन की वेतन कटौती कर कुल आठ करोड़ 32 लाख रुपये की धनराशि जमा की गई थी. अब सवाल उठता है कि लगभग सात करोड़ रुपयों से ज़्यादा की धनराशि कहां ग़ायब हो गई, इस बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहा है.

भ्रष्टाचार और गबन की हद तो तब हो गई, जब एसईसीएल के अधिकारियों और जेसीसी एवं जेबीसीसीआई के सदस्यों द्वारा आपसी मिलीभगत से 37 लाख 80 हज़ार 733 रुपये को गोपनीय रूप से किसी अनाम बैंक में अवैध रूप से जमा कराया गया. जब इसकी जानकारी मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त रकम वर्तमान में ब्याज सहित बढ़कर 59 लाख से अधिक हो गई है, जिसे प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया गया है, लेकिन इसकी कोई रसीद या प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं है. अभी भी यह प्रश्न अनुत्तरित है कि वर्ष 1999 में कारगिल के शहीदों के नाम पर एकत्र की गई 2 करोड़ 46 लाख 81 हज़ार रुपये की राशि को अवैध रूप से ब्याज आहरित कर, वर्ष 2007 में शहीद जवानों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में केवल एक करोड़ नौ लाख ही क्यों भेजा गया. कोयला खदानों से ताप विद्युत घरों के मध्य परिवहन के दौरान कोयला तस्करी में एक बड़ा समूह संगठित रूप से काम कर रहा है, जिसमें कोल कंपनी के अधिकारियों के अतिरिक्त निजी कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं. इन संलग्न कर्मचारियों का रसूख इतना अधिक है कि ये सीबीआई की जांच तक को बार-बार अपने पक्ष में प्रभावित करने का माद्दा रखते हैं. केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्री पी चिदंबरम के स्पष्ट निर्देशों के बाद की गई कार्यवाही से अब उम्मीद बनी है कि कोल माइंस और ताप विद्युत गृहों के मध्य चल रहे इस 20 साल पुराने तस्करी के सिलसिले को कहीं लगाम लगाई जा सकती हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पीड़ितों के नाम पर एकत्र राशि में करोड़ों का घोटाला

लातूर भूकंप मे एसईसीएल के पास कुल जमा राशि रु. 70,00,125,07 थी जिसमें हसदेव क्षेत्र का अंशदान रु. 16.73.104.54 था. इस राशि को एसईसीएल प्रबंधन द्वारा डब्ल्यूसीएल को एक फरवरी और 30 मार्च 1994 को रु. 41.87.125.07 और रु. 28.13.000.00 क्रमश: प्रधानमंत्री राहतकोष के लिए प्रेषित किया गया. वहीं उड़ीसा चक्रवात के लिए एक करोड़ 87 लाख से अधिक रु. एसईसीएल द्वारा कोल इंडिया को तीन अलग-अलग किस्तों में प्रेषित किया गया. इसमें हसदेव क्षेत्र का अंशदान 34 लाख 16 हज़ार रु. था. कारगिल युद्ध में शहीदों के परिवार वालों के लिए प्रधानमंत्री राहतकोष मे कुल दो करोड़ 46 लाख से अधिक की धनराशि एसईसीएल द्वारा कोल इंडिया को भेजी गई, जिसमें 42 लाख 77 हज़ार 987 रु. का अंशदान हसदेव क्षेत्र द्वारा भेजा गया. वहीं आंध्रप्रदेश चक्रवात और जबलपुर भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए एक करोड़ तीन लाख 10 हज़ार रु. की धनराशि इकट्ठा की गई, जिसमें हसदेव क्षेत्र का सहयोग लगभग 21 लाख रु. था. गुजरात के भूकंप पीड़ितों के लिए दो करोड़ 23 लाख 91 हज़ार की धनराशि इकट्ठा की गई जिसमें हसदेव क्षेत्र ने 42 लाख 83 हज़ार 951 रु. उपलब्ध कराए.

इन सभी धनराशियों को एसईसीएल और कोलइंडिया द्वारा प्रधानमंत्री राहतकोष में जमा करवाया जाना चाहिए था, लेकिन विडंबना यह है कि कोयला कामगारों के वेतन से प्राप्त अंशदान की राशि को कोलइंडिया व एसईसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत से मात्र एक करोड़ नौ लाख छह हज़ार 13 रु. ही अब तक प्रधानमंत्री राहतकोष मे जमा करवाया गया है, जो कि चेक क्र. 9440 द्वारा 50.00.000.00 रु. ड्राफ्ट नं. 171511 द्वारा 43,01,921,00 रु. तथा 171512 द्वारा 16,04,092,00, रु. जमा कराए गए. इसका कुल योग 1,09,06,013,00 रु. होते हैं, जिसका भुगतान स्टेट बैंक के दो ड्राफ्ट व यूटीआई बैंक के चेक द्वारा 10 सितंबर 2007 को प्रधानमंत्री राहतकोष मे जमा करवाया गया. इसका प्रमाण पत्र एसईसीएल को 16 सितंबर 2007 को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजा गया था.

एक करोड़ नौ लाख की धनराशि के अतिरिक्त एसईसीएल बिलासपुर या हसदेव क्षेत्र के पास बाकी रकम का कोई लेखा जोखा नहीं है. वहीं कोसी बाढ़ पीड़ितों के लिए एकत्र की गई सहायता राशि का हिसाब प्रबंधन के अधिकारियों के पास नहीं है, सूचना के अधिकार के तहत जब इसकी जानकारी मांगी गई तो लोक सूचना अधिकारी ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि संबंधित विभाग से जानकारी मांगी गई है. जब यह जानकारी उपलब्ध होगी तो इसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 19 अप्रैल–25 अप्रैल 2010

विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का एकमात्र पार्क है, जहां टाइगर और बारहासिंगहा दोनों ही पाये जाते हैं. वर्ष 1955 में यह पार्क नेशनल पार्क घोषित हुआ था.

जंगल के राजा पर संकट

असगर कुरैशी

विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में शेरों की संख्या घटकर केवल 89 बची है. वर्ष 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद से बढ़ने वाली यह संख्या अब तक के सबसे कम संख्यांक तक पहुंच रही है. कान्हा प्रबंधन भी शेरों की गणना से मीडिया को दूर रखना चाहता है. इससे यह संकेत मिलता है कि, मध्य प्रदेश जैसा विशाल राज्य अपने टाइगर रिजर्व को संरक्षित रख पाने में कहीं-न-कहीं असफल रहा है. विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का एकमात्र पार्क है, जहां टाइगर और बारहासिंगहा दोनों ही पाए जाते हैं. वर्ष 1955 में यह पार्क नेशनल पार्क घोषित हुआ था. उस समय शेरों की संख्या को देखते हुए वर्ष 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था. उस दौरान शेरों की संख्या 40 से 45 के बीच थी. धीरे-धीरे यह संख्या बढ़कर वर्ष 1980 में 70, वर्ष 1990 में 90, वर्ष 2001 में 105, और वर्ष 2005 में 129 हो गई. अचानक शेरों की बढ़ती हुई इस आबादी पर मानो ग्रहण लग गया हो, इनकी संख्या धीरे-धीरे घटने लगी. वर्ष 2008 की गणना के मुताबिक़, कान्हा में केवल 89 शेर ही बचे हैं.

कान्हा नेशनल पार्क में 10 फरवरी को शेरों की गिनती का कार्य प्रारंभ किया गया जो 16 फरवरी को पूरा भी हो गया. कान्हा प्रबंधन ने शुरुआती दिनों में इस गिनती से मीडिया को पूरी तरह दूर रखा. वर्ष 2001-02 में जहां पूरे देश में 3642 बाघ थे वहीं अब इनकी संख्या घटकर 1411 पर पहुंच चुकी है. शेरों की इस गिनती में सहयोगी एजेंसियों के रूप में वर्ल्ड वाईल्ड फन्ड और फॉर्म नेचर ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियां सहयोगी रहती हैं. इन एजेंसियों के अनुसार 600 करोड़ रुपयों की राशि इन टाइगर की सुरक्षा के लिए ख़र्च की जाती है. अनुमान के अनुसार प्रति टाइगर पर दस लाख रुपये प्रतिवर्ष ख़र्च किया जाता है. इसके बावजूद बाघों की संख्या घट रही है.

मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क में 89, बांधवगढ़ में 47, पन्ना टाइगर रिसर्व में 24, पेंच पार्क में 35 और सतपुड़ा में 39 टाइगर पाये गये. इनकी मौत के आंकड़ों पर यदि ग़ौर किया जाए तो केवल 2009 में ही सात बाघों की मौत हो हुई. इनमें से 3 जनवरी 2009 को 2, 7 जनवरी 2009 को 1, 18 जनवरी को 1, 29 जनवरी को एक और बाघ की मौत हुई. कान्हा नेशनल पार्क के डायरेक्टर हिम्मत सिंह मेगी के अनुसार कान्हा में शेरों की सुरक्षा का प्रयास जारी है. मेगी के अनुसार ज़्यादातर टाइगर की मौत आपस में लड़ने के कारण, या उम्र पूरी हो जाने के कारण हुई है. इस बयान के बाद भी मध्य प्रदेश में बाघों का भविष्य ख़तरे में है. अब देखना होगा कि प्रशासन इनकी सुध कब तक लेता है.

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

बाघों के दर्शन लिए मुख्यमंत्री भी तरसे

शिवराज सिंह चौहान को भी राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण और वन्य प्राणी अभयारण्यों की हक़ीक़त का पता चल गया है. अपने अतिव्यस्त राजनैतिक जीवन में ताज़गी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने सपरिवार 4 अप्रैल 2010 रविवार को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सुरम में प्राकृतिक पर्यटन केन्द्र मढ़ई (ज़िला होशंगाबाद) में 24 घंटे की छुट्टी मनाई. शिवराज सिंह ने देनवा नदी में अपने परिवार के साथ नौकाविहार का आनन्द लिया और दिन में हिरण, चीतल आदि कई वन्य प्राणियों के अवलोकन का सुख प्राप्त किया. रात्रि में मुख्यमंत्री शेर देखने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन राजनीति के इस सिंह को जंगल के शेर ने दर्शन नहीं दिए. सच तो यह है कि, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वर्षों से शेर नहीं है, लेकिन वन विभाग शेरों की संख्या मनगढ़ंत बताकर इस वन क्षेत्र के लिए सरकारी धन प्राप्त कर लेते है. 24 घंटे के अवकाश से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ पत्रकारों के पूछे जाने पर कहा कि उन्हें मढ़ई में शेर दिखाई नहीं दिया. फिर अपने विभाग की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए चुटकी ली और कहा, मेरे सामने शेर नहीं आते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

जलमनी योजना खटाई में

शिवा कुमार

केंद्र सरकार के एक निर्देश पर राज्य के 900 स्कूलों के बच्चों की सेहत के लिए राज्य सरकार अचानक गंभीर हो गई है. इन छात्रों को स्वच्छ जल पिलाने के लिए सरकार ने वाटर फिल्टर लगाने की अनुशंसा को मान लिया है. इस संदर्भ में निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं.

केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 900 बच्चों की सेहत के लिए वाटर फिल्टर लगाने की योजना बनाई है. केंद्र ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता जताते हुए राज्यों को निर्देश दिया था कि शालाओं में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करें. जलमनी योजना के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में वाटर फिल्टर लगाने की अनुशंसा कर दी, ताकि स्कूलों में ही बच्चों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सके. यह अलग बात है कि नगर निगम और नगर पालिका जैसी संस्थाएं आम जनता को उनके घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रही है.

परंतु, सरकार की चिंता 900 स्कूलों के बच्चों को स्वच्छ पेयजल स्कूल अवधि में पिलाने की है. इसलिए दिनांक 25 सितम्बर 2009 को इस संदर्भ में निविदा बुलाई गई. चूंकि ठेकेदारों ने नियमानुसार अनुभव पत्र जमा नहीं किया था, इसीलिए अधीक्षण यंत्री मदनलाल अग्रवाल के अनुसार इसे निरस्त कर दिया गया. प्रस्तावित नियमों के अनुसार, वही ठेकेदार इस निविदा के लिए योग्य थे, जिन्हें वाटर फिल्टर के पचास नग का सप्लाई करने का अनुभव हो. श्री अग्रवाल के अनुसार वाटर फिल्टर बनाने व वितरित करने वाली 47 प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची तय की गई है. इन्हीं कंपनियों में से कोई कंपनी स्कूल में इन वाटर फिल्टरों की सप्लाई करेगा. चुनी गई कंपनी को पांच वर्ष तक वाटर फिल्टर का रखरखाव भी करना होगा.

उपरोक्त टेंडर में जानकार घोटाला ढूंढ़ रहे हैं. उनके अनुसार पहली बार जब निविदा बुलाई गई थी तो एक वाटर फिल्टर के लिए 20 हज़ार रुपये स्वीकृत किए गए थे, जबकि बाद में इस रकम को 40 हज़ार तक कर दिया गया. वाटर फिल्टर के रख-रखाव को निविदा का एक प्रमुख पहलू माना गया है, जबकि एक वाटर फिल्टर के रखरखाव में मात्र 300 रुपये तक का ख़र्च आता है. भारतीय टेलीविजन की एक मशहूर अभिनेत्री एवं भाजपा नेता स्मृति इरानी ने जलमनी योजना पर ख़ास रुचि लेते हुए इसमें गहरी रुचि दिखाई थी. उनकी इस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा भी हुई थी. ग़ौरतलब है कि स्मृति इरानी एक वाटर फिल्टर बनाने वाली कंपनी की ब्रान्ड एंबेसडर भी हैं. विभाग 20 हज़ार रुपये का वाटर फिल्टर, 40 हज़ार रुपये की दर से ख़रीदने जा रहा है. इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है. होने वाली निविदा में केवल 47 कंपनियां ही भाग ले सकती हैं. इन काग़ज़ी नियमों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार का एक नया प्रकरण तैयार किया जा रहा है. जिसकी बुनियाद स्कूली बच्चों के संरक्षण और स्वास्थ्य के नाम पर रखी जा रही है.

feedback@chauthiduniya.com

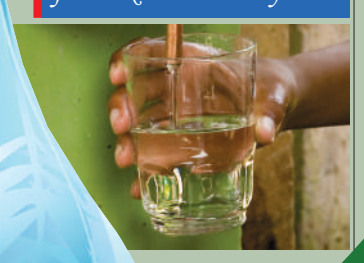

देश की केंद्रस्थली करौंदी उपेक्षा की शिकार

अरविन्द वर्मा

मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव करौंदी, देश की भौगोलिक सीमाओं के केंद्र बिन्दु में स्थापित है. यह गांव डॉ. राममनोहर लोहिया, आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के विचारों और आन्दोलनों का मुख्य प्रेरणास्त्रोत बना रहा है. पर, यह आज भी उपेक्षित है. इतिहास बताता है कि इस गांव ने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए कई वर्षों तक का संघर्ष प्रत्यक्ष देखा है.

आज़ादी मिलने के बाद भी डॉ. राममनोहर लोहिया ने अपने संघर्ष को जो ऊंचाई दी, उसका उल्लेख इतिहास में अंकित है, परंतु उसमें करौंदी गांव की भूमिका कहीं नहीं मिलती. मध्य प्रदेश का यह छोटा सा गांव जिसमें इतिहासकारों ने समुद्र की ऊंचाई अक्षांश और देशांश के आधार पर एक गोंड आदिवासी परिवार की पुश्तैनी भूमि पर वह बिन्दु खोजा था, आपको बता दें कि इसे भारत का केंद्र बिन्दु प्रमाणित किया गया था. हालांकि, डॉ. लोहिया स्वयं तो इस बिन्दु तक नहीं पहुंच सके थे, परंतु जानकारों के मुताबिक़ जबलपुर के समीप सिहोरा कस्बे में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समता विश्वविद्यालय की स्थापना इसी केंद्र बिन्दु पर किए जाने के सपने का उल्लेख किया था.

डॉ. लोहिया के अलावा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी ने अपने स्तर पर करौंदी में भारत के भौगोलिक केंद्र को मान्यता प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेद विज्ञान महाविद्यालय और विश्व की सबसे ऊंची इमारत बनाने का प्रयास प्रारंभ किया था. महर्षि अपने जीवनकाल में करौंदी गांव से जुड़े रहे. महर्षि का यह सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, परंतु करौंदी गांव आज भी भारत के केंद्र बिन्दु के रूप में वैज्ञानिक तौर पर स्थापित है.

पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने भी करौंदी के इतिहास को जानते हुए इस क्षेत्र में अपनी विशेष रुचि दिखाई थी, उन्होंने करौंदी की कई यात्राओं के दौरान इस गांव का नाम डॉ. राममनोहर लोहिया के नाम पर रखने की सिफ़ारिश की थी. यहां आचार्य नरेंद्र देव जन्म शताब्दी के समारोह के आयोजन के तहत देशभर के समाजवादी और लोहिया अनुयायी एकत्र हो चुके हैं. श्री चंद्रशेखर की पदयात्रा के दौरान तत्कालीन खाद्य एवं प्रस्करण मंत्री सुबोधकांत सहाय अपने साथियों के साथ रांची से पैदल चलते हुए करौंदी आए थे. इसके अलावा जेएनयू दिल्ली के डॉ. आनंद कुमार श्यामरजक, कैप्टन विक्रम सिंह, सुधींद्र भदौरिया आदि महत्वपूर्ण व्यक्ति पदयात्रा या साईकिल यात्रा करते हुए चंद्रशेखरजी के बुलावे पर करौंदी पहुंचे थे. चंद्रशेखर गांव करौंदी ने अपने भारत यात्रा केंद्र का एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते थे जो उनके भोड़सी में स्थित केन्द्र से गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और आचार्य नरेंद्र देव जैसे महामानव के सपनों का प्रतिबिंब हो. यह प्रयास चंद्रशेखरजी ने अपने अल्पकालीक प्रधानमंत्री काल में भी जारी रखा. इस दौरान उन्होंने करौंदी की दो यात्राएं की थीं. सारी कोशिशों के बावजूद भारत यात्रा केंद्र की स्थापना इस क्षेत्र में नहीं हो सकी. इस बारे में निधन के कुछ समय पूर्व उन्होंने जनसंगठन एकता परिषद के श्री पीव्ही राजगोपाल से इस सपने के बारे में विस्तार से चर्चा की थी.

1. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी.
2. डॉ. राम मनोहर लोहिया.

करौंदी के संदर्भ में कई बार की गई कोशिशों और भारतीय राजनीति के पुरोधाओं की समस्त इच्छाओं के बावजूद विकास ठहरा रहा. मध्य प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने करौंदी गांव को विशेष पहचान देने के लिए कुछ नहीं किया. यहां तक की राज्य सरकारों ने इस अंतस्थलीय भूभाग और भौगोलिक केंद्र बिन्दु को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया. कटनी ज़िले के इस गांव में आदिवासी बहुल ढीमरखेड़ विकास खण्ड के गिने-चुने गौड़ आदिवासी परिवार आज भी इस वास्तविकता से अनजान हैं कि भारत का भौगोलिक केंद्र उनके ही उपयोग में आ रही ज़मीन के मध्य कहीं स्थित है.

जंगली बसाहट के आसपास लौह अयस्क, बाक्साइड, डोलोमाइट, लेटराइट, लाईम स्टोन और संगमरमर के अलावा अन्य कई बहुमूल्य खनिज यहां बिखरे हुए हैं. जंगलों में जैव विविधता से भरपूर वनस्पति और वन्य प्राणियों की भरमार इस क्षेत्र में है. इसके बावजूद आधुनिक विकास प्रक्रिया में संसाधनों का दोहन करौंदी गांव की नियत बन चुका है. यहां के बहुसंख्य निवासी ग़रीबी, भूखमरी, कुपोषण, अशिक्षा और असमानता से ग्रसित हैं.

इसके बावजूद करौंदी आज भी भारत के मध्य केंद्र बिन्दु के रूप में स्थापित है, जिसे बनाने की कई बार कोशिश की गई, परंतु समय ने करौंदी के अस्तित्व को हमेशा एक मुकाम तक लाकर संकट में ला दिया. मध्य प्रदेश शासन से निरंतर उपेक्षा का शिकार करौंदी अभी भी अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है.

feedback@chauthiduniya.com